सोशल मीडिया से जुड़ें
Parivehan_Vishesh
YouTube

RNI No :- DELHIN/2023/86499
DCP Licensing Number : F.2 (P-2) Press/2023

www.newsparivahan.com

परिवहन विशेष

वर्ष 02, अंक 252, नई दिल्ली । शुक्रवार, 22 नवम्बर 2024, मूल्य ₹ 5, पेज 8

देश का पहला ट्रांसपोर्ट दैनिक समाचार पत्र

आज का सुविचार

अगर भाग्य पर भरोसा है तो जो तकदीर में लिखा है वही पाओगे, और अगर खुद पर भरोसा है तो जो चाहोगे वही पाओगे।

03 एक पिस्तौल और एक चाकू के साथ तीन लुटेरे गिरफ्तार
06 जेईई मेन के लिए ड्रॉप ईयर लेना जोखिम भरा हो सकता है
08 कानपुर में ईवीएम स्थल का कैमरा बंद होने से फिर भड़के सपाई, अखिलेश को बताया

रोड सेफ्टीः सरकार वाहनों की रफ्तार पर नियंत्रण रखने के लिए बना रही है नए नियम...

सड़क सुरक्षा को मजबूत करने और यातायात प्रवर्तन में सुधार लाने के लिए, भारत सरकार वाहनों की रफ्तार मापने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले रडार उपकरणों के लिए नियम लागू करेगी। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के लीगल मेट्रोलॉजी (कानूनी माप विज्ञान) प्रभाग द्वारा तैयार किए गए मसौदा नियमों के अनुसार, सभी रडार उपकरणों को तैनाती से पहले वेरिफिकेशन (सत्यापन) से गुजरना होगा और आधिकारिक मुहर हासिल करनी होगी।

संजय बाटला

नई दिल्ली। सड़क सुरक्षा को मजबूत करने और यातायात प्रवर्तन में सुधार लाने के लिए, भारत सरकार वाहनों की रफ्तार मापने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले रडार उपकरणों के लिए नियम लागू करेगी। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के लीगल मेट्रोलॉजी (कानूनी माप विज्ञान) प्रभाग द्वारा तैयार किए गए मसौदा नियमों के अनुसार, सभी रडार उपकरणों को तैनाती से पहले वेरिफिकेशन (सत्यापन) से गुजरना होगा और आधिकारिक मुहर हासिल करनी होगी।

ये नियम कानूनी माप विज्ञान (सामान्य) नियम, 2011 के अंतर्गत आते हैं, और विशेष रूप से माइक्रोवेव डॉपलर रडार उपकरण पर लागू होंगे। जिसका व्यापक रूप से ट्रैफिक स्पीड निगरानी में इस्तेमाल किया जाता है। इसका मकसद स्पीड का पता लगाने में सटीकता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करना है। जो सड़क दुर्घटनाओं को कम करने और ट्रैफिक कानूनों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए महत्वपूर्ण है।

इन विनियमों के लिए रूपरेखा भारतीय विधिक मापविज्ञान संस्थान (इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी) (IILM), क्षेत्रीय संदर्भ प्रयोगशालाओं (रिजनल रेफरेंस लेबोरेटरी) (RRSLs), निर्माताओं और वाहन प्रमाणन संगठनों सहित प्रमुख हितधारकों के साथ परामर्श के बाद विकसित की गई थी। नियमों का एक मसौदा सार्वजनिक परामर्श के लिए प्रकाशित किया गया था, और मिले इनपुट की सावधानीपूर्वक जांच की गई थी।

मंत्रालय ने एक बयान में कहा, ₹विभिन्न परामर्शों के दौरान मिले सुझावों की सावधानीपूर्वक जांच की जाती है, और नियमों को जल्द ही अधिसूचित किया जाएगा।₹ ये नियम अंतर्राष्ट्रीय कानूनी माप विज्ञान संगठन (OIML) द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप हैं। जो वैश्विक अनुपालन और सबसे अच्छी आदतों को शामिल करते हैं।

वेरिफाइड रडार इक्यूपमेंट स्पीड और दूरी का सटीक माप सुनिश्चित करेंगे। जिससे सड़क सुरक्षा से समझौता करने वाली त्रुटियों को कम किया जा सकेगा। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने यातायात प्रवर्तन में विश्वसनीय डेटा के महत्व पर रोशनी डालते हुए कहा, "विश्वसनीय रफ्तार माप न सिर्फ स्पीड उल्लंघन की पहचान करने में मदद करेगा, बल्कि असुरक्षित ड्राइविंग व्यवहार को रोकने में भी मदद करेगा। जिससे दुर्घटनाओं और सड़क बुनियादी ढांचे पर होने वाले नुकसान में कमी आएगी।"

यहां बताया गया है कि नए नियमों में क्या-क्या शामिल है, उनकी आवश्यकता क्यों है। और उनका मकसद सड़क सुरक्षा में किस तरह सुधार करना है।

नए रडार नियम क्या हैं?

कानूनी माप विज्ञान (सामान्य) नियम, 2011 के तहत विकसित नए नियमों में वाहनों की स्पीड मापने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले रडार उपकरणों का अनिवार्य सत्यापन और स्टैम्पिंग की आवश्यकता होगी। ये नियम विशेष रूप से माइक्रोवेव डॉपलर रडार उपकरणों को लक्षित करते हैं, जिन्हें यातायात प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा व्यापक रूप से तैनात किया जाता है।

उपयोग में लाने से पहले, हर एक रडार उपकरण को गति और दूरी मापने में सटीकता सुनिश्चित करने के लिए सत्यापन से गुजरना होगा।

सत्यापित उपकरणों को उद्योग और अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुपालन को प्रमाणित करने वाली एक आधिकारिक मुहर मिलेगी।

ये नियम क्यों लागू किए जा रहे हैं?

भारत में सड़क दुर्घटनाओं में चिंताजनक बढ़ोतरी देखी गई है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अनुसार, 2022 में देश में 461,312 सड़क दुर्घटनाएं दर्ज की गईं, जिनमें 168,491 मौतें और 443,366 घायल हुए। ये आंकड़े 2021 की तुलना में दुर्घटनाओं में 11.9 प्रतिशत, मृत्यु दर में 9.4 प्रतिशत और चोटों में 15.3 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्शाते हैं।

गलत स्पीड माप उपकरण प्रवर्तन और सड़क सुरक्षा को खतरे में डाल सकते हैं। वे स्पीड उल्लंघनों की पहचान करने में नाकाम हो सकते हैं, जिससे असुरक्षित ड्राइविंग प्रथाओं को जारी रहने दिया जा सकता है। जैसा कि उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने कहा है, "गलत स्पीड माप गति उल्लंघनों का पता लगाने में असफल होने से सड़क सुरक्षा को कमजोर कर सकते हैं, जिससे सड़क उपयोगकर्ताओं के लिए जोखिम बढ़ जाता है।"

नियम कैसे विकसित किए गए?

उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के कानूनी माप विज्ञान प्रभाग ने कई हितधारकों के परामर्श से नियम विकसित किएः

भारतीय कानूनी माप विज्ञान संस्थान (IILM)

क्षेत्रीय संदर्भ प्रयोगशालाएं (RRSL)

रडार उपकरण निर्माता

वाहन प्रमाणन संगठन

नियमों का मसौदा सार्वजनिक परामर्श के लिए प्रकाशित किया गया था। मंत्रालय ने सभी सुझावों की समीक्षा की और प्रासंगिक फीडबैक को शामिल किया। नियमों को जल्द ही आधिकारिक रूप से अधिसूचित किया जाएगा।

मंत्रालय ने एक बयान में कहा, ₹विभिन्न परामर्शों के दौरान मिले सुझावों की सावधानीपूर्वक जांच की जा रही है। और नियमों को जल्द ही अधिसूचित किया जाएगा।"

ये नियम सड़क सुरक्षा को कैसे बेहतर बनाएंगे?

नए नियमों के मुख्य लाभों में शामिल हैंः

सटीक स्पीड का पता लगाना

सत्यापित रडार उपकरण सटीक गति और दूरी माप प्रदान करेंगे, जो गति उल्लंघन की पहचान करने के लिए महत्वपूर्ण है।

यातायात कानून प्रवर्तन बढ़ेगा

विश्वसनीय डेटा के साथ, यातायात अधिकारी गति सीमा को ज्यादा प्रभावी ढंग से लागू कर सकते हैं। जिससे गति से संबंधित दुर्घटनाओं की घटनाओं में कमी आएगी।

अंतर्राष्ट्रीय मानकों का अनुपालन

नियम अंतर्राष्ट्रीय कानूनी माप विज्ञान संगठन (OIML) के दिशा-निर्देशों के अनुरूप हैं, जो सड़क सुरक्षा प्रवर्तन में वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं को सुनिश्चित करते हैं।

सार्वजनिक विश्वास का निर्माण

प्रमाणित रडार उपकरण खराबी या त्रुटियों के जोखिम को कम करते हैं, जिससे प्रवर्तन में निष्पक्षता सुनिश्चित होती है।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक जानकारों का कहना है कि, ₹रडार उपकरणों को विनियमित करने का कदम समय पर और सोच-समझकर उठाया गया है। सत्यापित रडार उपकरण यातायात कानून प्रवर्तन की दक्षता को भी बढ़ाएगा।"

आगे क्या होगा?

एक बार नियम अधिसूचित हो जाने के बाद, सभी रडार उपकरणों को इन सत्यापन और स्टैम्पिंग आवश्यकताओं का अनुपालन करना होगा। इस कदम से ट्रैफिक गति निगरानी के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरणों को मानकीकृत करने, प्रवर्तन सटीकता में सुधार करने और आखिरकार सभी के लिए सुरक्षित सड़कें बनाने की उम्मीद है।

प्रवर्तन अशुद्धियों के मूल कारण को संबोधित करके, सरकार का लक्ष्य भारतीय सड़कों को सुरक्षित बनाना और सड़क दुर्घटनाओं की खतरनाक दर को कम करना है।

लुटियंस दिल्ली में बनेगी स्टैक पार्किंग, खड़े हो सकेंगे दो हजार वाहन

परिवहन विशेष न्यूज

लुटियंस दिल्ली में पार्किंग सुविधा का विस्तार होने जा रहा है। करीब 2000 अतिरिक्त वाहनों की पार्किंग क्षमता के साथ नई बहुमंजिला पार्किंग और स्टैक पार्किंग मॉडल लागू किया जाएगा। गोल मार्केट खान मार्केट और केजी मार्ग पर बहुमंजिला पार्किंग समेत कुल 25 नए पार्किंग स्थल उपलब्ध होंगे। एनडीएमसी टावर और स्टैक जैसी पार्किंग तकनीक का भी उपयोग करेगा। वर्तमान में 150 पार्किंग स्थलों को बढ़ाकर 175 किया जाएगा।

नई दिल्ली। लुटियंस दिल्ली में पार्किंग सुविधा का विस्तार होगा। करीब दो हजार वाहनों की क्षमता की अतिरिक्त पार्किंग की व्यवस्था की जाएगी। इसके लिए न केवल नई बहुमंजिला पार्किंग का निर्माण किया जाएगा बल्कि स्टैक पार्किंग माडल को भी लागू किया जाएगा।

टावर और स्टैक जैसी पार्किंग तकनीक पर होगा काम

इसमें गोल मार्केट, खान मार्केट, केजी मार्ग पर बहुमंजिला पार्किंग समेत कुल 25 पार्किंग के नए स्थल उपलब्ध होंगे। एनडीएमसी ने कम स्थान पर ज्यादा वाहनों के लिए पार्किंग की सुविधा उपलब्ध कराने वाली टावर और स्टैक जैसी पार्किंग तकनीक का भी उपयोग करने पर भी कार्य करेगा।

150 से बढ़कर 175 होगी पार्किंग साइट की संख्या

एनडीएमसी उपाध्यक्ष कुलजीत चहल ने बताया कि सभी पार्किंग स्थलों को हम फास्टैग तकनीक युक्त आने वाले दिनों में करेंगे। साथ ही मौजूदा पार्किंग साइट की संख्या 150 से बढ़ाकर 175 तक करेंगे। साथ ही डिजीटल ट्राजेक्शन पर पार्किंग की सुविधा का उपयोग करने वालों को अतिरिक्त लाभ दिया जाएगा।

चहल ने बताया कि एनडीएमसी वर्तमान में 150 पार्किंग स्थल हैं। इसमें छह पार्किंग भागीदारी योजना के तहत चलती है। जबकि दो बहुमंजिला पार्किंग है। शेष 142 पार्किंग स्थलों का प्रबंधन सीधे एनडीएमसी कर्मचारियों द्वारा किया जाता है।

इन जगहों पर मिलेगी सुविधा

इन पार्किंग स्थलों पर 9025 कार और 4375 दो पहिया और 123 बसों को खड़ा करने की क्षमता है। पार्किंग संख्या के विस्तार के बाद यह सुविधा 11,000 कारें, 5,000 दोपहिया वाहन और 200 बसें खड़ी करने की हो जाएगी। उन्होंने बताया कि जो नई स्थलीय पार्किंग शुरू होने है उसमें टालस्टाय मार्ग, अतुल ग्रोव रोड, तिलक लेन, सरोजिनी नगर, खान मार्केट, कनॉट प्लेस और राजेश पायलट मार्ग जैसे उच्च मांग वाले क्षेत्र शामिल हैं।

खान मार्केट में होगा स्टैक पार्किंग मॉडल पर काम

एनडीएमसी उपाध्यक्ष ने बताया कि चूंकि गोल मार्केट में संग्रहालय बन रहा है। ऐसे में यहां पर बड़ी संख्या में लोगों के आने की उम्मीद है। इसलिए यहां के साथ ही खान मार्केट और महार्षि रमन मार्ग पर स्टैक पार्किंग मॉडल पर कार्य किया जाएगा।

इसके लिए उपयुक्त भूमि की पहचान करने का कार्य चल रहा है। उन्होंने बताया कि केजी मार्ग पर एक बहुमंजिला पार्किंग का निर्माण राष्ट्रमंडल खेलों से पूर्व से लंबित है। इस पार्किंग के निर्माण पर चल रहा विवाद का मामला सुलझ गया है। इस पर भी जल्द पार्किंग निर्माण शुरू होगा।

सिग्नेचर पुलः चार माह से काम ठप

केंद्र सरकार की रिपोर्ट पर अटका भविष्य

परिवहन विशेष न्यूज

रुद्रप्रयाग। ऋषिकेश-बदरीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर ऑलवेदर रोड परियोजना के तहत नरकोटा में प्रस्तवित सिग्नेचर पुल का काम चार माह से ठप पड़ा है। जुलाई माह में पुल के एक पिलर पर निर्मित अस्थायी ढांचा ध्वस्त हो गया था। अब, केंद्र सरकार के सड़क एवं परिवहन मंत्रालय की टीम की सर्वेक्षण रिपोर्ट पर इस पुल का भविष्य अटका हुआ है। स्वीकृति के बाद से पुल पर विवादों का साया बना हुआ है। पुल निर्माण की सामग्री जगह-जगह रखी गई है, जिससे यातायात भी प्रभावित हो रहा है।

वर्ष 2017-18 में केंद्र सरकार की ऑलवेदर रोड परियोजना के तहत ऋषिकेश-बदरीनाथ राजमार्ग का चौड़ीकरण कार्य शुरू हो गया था। राजमार्ग पर तीखे मोड़ों को खत्म करने के लिए कई जगहों पर पुल प्रस्तावित किए गए थे। इनमें अधिकांश का निर्माण पूरा हो चुका है, पर नरकोटा में 110 मीटर स्पान का 64 करोड़ की लागत से बनने वाला सिग्नेचर पुल कब पूरा होगा, किसी को पता नहीं है।

नरकोटा गदेरे पर पुल के निर्माण के लिए पहले श्रीनगर की तरफ वाले पिलर को लेकर भूमि विवाद आड़े आया। जैसे-तैसे विवाद निपटा तो पिलर की कई बार डिजाइन बदली गई। जून 2022 में काम शुरू हुआ, पर एक माह में ही शटरिंग ढह गई। इस हादसे में दो मजदूरों की मौत हो गई थी और कई घायल हुए। इसके बाद छह माह तक कार्य पूरी तरह से ठप रहा। साथ ही शासन व विभागीय स्तर पर तत्कालीन ईई को निलंबित कर देहरादून अटैच कर दिया गया। जनवरी 2023 में पुनः सॉयल टेस्टिंग और डिजाइन में बदलाव के बाद पिलर निर्माण का कार्य शुरू किया गया। कार्यदायी संस्था आरसीसी द्वारा सितंबर 2024 तक सिग्नेचर पुल को तैयार करने का लक्ष्य रखा गया। तय समय के हिसाब से पुल का कार्य जोरों पर चल रहा था। इस वर्ष मार्च से निर्माण सामग्री मौके पर पहुंचाई जाने लगी थी। यहां लगभग एक किमी क्षेत्र में पुल निर्माण सामग्री रखी गई है, जिससे यातायात भी बाधित हो रहा है। इधर, बीते जून माह में दोनों पिलर पर लोहे के फ्रेम का अस्थायी टॉवर बनाकर पुल जोड़ने का काम शुरू किया गया।

टेंपल्स ऑफ लिबरलाइजेशन एंड वेलफेयर एलाइड ट्रस्ट (पंजीकृत)

TOLWA

website : www.tolwa.in
Email : tolwadelhi@gmail.com
bathlasanjaybathla@gmail.com

रजिस्टर्ड अंडर सैक्शन 60 विद रजिस्ट्रेशन नंबर (152/02-03-2020), एमएसएमई रजिस्ट्रेशन नंबर उद्यम -डीएल -0026470, नीति आयोग रजिस्ट्रेशन नंबर वीओ/एनजीओ/0303274/25-01-2022 दर्पण

रजिस्टर्ड कार्यालय :- 3, प्रियदर्शिनी अपार्टमेंट, ए -4 पश्चिम विहार, न्यू दिल्ली 110063
कॉरपोरेट कार्यालय :- 529, समयपुर, मेंन बवाना रोड, नियर बैंक ऑफ़ बड़ौदा दिल्ली 110042

दिल्ली मेट्रो के एप पर अब मिलेगी खास सुविधा, हजारों लोगों को होगा फायदा

परिवहन विशेष न्यूज

दिल्ली मेट्रो के टिकट बुकिंग एप से अब राजधानी में एएसआई द्वारा प्रबंधित स्मारकों के लिए लोग टिकट बुक कर सकेंगे। एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि बुधवार को दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (डीएमआरसी) ने डीएमआरसी के मोमेंटम 2.0 मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से एएसआई स्मारक टिकटों की बिक्री को सक्षम करने के लिए एएसआई के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किया है।

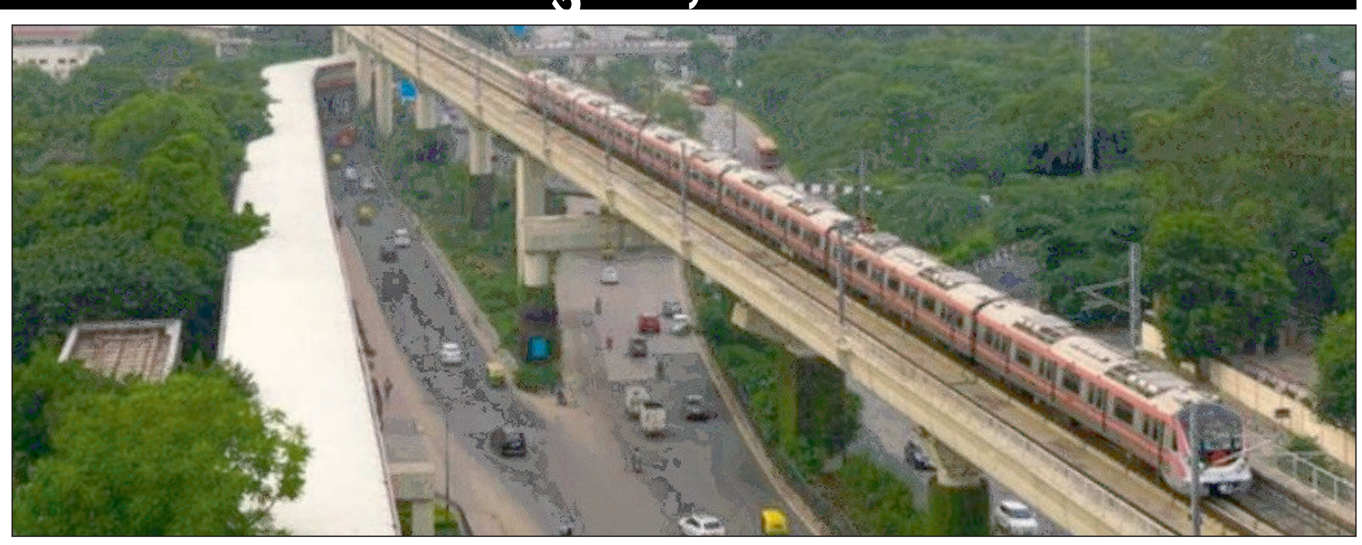

नई दिल्ली। दिल्ली मेट्रो रेल निगम (डीएमआरसी) के मोबाइल एप मोमेंटम 2.0 दिल्ली सारथी पर अब भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) के स्मारकों का टिकट भी उपलब्ध होगा। इसके लिए डीएमआरसी ने एएसआई के साथ समझौता किया है। इससे पर्यटकों को सुविधा होगी।

DMRC और ASI के बीच हुआ समझौता

डीएमआरसी के प्रबंध निदेशक डॉ. विकास कुमार और एएसआई के अतिरिक्त महानिदेशक (प्रशासन) आनंद मधुकर की उपस्थिति में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है। एएसआई के सहयोग से डीएमआरसी एकीकृत क्यूआर-आधारित टिकटिंग प्रणाली विकसित और कार्यान्वित करेगी। इसके माध्यम से दिल्ली मेट्रो सेवा के उपयोग और एएसआई द्वारा संरक्षित स्मारकों में प्रवेश की सुविधा मिलेगी।

स्मारकों को देखने में होगी आसानी

इसका उद्देश्य डिजिटल प्लेटफार्म के माध्यम से दिल्ली की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देने के लिए मिलकर काम करना है। इससे पर्यटकों को दिल्ली में मेट्रो ट्रेन में यात्रा करने और यहां स्थित स्मारकों को देखने में आसानी होगी। नामित मेट्रो स्टेशनों पर एएसआई स्मारकों के बारे में जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। इसके लिए साइनेज लगाए जाएंगे।

आप सरकार के समय दोगुना हुआ मेट्रो का विस्तार- केजरीवाल

इससे पहले, मंगलवार को मुख्यमंत्री आतिशी ने मुकुंदपुर डिपो में मेट्रो फेज-4 के लिए आई ट्रेन का निरीक्षण किया था। आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि आप सरकार के कार्यकाल में पिछले 10 वर्षों में मेट्रो का बड़े स्तर पर विस्तार हुआ है। केजरीवाल ने एक्स पर जारी पोस्ट में कहा था कि दिल्ली में पिछले 10 साल में बहुत से इलाकों को मेट्रो से जोड़ा गया है और चौथे फेज में बहुत जल्द नए इलाके भी जुड़ जाएंगे। केजरीवाल ने मेट्रो को लेकर हुए इस काम के लिए दिल्ली सरकार और सभी दिल्लीवासियों को बधाई दी।

राज्य सरकार के कारण मेट्रो के चौथे चरण में हुआ विलंबः भाजपा

भाजपा ने राज्य सरकार पर मेट्रो के विस्तार को लेकर झूठा श्रेय लेने का आरोप लगाया। दिल्ली प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजेंद्र गुप्ता ने कहा था कि आप की सरकार के कारण मेट्रो के तीसरे चरण और चौथे चरण के निर्माण कार्य में विलंब हुआ है। अब मुख्यमंत्री आतिशी इसे लेकर भ्रम फैला रही हैं।

उन्होंने कहा था कि पहले कांग्रेस और उसके बाद आप सरकार ने मेट्रो के तीसरे व चौथे चरण के काम को बाधित किया। गुप्ता ने कहा कि वर्ष 2015 में आप की सरकार बनने के बाद चार वर्षों तक चौथे चरण की फाइलों को स्वीकृति नहीं दी गई।

भगवान शंकर की समाधि भंग करने के लिए ब्रह्मा जी ने किस देवता का नाम सुझाया?

ब्रह्माजी ने देवताओं को यही तो समाधान दिया था, कि अगर भगवान शंकर के वीर्य से उत्पन्न पुत्र से तारकासुर का रण होगा, तभी तारकासुर का वध संभव है। लेकिन समस्या तो यह थी, कि भगवान शंकर तो समाधि में हैं।

भगवान शंकर को, जब यह प्रमाणिकता प्राप्त हुई कि देवी पार्वती जी ही वह शक्ति हैं, जिनसे उनका विवाह होना है। तो संसारिक जीवों की भाँति वे राग-रंग के संसाधनों में लिप्त नहीं हुए। अपितु इसके विपरीत फिर से ध्यान गहराईयों में डूब जाते हैं। यही आचरण उनका तब भी था, जब श्रीसती जी उनसे मिथ्या भाषण करती हैं, और उनका दक्ष के यज्ञ में निधन भी हो जाता है।

कहने का तात्पर्य, कि जीव को भी सदैव, ऐसे ही आचरण का निर्वाह करना चाहिए। उसके जीवन में भले ही तो उसका जीवन साथी बिछुड़े, अथवा भले ही नये जीवन साथी की प्राप्ति हो, उसे हर प्रस्थिती में प्रभु के भजन में ही लगे रहना चाहिए। तब देखिए ब्रह्माजी भी आपको विकट से विकट समस्या के समाधान के लिए याद करेंगे।

ब्रह्माजी ने देवताओं को यही तो समाधान दिया था, कि अगर भगवान शंकर के वीर्य से उत्पन्न पुत्र से तारकासुर का रण होगा, तभी तारकासुर का वध संभव है। लेकिन समस्या तो यह थी, कि भगवान शंकर तो समाधि में हैं। उनकी समाधि कितने सहस्त्र वर्ष चले, कोई पता नहीं। ऐसा भी नहीं, कि उनकी समाधि को कोई भंग कर सकता था। किंतु तब भी आज के समीकरण यह थे, कि जिस समाधि की अवस्था में बड़े बड़े संत महापुरुष रहते हैं, व उसका संरक्षण करते हैं, आज वही समाधि को भंग करने की आवश्यकता आन पड़ी थी। मानव जीवन के सर्वोच्च पद ही समाधि है। इसके पश्चात तो कुछ भी पाना शेष नहीं है। केवल व्यक्तिगत लाभ के लिए ही नहीं, अपितु संपूर्ण पृथवी के कल्याण के लिए समाधि की आवश्यक्ता होती है। कारण कि जब कोई भी समाधि की अवस्था को प्राप्त होता है, तो उस समाधिस्थ महानुभूति के सरीर से दुर्लभ व दिव्य तरंगों का विस्तार होता है। यह तरंगें संसार में होने वाले तीनों प्रकार के तापों का समाधान कर्ता होती हैं। इसीलिए कहा जाता है, कि समाधिस्थ महात्मा को कभी छेड़ना नहीं चाहिए। क्योंकि इस दुर्लभ अवस्था को कोई-कोई प्राप्त करता है।

किंतु आज समीकरण ऐसे हैं, कि स्वयं विधाता ही असमंजस की स्थिति में चले गए हैं। वे नहीं चाह कर भी चाह रहे हैं, कि भगवान शंकर की समाधि भंग हो जाये। अब ऐसा निंदनीय कार्य कोई महात्मा तो करने से रहे। तो कौन है, जो यह साहस कर पायेगा। तो इसके लिए ब्रह्माजी ने देवताओं को नाम सुझाया 'कामदेव' का। कारण कि कामदेव ही है, जो संसार में किसी सभा में शौभा नहीं पाता। जबकि हर कोई काम का दास है, किंतु जब भी किसी से सार्वजनिक स्तर पर कामदेव की बात की जाती है, तो कोई भी काम विषय पर खुलकर बात करने को राजी नहीं होता है। बात करता भी है, तो केवल उसकी बुराई ही करता है। फिर ऐसा कुकृत्य तो काम के हिस्से ही आये तो न्याय सा प्रतीत होता है। इसलिए हे देवताओ! तुम जाकर कामदेव को मनाओ-

'पठवहु कामु जाइ सिव पाहीं।
करै छोभु संकर मन माहीं।।
तब हम जाइ सिवहि सिर नाई।
करवाउब बिबाहु बरिआई।।'

अर्थात कामदेव जब भगवान शंकर की समाधि भंग कर देगा, तब हम जाकर भोलेनाथ के चरणों में अपना सीस रख देंगे, और जबरदस्ती उन्हें विवाह के लिए मना लेंगे। देवताओं को ब्रह्माजी की यह सम्मति बहुत अच्छी लगी। तब सभी देवताओं ने बड़े प्रेम से कामदेव की स्तुति की और तब पाँच बाण धारण करने वाला और मछली के चिन्नयुक्त ध्वजा वाला कामदेव प्रकट हुआ।

कामदेव इस कार्य के लिए सहमत होता है, अथवा नहीं, यह तो हम अगले अंक में देखेंगे। किंतु इस संदेश को अंगीकार अवश्य करेंगे, कि कभी-कभी जीवन में वह पक्ष भी अत्यंत लाभकारी व श्रेष्ठ होता है, जिसे हम बड़ी बड़ी सभायों में निंदा का पात्र बताते हैं। अधर्म का पर्याय बन चुके कामदेव से भी कुछ अच्छा कार्य संभव हो सकता है, यह आज प्रथम बार देखने को मिल रहा था।

ऐसे ही समाधि, भले ही जीवन का सार ही क्यों न हो, लेकिन अगर जीवन के किसी मोड़ पर, समाधि भी लोक कल्याण में बाधा है, तो इसे तोड़ने में संकोच नहीं करना चाहिए।

कामदेव भगवान शंकर की समाधि भंग करने के लिए देवताओं का साथ देता है, अथवा नहीं, जानेंगे अगले अंक में---
(क्रमशः)---जय श्रीराम।

अल्जाइमर रोग होने पर सोचने-समझने की क्षमता होती है प्रभावित, वैज्ञानिकों ने ढूंढा इलाज

अल्जाइमर की समस्या होने पर सोचने-विचारने की क्षमता प्रभावित होती है और चीजों को याद रखने में मुश्किल होती है। हालांकि इस बीमारी के लक्षणों को कम करने और इस बीमारी से बचाव के लिए कुछ दवाओं को प्रयोग में लाया जाता है।

अल्जाइमर रोग वैश्विक स्तर पर बढ़ती एक गंभीर बीमारी है। इस दुनिया में करीब 5.5 करोड़ से ज्यादा लोग अल्जाइमर और इसकी वजह से होने वाली डिमेंशिया की बीमारी से पीड़ित हैं। वहीं आंकड़ों की मानें, तो हर साल करीब 1 करोड़ से ज्यादा लोग इस बीमारी की चपेट में आ रहे हैं। इस बीमारी में मस्तिष्क का आकार सिकुड़ जाता है और कोशिकाओं में क्षति होने लगती है। अल्जाइमर की समस्या होने पर सोचने-विचारने की क्षमता प्रभावित होती है और चीजों को याद रखने में मुश्किल होती है। हालांकि इस बीमारी के लक्षणों को कम करने और इस बीमारी से बचाव के लिए कुछ दवाओं को प्रयोग में लाया जाता है। वहीं अब मस्तिष्क संबंधी इस विकार के इलाज में भारतीय वैज्ञानिकों को बड़ी कामयाबी मिली है।

वैज्ञानिकों द्वारा विकसित किए नए मॉलिक्यूल

पुणे स्थित आघारकर अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों ने द्वारा अल्जाइमर रोग के इलाज के लिए नए मॉलिक्यूल विकसित किए गए हैं। दो वैज्ञानिकों ने मिलकर सिंथेटिक, कम्प्यूटेशनल और इन-विट्रो अध्ययनों के जरिए से नए अणुओं को संश्लेषित और डिजाइन किया है। विशेषज्ञों की मानें, तो यह मॉलिक्यूल नॉन टॉक्सिक हैं और इस गंभीर बीमारी के इलाज में प्रभावी हो सकते हैं।

वैज्ञानिकों के मुताबिक यह अणु कोलिनेस्टरेज एंजाइमों के विरुद्ध प्रभावी हैं। इनके इस्तेमाल से दवाएं तैयार की जा सकती हैं और यह मस्तिष्क की इस बीमारी को भी ठीक करने में प्रभावी रूप में सहायक हो सकती हैं।

अल्जाइमर रोग के उपचार में अहम खोज

शोधकर्ताओं की मानें, तो वैज्ञानिकों द्वारा की गई यह खोज अल्जाइमर रोग के इलाज में काफी अहम साबित हो सकती है। वहीं अगर इसके अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, तो इस गंभीर न्यरोलॉजिकल समस्या के इलाज में आसानी होगी।

यह रोग स्तिष्क में संचार की प्रक्रिया में होने वाली गड़बड़ी की वजह से होता है। जिसके कारण सीखने और याददाश्त में कमी आती है। साथ ही इस बीमारी के होने से व्यक्ति के व्यवहार में भी बदलाव आने लगता है।

अल्जाइमर का इलाज

इस रोग के इलाज में ऐसी दवाओं का इस्तेमाल किया जाता रहा है, जो इसके लक्षणों को कम करने में सहायता करती है। यह दवाएं स्मृति को कम होने से संबंधित लक्षणों और अन्य परिवर्तनों को सुधारने में मदद करती है। हेल्थ एक्सपर्ट की मानें, तो इस नई खोज से इलाज की प्रक्रिया को और भी आसान बनाया जा सकेगा। साथ ही यह क्वालिटी ऑफ लाइफ को सुधारने में सहायक साबित हो सकती है।

लाइफस्टाइल को रखें ठीक

बता दें कि ऑस्ट्रेलिया में अल्जाइमर रोग के इलाज को लेकर इससे पहले किए गए एक अन्य अध्ययन में रोगियों में व्यायाम, आहार और अन्य लाइफस्टाइल में बदलावों पर जोर दिया गया था। ऐसे में शोधकर्ताओं ने पाया कि खराब लाइफस्टाइल वाले लोगों की तुलना में रोजाना एक्सरसाइज और सामाजिक रूप से जुड़े रहने से इस बीमारी का खतरा काफी कम हो सकता है। गेम खेलना, नृत्य करना, पढ़ना, सोशल एक्टिविटी में हिस्सा लेना, कोई वाद्य बजाना और अन्य एक्टिविटी में शामिल होकर आप इस गंभीर स्वास्थ्य समस्या के खतरे को कम कर सकते हैं।

सर्दियों में सुपरफूड से कम नहीं है आंवला, रोज आंवले का सेवन करें, मिलेंगे अनगिनत फायदे

विटमिन सी भरपूर आंवला एक सुपरफूड की तरह है। इसके फायदे जानकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। आंवला के फायदे इतने है कि आप इसे खाने से खुद को नहीं रोक पाएंगे। बालों से लेकर पेट संबंधित सभी समस्याओं को दूर करता है आंवला।

आयुर्वेद में आंवला को अमृत बताया गया है। सर्दियों में आंवला खाने से कई फायदे मिलते हैं। सुपरफूड से कम नही है आंवला, क्योंकि इसमें कई पोषक तत्व पाए जाते है। पौराणिक मान्यता है कि अमृत मे सभी रस समाहित होते हैं, इसलिए यह अमरता प्रदान करता है। यानी के आंवले में हरड़ में पांच रस होते हैं। इसलिए इसे अमृत के बाद दूसरे स्थान पर रखा गया है। आंवला में विटामिन- सी, ए, कार्बोहाइड्रेट और फाइबर जैसे महत्वपूर्ण पोषक तत्व होते हैं, जो एंटी-एजिंग, एंटीऑक्सीडेंट और एंटी-कार्सिनोजेनिक गुण भी पाए जाते है। इसी वजह से आंवला सेहत के लिए लाभकारी है।

प्रतिदिन एक आंवला खाने के फायदे

इम्यून सिस्टम मजबूत होता

आंवला में सबसे ज्यादा विटामिन सी का सोर्स पाया जाता है। वहीं, इम्यून फंक्शन के लिए बेहद महत्वपूर्ण न्यूट्रिएंट में से एक है। एक स्टडी के मुताबिक, आंवले में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट हमें ऑक्सिडेटिव स्ट्रेस से बचाते हैं। इसके साथ ही इम्यून सिस्टम भी मजूबत होता है।

डाइजेशन में सुधार

प्रतिदिन आंवला खाने से पेट संबंधित समस्याएं दूर होती है। इसके साथ ही पेट से जुड़ी समस्याओं से भी राहत मिलता है।

हार्ट हेल्थ बेहतर होता है

रोजाना एक आंवला खाने से हार्ट डिजीज के कई जोखिम कम हो सकते हैं। कोलेस्ट्रॉल लेवल, ट्राइग्लिसराइड लेवल और ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहता है।

हेयर्स हेल्दी रहते हैं

आंवला हेयर्स फॉलिकल्स को पोषण प्रदान करता है। बालों की जड़ों को मजबूत करने और समय से पहले सफेद होने से रोकने में मदद करता है। इससे बाल हेल्दी, चमकदार और घने दिखने लगते हैं।

डायबिटीज रोगियो के लिए फायदेमंद

जो लोग डायबिटीज से परेशान हैं उन्हें आंवले का सेवन करना चाहिए। आंवला में कुछ ऐसे कंपाउंड्स मौजूद होते हैं जो ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करते हैं, जो डायबिटीज वाले मरीजों के लिए फायदा पहुंचाता है।

आंखों की सेहत के लिए फायदेमंद

बता दें, रोजाना एक आंवला खाने से आंखों की रोशनी तेज होती है। आंवला कैरोटीन से भरपूर होता है। डॉक्टर भी कहते हैं कि रोज आंवला और शहद खाने से आंखों की सेहत के लिए बहुत अच्छा माना जाता है।

मेंटल हेल्थ में फायदेमंद

यदि आप रोजाना आंवला खाते हैं तो यह ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है और नर्व हेल्थ में सुधार करता है। आंवले में पर्याप्त मात्रा में डाइटरी फाइबर होता है, जो वेट मैनेजमेंट में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आंवले का आप जूस पी सकते हैं।

10 हजार रुपये से कम में मिल रहा यह स्मार्ट फोन, 108MP कैमरा के साथ गजब के फीचर्स

आपको बता दें कि, अमेजन पर फिर से itel Days सेल शुरु हो गई है। यह सेल 27 नवंबर तक चलने वाली है। इस सेल में आइटेल के सभी स्मार्टफोन्स पर शानदार छूट मिल रही है। आप सेल में आइटेल का यह स्मार्टफोन खरीद सकते हैं।

अगर आप कम बजट में सस्ता स्मार्टफोन तलाश रहे हैं तो आप यह 108MP कैमरे वाला फोन जरुर खरीद सकते हैं। एक बार फिर से Itel days सेल शुरु हो चुकी है। 7 नवंबर तक चलने वाली है, इसमें आप आइटेल के सभी स्मार्टफोन्स पर शानदार छूट मिल रही है। आइए आपको डिटेल में बताते हैं itel सेल में मिलने वाले ऑफर्स और डिस्काउंट के बारे में-

108MP कैमरा वाले itel S24 पर मिल रही जबरदस्त छूट

itel S24 को कंपनी ने 9999 रुपये में लॉन्च किया है। आइटेल डेज सेल में इस फोन पर 8499 रुपये का डिस्कांउट मिल रहा है। सेल में 1 हजार रुपये तक का बैंक डिस्काउंट दिया जा रहा है। यदि आप पुराने फोन से एक्सचेंज करना चाहते हैं तो इस पर आपको 7000 रुपये की छूट मिलेगी। लेकिन यह एक्सचेंज ऑफर मिलने वाला डिस्काउंट फोन की कंडीशन और ब्रैंड पर निर्भर करेगा।

जानें इसके फीचर्स

आइटेल के इस फोन में 6.6 इंच की एचडी+ डिस्प्ले है। डिस्प्ले में 90Hz के रिफ्रेश रेट सपोर्ट के साथ आ रहा है। इस फोन में 8gb हार्डवेयर के साथ 8जीबी वर्चुअल रैम भी दे रही है। इससे फोन की टोटल रैम 16जीबी तक की हो जाती है। फोन में 128जीबी के इंटरनल स्टोरेज के साथ आता है। यह फोन ऐंड्रॉयड 13 पर बेस्ड itel OS 13 पर काम करता है। फोन मे मीडियाटेक हीलियो G91 चिपसेट देखने को मिलेगा। कैमरे की बात करें तो इसमें 108 मेगापिक्सल को मेन लेंस है। फोन में फ्रंट में सेल्फी के लिए आपको 8 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिलेगा। वहीं, फोन में 5000mAh की बैटरी है जो 18 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है।

अब फूलगोभी से कीड़े निकालना होगा बहुत आसान, अपनाएं ये सिंपल हैक्स

सीजनल सब्जियां ऑफ सीजन में कभी भी स्वादिष्ट नहीं लगती हैं। अब आप फूल गोभी को ही ले लीजिए। फूल गोभी ठंड के दिनों में आती है और इसको बनाना भी काफी आसान होता है। यह सब्जी काफी अच्छी बनती है, लेकिन इसके फूलों में कीड़े छिपे होते हैं। ऐसे में इन कीड़ों को हटाना काफी मुश्किल हो जाता है। क्योंकि यह कीड़े दिखाई नहीं देते हैं हैं और फूल पर चिपके होते हैं। तो वहीं कुछ लोगों को फूल गोभी अच्छे से काटना नहीं आता है, जिसके कारण फूल के टुकड़े-टुकड़े हो जाते हैं। ऐसे में आज इस आर्टिकल के जरिए हम आपको फूलगोभी से कीड़े हटाने के कुछ आसान तरीकों और इसे काटने के सही तरीके के बारे में बताने जा रहे हैं।

गोभी में कीड़े लगने की वजह

बता दें कि फूलगोभी नम वातावरण में जमीन के नीचे उगती है। जिसके वजह से इसमें कीड़े लग जाते हैं। वहीं इसके घने पत्तों और स्टेम्स में कीड़े आसानी से छिप जाते हैं। यह कीड़े फूल के अंदर गहराई तक जा सकते हैं। ऐसे में इन कीड़ों को पहली नजर में पहचानना मुश्किल होता है।

कीड़े निकालने के उपाय

नमक के पानी में भिगोना

फूल गोभी से कीड़ा निकालने का सबसे आसान और प्रभावी तरीका है कि आप इसको नमक के पानी में भिगो दें। नमक का पानी गोभी में छिपे कीड़ों और गंदगी को निकालने में सहायता करता है।

क्या करें

सबसे पहले एक बड़े कटोरे में हल्का गुनगुना पानी भर लें और इसमें 2-3 चम्मच नमक डालकर इसको घुलने दें।

अब गोभी को बड़े टुकड़े में काटकर इन्हें 15-20 मिनट के लिए पानी में डुबोकर रखें।

इसके बाद गोभी को पानी में डालकर धीरे-धीरे घुमाएं और अब गोभी को ठंडे पानी से धो लें, जिससे कि बचा हुआ नमक और कीड़े निकल जाएं।

यह उपाय गोभी से कीड़े निकालने के लिए काफी कारगर साबित होगी। क्योंकि नमक कीड़ों को इरिटेट करता है।

हल्दी के पानी में डुबोएं

फूल गोभी से कीड़े निकालने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप इसको हल्दी के पानी में कुछ देर के लिए डुबो दें। हल्दी जीवाणुरोधी और एंटीफंगल गुणों के लिए जानी जाती है। इसकी तेज महक कीड़ों को निकालने में मदद करती है।

क्या करें

सबसे पहले एक बड़े कटोरे में गर्म पानी में 1-2 चम्मच हल्दी पाउडर मिलाएं। अब इसमें 15 मिनट के लिए गोभी भिगोने के लिए डाल दें।

अब 15 मिनट बाद पानी निकालकर गोभी को अच्छे से धो लें, जिससे कि हल्दी अच्छे से साफ हो जाए।

क्योंकि हल्दी का पानी बैक्टीरिया मारने और फूलों की दरारों से कीड़े को बाहर निकालने में सहायता करता है।

ब्लांचिंग की मदद से निकाले कीड़े

बता दें कि फूल गोभी को ब्लांच करने से इसमें मौजूद कीड़े निकल जाएंगे और सब्जी भी आसानी से पक जाएगी। वहीं ब्लांच करके आप इसको फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं।

क्या करें

सबसे पहले बड़े बर्तन में पानी उबाल लें और गोभी को बड़े-बड़े टुकड़ों में काटकर उसे उबलते हुए पानी में 2-3 मिनट के लिए रखें।

गोभी को ब्लांच करने के बाद फौरन इसे बर्फ के ठंडे पानी के कटोरे में डालें, जिससे कि फूल गोभी के पकने की प्रक्रिया खत्म हो जाए।

अब पानी को छानकर फूलगोभी को ध्यान से जांच लें, हालांकि ब्लांच करने पर हीट करने की वजह से कीड़े मर जाएंगे या फिर बाहर निकल जाएंगे।

इसके बाद आप चाहें तो गोभी को आगे के लिए स्टोर करके रख सकती हैं।

फूल गोभी काटने का सही तरीका

क्या आपको भी फूल गोभी का एक-एक फूल अलग करने में मुश्किल का सामना करते हैं। तो आप हमारे बताए गए तरीकों को फॉलो कर एक समान फूल काट लेंगे।

सबसे पहले फूल गोभी के बाहरी पत्तों को हटा लें, क्योंकि इनमें ज्यादा कीड़े होते हैं। अब गोभी के निचले हिस्से से मोटी और बड़ी हरी पत्तियां हटाएं। आप चाहें तो इनको हाथों से तोड़कर अलग कर सकते हैं।

फूल गोभी के तने का भी उपयोग किया जाता है। अगर आपको इसका तना पसंद नहीं है, तो आप गोभी के डंठल से काटकर अलग कर सकते हैं।

खूबसूरत समुद्र तटों और प्राकृतिक सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध है विशाखापत्तनम

रामकृष्ण समुद्र तट, विशाखापत्तनम का सबसे लोकप्रिय समुद्र तट है। यहाँ पर सूर्योदय और सूर्यास्त का दृश्य मंत्रमुग्ध कर देने वाला होता है। तट पर कई कैफे और रेस्टोरेंट हैं, जहाँ आप ताजगी भरे समुद्री भोजन का आनंद ले सकते हैं।

विशाखापत्तनम, जिसे अक्सर ₹विजाग₹ के नाम से जाना जाता है, आंध्र प्रदेश का एक प्रमुख तटीय शहर है। यह अपने खूबसूरत समुद्र तटों, ऐतिहासिक स्थलों और प्राकृतिक सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ के पर्यटन स्थलों की विविधता इसे एक आकर्षक गंतव्य बनाती है। आइए जानते हैं विशाखापत्तनम के कुछ प्रमुख पर्यटन स्थलों के बारे में।

1. रामकृष्ण समुद्र तट (RK Beach)

रामकृष्ण समुद्र तट, विशाखापत्तनम का सबसे लोकप्रिय समुद्र तट है। यहाँ पर सूर्योदय और सूर्यास्त का दृश्य मंत्रमुग्ध कर देने वाला होता है। तट पर कई कैफे और रेस्टोरेंट हैं, जहाँ आप ताजगी भरे समुद्री भोजन का आनंद ले सकते हैं।

2. काली देवी मंदिर

यह मंदिर शहर की सबसे पुरानी धार्मिक स्थलों में से एक है। काली देवी के इस मंदिर में हर साल हजारों भक्त दर्शन के लिए आते हैं। यहाँ से शहर का दृश्य भी अद्भुत होता है।

3. सिंहचालम

यह स्थान विशेष रूप से अपने गहरे जंगलों और पहाड़ी क्षेत्रों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ की ट्रैकिंग और हाइकिंग के अवसर साहसिक प्रेमियों के लिए एक आदर्श अनुभव देते हैं।

4. बोर्रा गुफाएँ

बोर्रा गुफाएँ, विशाखापत्तनम के निकट स्थित हैं और प्राचीन काल से बनी हुई हैं। यहाँ का वातावरण और शांतता पर्यटकों को मंत्रमुग्ध कर देती है।

5. विजाग प्रादेशिक संग्रहालय

यह संग्रहालय आंध्र प्रदेश की सांस्कृतिक धरोहर को प्रदर्शित करता है। यहाँ प्राचीन कलाकृतियों, आदिवासी कला, और पुरातात्विक वस्तुओं का संग्रह है। यह संस्कृति के प्रति रुचि रखने वालों के लिए एक महत्वपूर्ण स्थल है।

6. नेत्रा देवी मंदिर

यह मंदिर समुद्र के किनारे पर स्थित है और यहाँ का शांत वातावरण और अद्भुत दृश्य इसे एक अनूठा स्थान बनाता है। भक्त यहाँ आकर शांति और आशीर्वाद प्राप्त करते हैं।

7. मूसीलिपट्नम

यह एक ऐतिहासिक स्थान है जो प्राचीन काकातिया वंश से जुड़ा हुआ है। यहाँ के अवशेष और धरोहरें इतिहास प्रेमियों के लिए विशेष रुचि का विषय हैं।

8. विजाग का चाय बागान

विशाखापत्तनम के आसपास के चाय बागान अपने हरित सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध हैं। यहाँ की चाय की गुणवत्ता भी उच्चतम स्तर की होती है। चाय बागानों में घूमना और चाय का स्वाद लेना एक अद्भुत अनुभव है।

देखा जाये तो विशाखापत्तनम एक ऐसा शहर है जो न केवल अपने समुद्र तटों के लिए जाना जाता है, बल्कि यहाँ की संस्कृति, इतिहास और प्राकृतिक सौंदर्य भी इसे विशेष बनाते हैं। चाहे आप इतिहास प्रेमी हों, साहसिकता के शौकीन हों या बस एक शांत छुट्टी की तलाश में हों, विशाखापत्तनम आपके लिए एक आदर्श गंतव्य है। यहाँ की यात्रा निश्चित रूप से आपके मन में एक विशेष स्थान बनाएगी।

दिल्ली में पांच दिन बाद AQI 400 के नीचे, हवा की गुणवत्ता 'खराब' श्रेणी में; जानें NCR का हाल

सीपीसीबी द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली का औसत एक्यूआई बेहद खराब श्रेणी में 371 रहा। इसके एक दिन पहले दिल्ली का AQI गंभीर श्रेणी में 419 था। इसके मुकाबले AQI 48 अंक कम हुआ। सुबह में दिल्ली में 12 जगहों पर एक्यूआई 400 से अधिक था। इससे शाम साढ़े पांच बजे दिल्ली के 35 प्रदूषण निगरानी केंद्रों में से छह जगहों पर एयर इंडेक्स 400 से अधिक रहा।

परिवहन विशेष न्यूज

नई दिल्ली। राजधानी में स्मॉग से भरी प्रदूषित हवा से लोगों को राहत मिली है। स्मॉग छटने और कोहरे से भी राहत रहने से गुरुवार को एयर क्वालिटी इंडेक्स (एक्यूआई) में गिरावट हुई। इससे प्रदूषण के स्तर में सुधार हुआ है। इससे लोगों ने पिछले दिनों के मुकाबले ज्यादा साफ हवा में सांस ली। आसमान भी पूरे दिन साफ रहा। दिन में गुनगुनी धूप खिली रही। लोग ऐतिहासिक स्थलों पर सामान्य दिनों की तरह घूमते नजर आए और बच्चे भी घर से बाहर निकलकर खेलते दिखे।

स्विस कंपनी के एप आइक्यूएयर के एक्यूआई का डाटा भी हवा की गुणवत्ता में हुए सुधार की तरफ इशारा कर रहा है। वहीं केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार पांच दिन बाद बृहस्पतिवार को दिल्ली का एयर इंडेक्स घटकर 400 से नीचे तो आ गया है लेकिन लेकिन हवा की गुणवत्ता खराब श्रेणी में बताया है।

आईएक्यूएयर एप ने द्वारका सेक्टर आठ में AQI 296 बताया

आईक्यूएयर एप ने दिल्ली में दिन में 11:30 बजे दिल्ली का एक्यूआई 326 बताया। बाद में हवा की गुणवत्ता में सुधार होने से शाम साढ़े बजे बजे दिल्ली का एक्यूआई 186 बताया। सीपीसीबी द्वारा निर्धारित मानक के अनुसार एक्यूआई 186 होने पर हवा की गुणवत्ता मध्यम श्रेणी में मानी जाती है। आईएक्यूएयर एप ने द्वारका सेक्टर आठ में एयर इंडेक्स सबसे अधिक 296 बताया।

दिल्ली का औसत एक्यूआई बेहद खराब श्रेणी में 371

दूसरी ओर सीपीसीबी द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली का औसत एक्यूआई बेहद खराब श्रेणी में 371 रहा। इसके एक दिन पहले दिल्ली का एयर इंडेक्स गंभीर श्रेणी में 419 था। इसके मुकाबले एयर इंडेक्स 48 अंक कम हुआ। सीपीसीबी के अनुसार सुबह में दिल्ली में 12 जगहों पर एक्यूआई 400 से अधिक था। बाद में एक्यूआई में सुधार हुआ। इससे शाम साढ़े पांच बजे दिल्ली के 35 प्रदूषण निगरानी केंद्रों में से छह जगहों पर एयर इंडेक्स 400 से अधिक रहा।

दिल्ली के मुकाबले NCR के शहरों में प्रदूषण से अधिक राहत

जहांगीरपुरी का एयर इंडेक्स सबसे अधिक 433 व वजीरपुर का एयर इंडेक्स 427 था। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) द्वारा जारी देश के 253 एयर इंडेक्स रिपोर्ट के अनुसार देश में हाजीपुर का एक्यूआई सबसे अधिक 403 रहा। इसके बाद दिल्ली का एक्यूआई ज्यादा रहा।

सीपीसीबी के अनुसार एनसीआर के सभी प्रमुख शहरों में बृहस्पतिवार को एयर इंडेक्स खराब श्रेणी में 300 से नीचे आ गया। इसलिए दिल्ली के मुकाबले एनसीआर के शहरों में प्रदूषण से अधिक राहत रही। सीपीसीबी के अनुसार दिल्ली में तीन दिन हवा की गुणवत्ता बेहद खराब श्रेणी में रह सकती है।

प्रदूषण में वाहनों के उत्सर्जन की भूमिका 17.75 प्रतिशत

आइआइटीएम पुणे के डिसिजन सपोर्ट सिस्टम (डीएसएस) के डाटा के अनुसार बृहस्पतिवार को दिल्ली के प्रदूषण में वाहनों के उत्सर्जन की भूमिका 17.75 प्रतिशत रही। लेकिन प्रदूषण में पराली के धुएं की भूमिका कितनी रही यह आंकड़ा डीएसएस पर वास्तविक समय में जारी न करके दो दिन बाद जारी हो रही है। 19 नवंबर को दिल्ली के प्रदूषण में पराली के धुएं की भूमिका 22.10 प्रतिशत थी।

सीपीसीबी द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार एनसीआर का एयर इंडेक्स

दिल्ली- 371
गुरुग्राम- 298
गाजियाबाद- 291
नोएडा- 253
फरीदाबाद- 243
ग्रेटर नोएडा- 212

शाम पांच बजे दिल्ली में अधिक प्रदूषित जगहों का एयर इंडेक्स

जहांगीरपुरी- 433
वजीरपुर- 427
शादीपुर- 410
अशोक विहार- 408
नेहरू नगर- 404
बवाना- 406

भाजपा नेता भूपेंद्र गोठवाल द्वारा किया गया "कार्यकर्ता स्नेह मिलन" कार्यक्रम का भव्य आयोजन

परिवहन विशेष न्यूज

नई दिल्ली। दिल्ली प्रदेश भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के पूर्व अध्यक्ष भूपेंद्र गोठवाल द्वारा मादीपुर में दिवाली, छठ पर्व एवं गुरु पर्व स्नेह मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिसमें भारी संख्या में स्थानीय भाजपा कार्यकर्ता एवं अन्य लोगों ने भाग लिया। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से दिल्ली प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा पश्चिमी दिल्ली की सांसद कमलजीत सेहरावत, भाजपा की राष्ट्रीय मंत्री और दिल्ली सह प्रभारी डॉ. अलका गुर्जर, प्रदेश महामंत्री विष्णु मित्तल, प्रदेश उपाध्यक्ष एवं पश्चिमी दिल्ली प्रभारी राजकुमार भाटिया, पश्चिमी दिल्ली अध्यक्ष चंद्रपाल बक्शी, मादीपुर विधानसभा संयोजक प्रवीण विज, जिला उपाध्यक्ष महेश यादव, महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष स्वाति शर्मा, एससी मोर्चा जिला अध्यक्ष मोहन मोरिया, मादीपुर मंडल अध्यक्ष लक्ष्मण दास पप्पू, रघुवीर नगर मंडल अध्यक्ष नीरज गुप्ता आदि शामिल हुए।

इस अवसर पर श्री गोठवाल ने कहा कि दिवाली छठ पर्व एवं गुरु पर्व हिंदू-सिखो का महापर्व है। आप सभी ईश्वरीय तुल्य कार्यकर्ताओं की मेहनत के दम पर भाजपा ने लोकसभा में अपना परचम लहराया था, और इस विधानसभा चुनाव में भी दिल्ली की भ्रष्ट सरकार को हम सब मिलकर भगाएंगे और भाजपा की सरकार बनाएंगे।

इस अवसर पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने पर्व के सफलतापूर्वक समापन हेतु अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया।

मणिपुर में हिंसा को समाप्त करने और शांति बहाल करने के लिए तत्काल कार्रवाई की आवश्यकताः जमाअत-ए-इस्लामी हिंद

सुषमा रानी

नई दिल्ली, जमाअत-ए-इस्लामी हिंद के उपाध्यक्ष प्रोफेसर सलीम इंजीनियर ने मणिपुर में जारी हिंसा पर गहरी चिंता व्यक्त की है। मीडिया को जारी एक बयान में उन्होंने कहा, "मणिपुर में अशांति जारी है, जिसके परिणामस्वरूप आम लोगों को भारी कष्ट उठाना पड़ रहा है और राज्य में शांति के लिए बड़ा खतरा पैदा हो गया है। सरकार राज्य को अपनी चपेट में लेने वाले हिंसा के इस चक्र को समाप्त करने के लिए तत्काल कार्रवाई करे। हम सभी पीड़ितों - मैतेई, कुकी और अन्य के साथ एकजुटता से खड़े हैं तथा अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं। राज्य और केंद्र सरकार की उदासीनता अत्यंत चिंताजनक है, तथा मणिपुर के प्रति उनकी उदासीनता तथा हिंसा को समाप्त करने और सामान्य स्थिति बहाल करने में उनकी विफलता पूरी तरह अन्यायपूर्ण है।₹

प्रोफेसर सलीम इंजीनियर ने कहा, ₹हम मुख्यमंत्री एन. बीरेन सिंह की बर्खास्तगी की मांग कर करते हैं जिन्होंने नागरिकों के जीवन और संपत्ति की सुरक्षा के लिए अपने संवैधानिक कर्तव्यों का त्याग किया है। लगभग डेढ़ साल से चल रही यह हिंसा सवाल खड़े करती है कि सरकार या प्रशासन के कुछ अधिकारी इस संघर्ष का समर्थन करके और त्रासदी को लम्बा खींचकर अपने हितों की पूर्ति कर रहे हैं? राहत शिविरों में लोगों की हालत दयनीय है। विस्थापितों के लिए बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराकर इन शिविरों को समाप्त किया जाना चाहिए। घायलों को उचित मुआवजा मिलना चाहिए, साथ ही मृतकों के परिवारों के लिए सार्थक समाधान भी होने चाहिए। अति प्रभावित लोगों के दर्द को कम करने के लिए ये कदम ज़रूरी हैं।₹

जेआईएच के उपाध्यक्ष ने कहा, ₹हम मणिपुर के पंगल मुस्लिम समुदाय के शांति प्रयासों और सभी मैतेई और कुकी पीड़ितों के समर्थन में सक्रिय कार्य के लिए उनकी पहल की भी सराहना करते हैं। इन चुनौतीपूर्ण दिनों में उनका कार्य आशा और एकजुटता का प्रतीक है। जमाअत-ए-इस्लामी हिंद सभी से संयम बरतने और हिंसा के बजाय बातचीत और चर्चा के माध्यम से मुद्दों को हल करने का आग्रह करती है। शांति, सद्भाव और आपसी सम्मान ही स्थायी समाधान पाने के तरीके हैं।"

"राजवीर": न्याय, प्रतिशोध और भाईचारे की एक रोमांचक कहानी

सुषमा रानी

नई दिल्ली। प्रख्यात फिल्म निर्माता साकार राऊत और स्वप्निल देशमुख द्वारा निर्देशित, राजवीर अपने gripping कथानक और रोमांचक एक्शन दृश्यों के साथ एक्शन सिनेमा को नए आयाम देने के लिए तैयार है। साकार राऊत, ध्वनि सकार राऊत, गौरव परदसानी और सूर्यकांत बाजी द्वारा अर्थ स्टूडियोज़ के बैनर तले निर्मित यह फिल्म आईपीएस अधिकारी राजवीर देशपांडे की कहानी पेश करती है, जो अपने भाई अक्षय की ड्रग ओवरडोज़ से हुई दुखद मृत्यु के बाद न्याय पाने के लिए एक अडिग संघर्ष पर निकलता है।

फिल्म में मुख्य भूमिका में सुप्रसिद्ध बॉडीबिल्डर सुहास खामकर हैं, जो भारतीय सिनेमा में अपने प्रभावशाली डेब्यू के लिए तैयार हैं। 2018 मिस्टर एमेच्योर ओलंपिया और 2010 मिस्टर एशिया जैसे उल्लेखनीय खिताब जीतने वाले खामकर, अपने किरदार में गहराई और वास्तविकता लेकर आते हैं। फिल्म में प्राशी अवस्थी सुहास खामकर के विपरीत मुख्य महिला भूमिका निभाती हैं, जो कहानी में भावनात्मक जुड़ाव जोड़ती हैं। गौरव परदसानी खलनायक लक्ष्मण गायतोंडे के रूप में एक शानदार प्रदर्शन देते हैं, जो एक खतरनाक ड्रग कार्टेल का सरगना है। साथ ही, जाकिर हुसैन, जिन्हें सरकार और जॉनी गद्दार में उनकी भूमिकाओं के लिए सराहा गया है, एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जो कहानी को और गहराई प्रदान करती है।

साकार राऊत, भारतीय सिनेमा के सबसे युवा फिल्म निर्माताओं में से एक, ने कलाकार और शिव्या जैसी उल्लेखनीय मराठी फिल्मों के साथ अपनी पहचान बनाई है। राजवीर के साथ, राऊत अपने कॅरियर का विस्तार कर रहे हैं, जिसमें उच्च-ऑक्टेन एक्शन और प्रभावशाली कहानी का मेल है। उनकी इस सोच को फोटोग्राफी निर्देशक भूषण वेदपाठक का समर्थन प्राप्त है, और अर्थ स्टूडियोज़ की नवीनतम तकनीकों के साथ, यह फिल्म दर्शकों को एक अविस्मरणीय सिनेमाई अनुभव प्रदान करने का वादा करती है।

राजवीर लक्ष्मण गायतोंडे और उसकी सौतेली बेटी लीना के नेतृत्व वाले शक्तिशाली ड्रग कार्टेल के खिलाफ राजवीर की लड़ाई को प्रस्तुत करता है। कहानी तब रोमांचक मोड़ लेती है जब वह कानून प्रवर्तन तंत्र में भ्रष्टाचार का पर्दाफाश करता है और एनसीबी अधिकारी गणेश वानखेड़े के विश्वासघात का सामना करता है। रोमांच, एक्शन और न्याय व भाईचारे का मजबूत संदेश देने वाली यह फिल्म दर्शकों को बांधे रखने का वादा करती है।

अर्थ स्टूडियोज़, जो प्रोडक्शन, पोस्ट-प्रोडक्शन और मूल संगीत में अपने अनुभव के लिए प्रसिद्ध है, राजवीर के साथ भारतीय सिनेमा को नई ऊंचाइयों तक ले जाने की दिशा में अग्रसर है। यह फिल्म उनकी असाधारण दृश्यात्मकता और कहानी कहने की प्रतिबद्धता का प्रमाण है।

सरस आजीविका मेला में मस्कट के साथ फोटो लेते आगंतुक

सुषमा रानी

नई दिल्ली। सरस आजीविका मेला 2024 में जहां एक तरफ ग्रामीण भारत की शिल्पकलाओं का मुख्य रूप से प्रदर्शन किया गया है वहीं दूसरी तरफ लोग सरस पवेलियन में भरपूर मनोरंजन भी कर रहे हैं। यही कारण है कि सरस में कहीं लोग जहां मस्कट (सुभंकर) के साथ फोटो और सेल्फी ले रहे हैं वहीं लोग सरस में मौजूद बिग पाइप बैंड का भी आनंद ले रहे हैं। बिग पाइप बैंड के सुखविंदर सिंह बताते हैं कि समय समय पर सरस में आने वाले आगंतुकों के लिए उनकी टीम विभिन्न गानों के धुनों पर बैंड बजाते हैं जिससे कि दर्शकों की थकान मिट जाता है और लोग झूम उठते हैं। ज्ञात हो कि केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा आयोजित और राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान (एनआईआरडीपीआर) द्वारा समर्थित सरस आजीविका मेला 2024 का आयोजन भारत मंडपम में 43वें विश्व व्यापार मेले में किया गया है। 14 नवंबर से 27 नवंबर तक चलने वाले इस उत्सव में 31 राज्यों की 300 से अधिक महिला शिल्प कलाकार, 150 से अधिक स्टॉलों पर अपनी-अपनी उत्कृष्ट प्रदर्शनी का प्रदर्शन व बिक्री कर रही हैं। सरस आजीविका मेला भारत मंडपम के हॉल नंबर– 9 और 10 में लगाया गया है। सरस आजीविका मेला के दौरान देश भर के 31 राज्यों के हजारों उत्पादों की प्रदर्शनी और बिक्री हो रही है।

एक पिस्तौल और 1 चाकू के 3 तीन लुटेरे गिरफ्तार

सुषमा रानी

पूर्वी दिल्ली पुलिस थाना मयूर विहार के पुलिस कर्मियों द्वारा तीन लुटेरों को गिरफ्तार किया गया तथा एक देशी पिस्तौल (कट्टा), एक चाकू बरामद किया गया

पूर्वी दिल्ली पुलिस उपायुक्त अपूर्वा गुप्ता के अनुसार दिनांक 17 नवंबर को चाकू और पिस्तौल की नोंक पर 3500/- रुपए की लूट के संबंध में एक पीसीआर कॉल पुलिस थाना मयूर विहार में प्राप्त हुई SHO/PS मयूर विहार IO ASI योगेंद्र प्रसाद के साथ तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे, और देखा कि घायल कासिफ निवासी त्रिलोकपुरी, दिल्ली, उम्र-27 वर्ष, को मैराज नर्सिंग होम में स्थानांतरित कर दिया गया था। प्राथमिक उपचार लेने के बाद, घायल को आगे की आवश्यक चिकित्सा जांच के लिए एलबीएस अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया गया। घटनास्थल पर क्राइम टीम को बुलाया गया और घटनास्थल से घायलों के खून के नमूने एकत्र किए गए। अपराध स्थल के सीसीटीवी फुटेज प्राप्त किए गए और यह देखा गया कि 04 व्यक्ति त्रिलोकपुरी में "आशु ट्रैवल्स" नामक दुकान में घुसे थे और घायल कासिफ के साथ शारीरिक रूप से मारपीट शुरू कर दी थी। उन्होंने कट्टा लहराते हुए कासिफ पर हमला करना शुरू कर दिया था। लड़कों में से एक ने कासिफ पर बन्दूक के बट से हमला किया था। उसके बाद, सभी लड़के कासिफ को छोड़कर दुकान से भाग गए। इसलिए एफ आई आर थाना मयूर विहार में मामला दर्ज किया गया और जांच शुरू की गई।

अपराध की गंभीरता को देखते हुए, एसीपी मयूर विहार की देखरेख में और इंस्पेक्टर प्रमोद कुमार/एसएचओ थाना मयूर विहार के नेतृत्व में एएसआई योगेंद्र, एचसी मोहम्मद आसिफ, एचसी अजय, एचसी उपेंद्र, एचसी राकेश, कांस्टेबल अहोक मौर्य और कांस्टेबल अजय की एक टीम की मदद से सीसीटीवी फुटेज और सीडीआर के माध्यम से कई आरोपियों/संदिग्ध व्यक्तियों की पहचान की गई। अपराध स्थल के सीसीटीवी फुटेज और स्थानीय स्तर पर की गई पूछताछ के आधार पर तीन आरोपियों की पहचान की गई और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इनके नाम हैं साहिल उर्फ नाता निवासी त्रिलोकपुरी, दिल्ली, उम्र-19 वर्ष, फरमान उर्फ ताऊ निवासी त्रिलोकपुरी, दिल्ली, उम्र-20 वर्ष और माज निवासी त्रिलोकपुरी, दिल्ली, उम्र-19 वर्ष। जांच के दौरान, उपरोक्त आरोपियों की निशानदेही पर एक और सह-आरोपी माज निवासी त्रिलोकपुरी, दिल्ली, उम्र-19 वर्ष को गिरफ्तार किया गया और उनके पास से अपराध की संपत्ति/हथियार यानी एक देसी पिस्तौल और एक चाकू बरामद किया गया। आगे की जांच जारी है।

'हरियाणा में निवेश के लिए हर स्तर पर बेहतर माहौल', सीएम सैनी ने दक्षिण कोरिया के प्रतिनिधिमंडल से की मुलाकात

हरियाणा में निवेश के बेहतर माहौल पर चर्चा के लिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने दक्षिण कोरिया के प्रतिनिधिमंडल से गुरुवार को गुरुग्राम में मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल ने हरियाणा में स्टारलेक सिटी प्रोजेक्ट लाने की इच्छा जताई। मुख्यमंत्री ने हरसंभव सहयोग का आश्वासन दिया। बैठक में ऑटो टेक्सटाइल खाद्य प्रसंस्करण रियल एस्टेट सहित कई क्षेत्रों में निवेश पर चर्चा हुई।

गुरुग्राम। प्रदेश में निवेश की संभावना को लेकर दक्षिण कोरिया के एक प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के साथ स्थानीय पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में बृहस्पतिवार को बैठक की। इसमें प्रतिनिधिमंडल ने स्टारलेक सिटी प्रोजेक्ट को हरियाणा में भी लाने की इच्छा व्यक्त की।

इस पर मुख्यमंत्री ने सरकार की ओर से हरसंभव सहयोग करने का आश्वासन देते हुए कहा कि हरियाणा में निवेश के लिए हर स्तर पर बेहतर माहौल है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के आसपास कोरियाई कारोबार को बढ़ावा देने के लिए जमीन की पहचान करने की संभावनाएं भी सरकार तलाश कर सकती है। दक्षिण कोरिया के साथ मिलकर हरियाणा को नई दिशा और तकनीक के क्षेत्र में आगे बढ़ाने का प्रयास होगा।

'भारत और दक्षिण कोरिया की संस्कृति में बहुत सारी समानताएं'

बैठक में ऑटो, टेक्सटाइल्स, खाद्य प्रसंस्करण, रियल एस्टेट सहित कई सेक्टर में निवेश को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधिमंडल से कहा कि सिटी टू सिटी प्रोजेक्ट के लिए दक्षिण कोरिया का हरियाणा में स्वागत है। भारत और दक्षिण कोरिया की संस्कृति में बहुत सारी समानताएं हैं।

सांस्कृतिक और आध्यात्मिक रूप से दोनों देश एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। दक्षिण कोरिया और हरियाणा एक दूसरे के लिए बने हैं। हमारा लक्ष्य है कि हरियाणा के विदेश सहयोग विभाग के साथ मिलकर हम प्रदेश को अंतरराष्ट्रीय जगत पर एक नई पहचान दिलाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा गीता की भूमि है। कर्म की भूमि है और भगवान श्रीकृष्ण की धरा है।

'अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव में कोरिया बने पार्टनर देश'

हर वर्ष हरियाणा में अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव (International Gita Mahotsav) मनाया जाता है, जिसमें एक देश पार्टनर देश होता है। इस बार अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव में तंजानिया को पार्टनर कंट्री के रूप में जोड़ा है। उन्होंने कोरियन प्रतिनिधिमंडल से आग्रह करते हुए कहा कि दक्षिणी कोरिया के साथ बहुत पुराना नाता है।

वह चाहते हैं कि अगली बार अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव में कोरिया भी पार्टनर देश बने। उन्होंने प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन देते हुए कहा कि हरियाणा सरकार द्वारा कोरिया को पूरा सहयोग दिया जाएगा, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आने दी जाएगी।

हरेरा एवं विदेश सहयोग विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी रहे मौजूद

इससे पहले कोरियन प्रतिनिधिमंडल, कोरिया हेराल्ड और देवू कारपोरेशन के अध्यक्ष एवं कोरिया हाउसिंग बिल्डर्स एसोसिएशन के चेयरमैन जंग वोन जू ने कहा कि प्रतिनिधिमंडल में 21 रीजनल हेड शामिल हैं, जिनकी कोरिया की हाउसिंग इंडस्ट्री में लगभग 30 प्रतिशत हिस्सेदारी है। उन्होंने कहा कि उनकी एसोसिएशन द्वारा वियतनाम में स्टारलेक सिटी प्रोजेक्ट स्थापित किया जा रहा है।

वह चाहते हैं कि इस परियोजना को आगे बढ़ाते हुए भारत के हरियाणा में लाया जाए। कोरियन प्रतिनिधिमंडल द्वारा 22 कंपनियों के 70 डेलीगेट हरियाणा-कोरिया बिजनेस कनेक्ट में उपस्थित होंगे। बैठक में प्रदेश के विदेश सहयोग विभाग के मंत्री राव नरबीर सिंह और सहकारिता व पर्यटन मंत्री डा. अरविंद शर्मा के साथ ही हरेरा एवं विदेश

गुरुग्राम में 22 नवंबर को करीब 40 इलाकों में नहीं आएगा पानी, GMDA ने बताई वजह

गुरुग्राम। गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण (जीएमडीए) द्वारा कादीपुर चौक पर मास्टर वाटर सप्लाई पाइपलाइन की मरम्मत का कार्य किया जाएगा।

इस कारण वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बसई और सेक्टर-16 बूस्टिंग स्टेशन से 22 नवंबर को सुबह दस बजे से रात दस बजे तक 12 घंटे के लिए शटडाउन रहेगा, जिसके दौरान पानी की आपूर्ति बाधित रहेगी।

शहर के इन इलाकों में नहीं होगी पानी की सप्लाई

इस दौरान गांव बसई, कादीपुर, सिरहोल, चकरपुर, नाथूपुर, सिकंदरपुर, डूंडाहेड़ा और सुखराली, गोशाला बूस्टर, सेक्टर 37, 34, सिविल लाइंस, हंस एंकलेव, सेक्टर 10ए, सेक्टर 14, 16, 17, 18, सेक्टर 15- पार्ट एक, सेक्टर 15- पार्ट दो, सेक्टर 27, 28, 29, 30, 31, 32, 38, 39, 40, 41, 43, 45 और 46 (आंशिक), डीएलएफ फेज एक से चार।

लोगों को पानी को स्टोर करके रखने की दी गई सलाह

साइबर सिटी और उद्योग विहार फेज-एक, दो, तीन, चार और पांच, साउथ सिटी-वन, सुशांत लोक-दो और एमजी रोड, सूर्या विहार (डूंडाहेड़ा) में पानी की सप्लाई नहीं होगी। जीएमडीए की ओर से नागरिकों को सलाह दी गई है कि वे शुष्क स्थिति से बचने के लिए पानी को स्टोर करके रखें और बर्बादी न करें।

मार्च के महीने में भी रोकी गई थी पानी की आपूर्ति

इससे पहले गुरुग्राम शहर में इसी साल मार्च के महीने में करीब आधे शहर में 24 घंटे के लिए पेयजल की आपूर्ति बंद कर दी गई। गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण (जीएमडीए) द्वारा चंदू बुढ़ेड़ा के वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में रखरखाव का काम किये जाने के कारण पानी की सप्लाई रोकी गई थी।

इसके अलावा द्वारका एक्सप्रेस-वे (Dwarka Expressway) पर मास्टर जल आपूर्ति पाइपलाइन की शिफ्टिंग का कार्य भी प्राधिकरण ने किया था। इन दोनों कार्यों के चलते ही सुबह दस बजे से अगले दिन सुबह दस बजे तक चंदू बुढ़ेड़ा प्लांट से शहर के कई क्षेत्रों में पानी का आपूर्ति बंद कर दी गई थी।

इन क्षेत्रों में नहीं होगी पानी की आपूर्ति

इस दौरान जिन क्षेत्रों में पानी की आपूर्ति बाधित रही थी उनमें सेक्टर चार, पांच, सात, नौ, 11, 12, 81 से 115, दयानंद कालोनी, पुराना गुरुग्राम, लक्ष्मण विहार, छोटी माता बूस्टर और बूस्टिंग स्टेशन सेक्टर 51 (सेक्टर 42 से सेक्टर 74 तक और गांव बादशाहपुर) शामिल थी।

रेहड़ी-पटरी वालों के लिए गुड न्यूज, अब कम ब्याज दर पर मिलेगा कर्ज; फटाफट पढ़ें पूरी खबर

गुरुग्राम। नगर निगम गुरुग्राम के आयुक्त अशोक कुमार गर्ग ने कहा कि केंद्र सरकार की जनकल्याणकारी योजना पीएम स्वनिधि के तहत नगर निगम गुरुग्राम द्वारा 18 नवंबर से दो दिसंबर तक स्वनिधि भी-स्वाभिमान भी पखवाड़े का आयोजन किया जा रहा है।

इसके तहत सिविल अस्पताल के सामने स्थित निगम कार्यालय में प्रतिदिन सुबह दस बजे से शाम चार बजे तक शिविर का आयोजन हो रहा है। निगमायुक्त ने कहा कि पखवाड़े के तहत सभी बैंकर्स व संबंधित विभागाध्यक्षों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए जा चुके हैं कि वे निर्धारित समयावधि में पीएम स्व निधि योजना के तहत अभी तक लंबित आवेदनों में तत्पर कार्रवाई करते हुए लाभपात्रों के खातों में ऋण राशि भिजवाना सुनिश्चित कराएं।

इसके साथ ही भारत सरकार द्वारा संचालित सभी आठ योजनाओं का लाभ भी आवेदकों को दिलवाएं। इसके तहत विभिन्न स्थानों पर विशेष कैंपों का आयोजन किया जा रहा है।

आठ कल्याणकारी योजनाओं का मिलेगा लाभ

इस विशेष पखवाड़े के दौरान भारत सरकार की आठ कल्याणकारी योजनाओं का लाभ भी दिया जा रहा है। इनमें पीएम सुरक्षा बीमा योजना, पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना, पीएम श्रम योगी मानधन योजना, जननी सुरक्षा योजना, पीएम जन धन योजना, बीओसीडब्ल्यू के तहत पंजीकरण, वन नेशन वन राशन कार्ड योजना तथा पीएम मातृ वंदना योजना शामिल हैं।

पीएम आवास 2.0 योजना लॉन्च (PM Awas Yojana) होने के साथ ही बेघरों का घर का सपना जल्द पूरा होने वाला है। नगर निगम गुरुग्राम क्षेत्र के बेघर लोगों के लिए जल्द ऑनलाइन आवेदन लेना शुरू होगा।

नगर निगम गुरुग्राम के आयुक्त अशोक कुमार गर्ग ने बताया कि इस योजना में केवल बीपीएल ही नहीं, बल्कि दूसरे मध्यम वर्गीय परिवार भी रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे। इसके लिए केंद्र सरकार की तरफ से प्रदेश के सभी नगर निगमों को पत्र भेजा गया है। उन्होंने कहा कि जल्द ही आवेदन लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी।

हड़ताल में चैंबर खोलने वाले वकीलों और टाइपिस्टों पर एक्शन, देना होगा भारी जुर्माना

गाजियाबाद जिला कोर्ट में 29 अक्टूबर को वकीलों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में बृहस्पतिवार को भी वकीलों का धरना प्रदर्शन जारी रहा। बार एसोसिएशन ने बड़ा बयान देते हुए फैसला किया है कि शुक्रवार से सभी वकील अपने चैंबर को बंद रखेंगे। ऐसा नहीं करनें पर उन पर 5000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। टाइपिस्ट के बैठेपाए जाने पर दो हजार रुपये का जुर्माना होगा।

गाजियाबाद। जिला जज कोर्ट में 29 अक्टूबर को वकीलों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में बृहस्पतिवार को भी वकीलों का धरना जारी रहा। बार एसोसिएशन ने निर्णय लिया है कि शुक्रवार से सभी वकील अपना चैंबर बंद रखेंगे।

चैंबर खुला पाए जाने पर पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। टाइपिस्ट बैठे मिलने पर दो हजार रुपये का जुर्माना लगेगा। आंदोलन की रणनीति बनाने के लिए 13 सदस्यीय समन्वय समिति बनाई गई है। इसमें पूर्व बार अध्यक्ष और पूर्व बार सचिव शामिल हैं।

'अधिवक्ता अपने चैंबर की बजाय धरने पर जाएं'

बार एसोसिएशन ने आंदोलन को सफल बनाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। बार सचिव अमित नेहरा के मुताबिक कचहरी में आने वाले अधिवक्ता अपने चैंबर की बजाय धरने पर बैठें। उसके लिए चैंबर पूरी तरह से बंद रखना अनिवार्य किया गया है।

चैंबर खुला पाए जाने पर अधिवक्ता पर पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। बार एसोसिएशन द्वारा ऐसे अधिवक्ताओं की सदस्यता निरस्त करने की कार्रवाई की जाएगी। कचहरी परिसर में में ठेले वाले, टाइपिस्ट और स्टांप वेंडर भी काम नहीं करेंगे।

ऐसा करते पाए जाने पर दो हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। बृहस्पतिवार को बार एसोसिएशन के पूर्व सचिव लाल बहादुर सिंह, लोकेश कुमार शर्मा, विनोद कुमार वर्मा, संतोष जाटव, विजय गौड़, परविंदर नागर और विश्वास त्यागी धरना स्थल पर क्रमिक अनशन पर बैठे।

समन्वय समिति बनाएगी रणनीति

आंदोलन की रणनीति तैयार करने की जिम्मेदारी पूर्व अध्यक्ष राम अवतार गुप्ता, विजयपाल राठी ,राकेश त्यागी काकड़ा, अनिल पंडित ,मुनीश त्यागी, पूर्व सचिव अतुल्य शर्मा, विनोद वर्मा, नरेश चौधरी, सुंदर त्यागी, परविंदर नागर समेत वरिष्ठ अधिवक्ता औरंगजेब खान और जयवीर सिंह को सौंपी गई है।

जिला जज पर कार्रवाई की मांग

शनिवार को वकीलों की महापंचायत में कई जनपदों से आए बार एसोसिएशन पदाधिकारियों ने अपनी बात रखी थी। बार एसोसिएशन अध्यक्ष दीपक शर्मा के मुताबिक जिला जज पर कार्रवाई होने तक वकील उनकी कोर्ट में उपस्थित नहीं होंगे।

हड़ताल करने वालों की मांग है कि एक सप्ताह में न्यायाधीश का निलंबन, ट्रांसफर या बर्खास्तगी नहीं हुई तो हर बुधवार को पूरे प्रदेश में हड़ताल रहा करेगी। बता दें वकीलों का कहना है कि लाठीचार्ज करने वाले पुलिस अधिकारियों व पुलिस कर्मियों पर एफआईआर दर्ज कर कार्यवाही भी नहीं हुई है।

कानूनी दायरे में कैसे लाए जाएं चुनावी वायदे

चुनाव घोषणा पत्रों और आज के दृष्टि और संकल्प पत्रों में किए वायदों और उन्हें लागू किए जाने को लेकर ठोस शोध जरूरी है। लेकिन मोटे तौर पर इनमें दर्ज ज्यादातर वायदे पूरे हो ही नहीं पाते। इसलिए मतदाताओं के एक वर्ग अलग ढंग से सोचने लगा है।

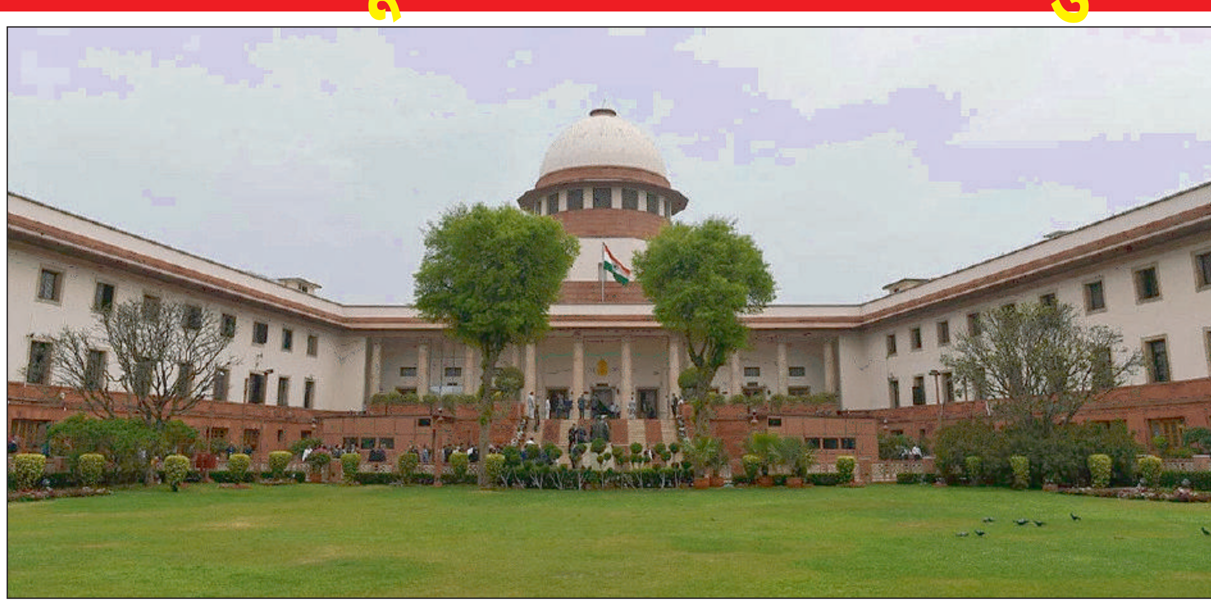

चुनाव घोषणा पत्रों में किए वायदों को पूरा न कर पाने को लेकर सत्ता में आने वाला हर राजनीतिक दल मतदाताओं और विपक्षी दलों के निशाने पर रहा है। मतदाताओं की बढ़ती जागरूकता के चलते इन आलोचनाओं से बचने के लिए राजनीतिक दलों ने अब चुनाव घोषणा पत्र जारी करना बंद कर दिया है। 2012 के उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों में उतरी कांग्रेस ने राज्य के लिए विजन डाक्युमेंट जारी किया। इसके बाद सभी दलों ने चुनाव घोषणा पत्र के शीर्षक को तकरीबन त्याग दिया। अब भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव के पहले संकल्प पत्र जारी करती है तो कांग्रेस अब गारंटियां देने लगी हैं। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में पार्टी ने पांच गारंटी देने का वादा किया। जो उसके लिए बहुत हिट रहा। अब पार्टियां गारंटी देती हैं, दृष्टि पत्र प्रस्तुत करती हैं और संकल्प पत्र प्रस्तुत करती हैं। गारंटी और संकल्प जैसे शब्द एक तरह से गवाह हैं कि राजनीतिक दलों के वायदों को लेकर मतदाताओं का एक बड़ा अब आलोचनात्मक रूख ही नहीं रखता है, बल्कि उन पर भरोसा भी नहीं करता।

घोषणा पत्र भले ही अब गारंटी या दृष्टि या संकल्प पत्र में तबदील हो गए हों, लेकिन अब भी उनकी साख नहीं बन पाई है। इसकी वजह यह है कि कई बार राजनीतिक दल वोटरों को लुभाने के चक्कर में ऐसे भी वायदे कर डालते हैं, जिन्हें पूरा कर पाना उनके लिए संभव नहीं होता। राजनीतिक दल भी जानते हैं कि संकल्प, दृष्टि या गारंटी पत्र में दिए वायदों को शत-प्रतिशत पूरा करना संभव नहीं है और अगर वे करते भी हैं तो सरकारी अर्थव्यवस्था का चरमरा सकती है। फिर वे वायदे करते हैं या कह सकते हैं कि सत्ता के लक्ष्य को लेकर चलने वाली मौजूदा राजनीति की यह मजबूरी भी है।

चुनाव घोषणा पत्रों और आज के दृष्टि और संकल्प पत्रों में किए वायदों और उन्हें लागू किए जाने को लेकर ठोस शोध जरूरी है। लेकिन मोटे तौर पर इनमें दर्ज ज्यादातर वायदे पूरे हो ही नहीं पाते। इसलिए मतदाताओं के एक वर्ग अलग ढंग से सोचने लगा है। मतदाताओं के एक वर्ग का मानना है कि चाहे जिस भी फ्रेम में चुनाव घोषणा पत्र जारी हों, उन्हें उपभोक्ता कानून के दायरे में लाना चाहिए। जिस तरह किसी प्रोडक्ट का निर्माता अपने प्रोडक्ट को लेकर गारंटी या वारंटी देता है, और जब वे पूरे नहीं होते तो उसके प्रोडक्ट खरीदने वाले उत्पादक के खिलाफ उचित फोरम में जाकर शिकायत दर्ज करा सकते हैं, उसी तरह चुनावी घोषणा पत्रों को लेकर भी कानून होने चाहिए। इस वर्ग का मानना है कि एक फोरम ऐसा भी होना चाहिए, जिसे कानूनी ताकत हासिल हो और जो चुनावी वायदाखिलाफी की सुनवाई कर सके।

चुनाव घोषणा पत्रों की स्थिति संविधान के नीति निर्देशक तत्वों की तरह ही है। नीति निर्देशक तत्व राज्य से लोक हित के तमाम कदम उठाने को लेकर उम्मीद तो करता है, लेकिन राज्य के लिए ऐसा करना अनिवार्य नहीं बनाता। नीति निर्देशक तत्वों के तहत राज्य या सरकार कदम नहीं उठाती तो किसी को भी किसी भी अदालत में इसकी शिकायत की ना तो अनुमति है और ना ही कोई अदालत ऐसी सुनवाई कर भी सकती है। चुनाव घोषणा पत्रों की भी कुछ ऐसी ही स्थिति है।

हालांकि ऐसा नहीं है कि चुनाव घोषणा पत्रों को लेकर अदालतों के सामने सवाल नहीं उठे।

चुनाव घोषणा पत्र को लेकर दाखिल एक याचिका पर सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने 5 जुलाई 2013 को अपना फैसला सुनाया था। एस. सुब्रमण्यम बालाजी बनाम तमिलनाडु सरकार और अन्य के मामले में देश की सबसे बड़ी अदालत ने चुनाव आयोग को सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों की सलाह से चुनावी घोषणापत्र के संबंध में दिशा-निर्देश तैयार करने का निर्देश दिया था। इस फैसले में कोर्ट ने कहा था,

- चुनाव आयोग, राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के बीच समान अवसर सुनिश्चित करने और यह देखने के लिए कि चुनाव प्रक्रिया की पवित्रता पर आंच ना आए, घोषणापत्र को लेकर निर्देश जारी करे। जैसे आयोग आदर्श आचार संहिता के निर्देश जारी करता है।

- आयोग के पास संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए ऐसे आदेश दे सकता है।

- अदालत को पता है कि सामान्यतया राजनीतिक दल मतदान के पहले चुनाव घोषणा पत्र जारी करते हैं, ऐसी स्थिति में चुनाव आयोग के पास किसी भी कार्य को रेगुलेट करने का अधिकार नहीं होता है। फिर भी, घोषणा पत्र को लेकर अपवाद बनाया जा सकता है, क्योंकि चुनावी घोषणापत्र का उद्देश्य सीधे चुनाव प्रक्रिया से जुड़ा होता है।

इसके बाद चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों से विचार-विमर्श के बाद साल 2015 में चुनाव घोषणा पत्र को लेकर गाइड-लाइन जारी की थी। इसके अनुसार,

- चुनाव घोषणापत्र में संवैधानिक आदर्शों और सिद्धांतों से इतर कुछ भी नहीं होगा और यह आदर्श आचार संहिता के अन्य प्रावधानों की भावना के अनुरूप होगा।

- संविधान में निहित राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के तहत राज्यों को नागरिकों के लिए विभिन्न कल्याणकारी उपाय करने के आदेश हैं, इसलिए चुनावी घोषणा पत्रों में ऐसे कल्याणकारी उपायों के वायदे पर कोई आपत्ति नहीं हो सकती। हालांकि, राजनीतिक दलों को ऐसे वादे करने से बचना चाहिए, जिनसे चुनाव प्रक्रिया की शुचिता पर असर पड़ सकता है या मतदाताओं पर उनके मताधिकार का प्रयोग करने में अनुचित प्रभाव पड़ने की आशंका हो।

- पारदर्शिता, समान अवसर और वायदों की विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए अपेक्षा की जाती है कि घोषणापत्र में किए गए वादे स्पष्ट हों और इसे पूरा करने के लिए वित्तीय संसाधन कैसे जुटाए जाएंगे, इसकी भी जानकारी हो। मतदाताओं का भरोसा उन्हीं वादों पर हासिल करना चाहिए, जिन्हें पूरा किया जाना संभव हो।

दुर्भाग्यवश चुनाव आयोग की गाइड लाइन भी बहुत प्रभावी नहीं हो पा रही है। हवा-हवाई वायदे भी खूब किए जा रहे हैं। इनमें रोजगार और नौकरियों को लेकर की जाने वाले वायदे पहले नंबर पर हैं। कल्याणकारी योजनाएं भी इसी कैटेगरी में आती हैं। लेकिन बहुत कम राजनीतिक दल ऐसे हैं, जो कल्याणकारी योजनाओं से संबंधि वायदे करते वक्त उन्हें पूरा करने के लिए जुटाई जाने वाली रकम और उनके स्रोत और तरीकों की जानकारी नहीं देते। मतदाताओं की बढ़ती जागरूकता का दबाव ही है कि कल्याणकारी योजनाओं को लेकर वायदे खूब हो रहे और हर राजनीतिक दल अपने ढंग से लागू भी कर रहा है। भले ही राज्य के खजाने की हालत खस्ता ही क्यों ना हो जाए। लेकिन यह भी सच है कि उस पर खर्च होने वाले फंड के स्रोत को लेकर जानकारी नहीं दी जा रही। साफ है कि चुनाव आयोग की गाइड लाइन इस संदर्भ में नाकाम लग रही है।

मौजूदा आर्थिकी में लाभ पर जोर है, रोजगार का सवाल लगातार पीछे छूटता जा रहा है। इसे उलटबांसी ही कहेंगे कि राजनीतिक दल इसी आर्थिकी को आगे बढ़ाने के साथ ही हवाई वायदों की फेहरिस्त भी जारी करते रहते हैं। चूंकि वोटरों के हाथ बंधे हुए हैं, इसलिए वे भी सवाल उठाने से ज्यादा कुछ नहीं कर सकते।

यहां पर याद आता है, संविधानसभा के सदस्य अनंत शयनम अयंगार के वे शब्द, जो उन्होंने नीति निर्देशक तत्वों पर अदालती चाबुक के तर्क के विरोध में दिया था। तब उन्होंने जनता की ताकत पर भरोसा जताते हुए कहा था कि पांच साल में एक बार जब चुनाव होंगे, तब मतदाताओं के लिए यह विकल्प होगा कि वे उन्हीं लोगों को न चुनें जो जनता की राय से अलग हैं।

लेकिन क्या ऐसा हो पा रहा है? निश्चित तौर पर इसका जवाब ना में है। ऐसे में सवाल उठता है कि फिर हवाई वायदे ना हों और जो किए जाएं, उन्हें लागू कैसे किया जाए? निश्चित तौर पर इसके लिए एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग को भी आगे आना होगा। मौजूदा राजनीतिक व्यवस्था इस आत्म नियंत्रण करने से रही। चूंकि वायदों में ही सबका फायदा है, इसलिए कोई भी दल बिल्ली के गले घंटी बांधने के लिए आगे आने की हिम्मत नहीं दिखा पाएगा।

- :सौजन्य :-
ईवी ड्राइव द फ्यूचर
EV
Drive the Future

प्योर ईवी ने मध्य पूर्व और अफ्रीका में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी का विस्तार करने के लिए अरवा इलेक्ट्रिक के साथ की साझेदारी

परिवहन विशेष न्यूज

भारतीय इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन निर्माता, प्योर ईवी ने मध्य पूर्व और अफ्रीकी बाजारों में इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिलों की आपूर्ति के लिए यूएई स्थित अरवा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मैन्युफैक्चरिंग (क्लैरियन इन्वेस्टमेंट की एक सहायक कंपनी) के साथ साझेदारी की है। इस समझौते में अगले दो वर्षों में अपने प्रमुख मॉडल, इकोड्रायफ्ट और ईट्रिस्ट एक्स की 50,000 इकाइयों की शुरुआती डिलीवरी शामिल है, जिसके बाद सालाना 60,000 इकाइयों तक पहुंचने की योजना है।

यह साझेदारी प्योर ईवी के मिशन के अनुरूप है, जिसका उद्देश्य टिकाऊ गतिशीलता को बढ़ावा देना और उभरते बाजारों में प्रवेश करना है, जहाँ इलेक्ट्रिक वाहन तेजी से लोकप्रिय हो रहे हैं। सहयोग के बारे में बोलते हुए, प्योर ईवी के संस्थापक और प्रबंध निदेशक डॉ निशांत डोंगरी ने कहा, ₹इस साझेदारी का उद्देश्य न केवल बिक्री को बढ़ाना है, बल्कि उन क्षेत्रों में टिकाऊ गतिशीलता समाधानों को बढ़ावा देना भी है, जहाँ इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिलें तेजी से लोकप्रिय हो रही हैं। उन्होंने कहा कि यह मध्य पूर्व और अफ्रीकी बाजारों में कंपनी के पदचिह्न का विस्तार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।₹

यूएई इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन बाजार का 2024 से 2031 तक 9.11% की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर) से बढ़ने का अनुमान है, जो 2023 में 29.97 मिलियन अमरीकी डॉलर से बढ़कर 2031 तक 60.19 मिलियन अमरीकी डॉलर हो जाएगा। ईंधन की बढ़ती कीमतें, वाहन दक्षता में सुधार और सरकारी प्रोत्साहन क्षेत्र में इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिलों की मांग को बढ़ा रहे हैं।

मोटरसाइकिलों की आपूर्ति के अलावा प्योर ईवी, अरवा इलेक्ट्रिक के लिए एक रणनीतिक प्रौद्योगिकी साझेदार के रूप में काम करेगा तथा वितरण प्रक्रिया के दौरान तकनीकी विशेषज्ञता और सहायता प्रदान करेगा।

प्योर ईवी मोटरसाइकिलें एकमात्र भारतीय इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल हैं जिन्हें आवश्यक विनियामक अनुमोदन के बाद मध्य पूर्व में उपयोग के लिए अनुमोदित किया गया है। यह उपलब्धि इस क्षेत्र की संधारणीय परिवहन की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए प्योर ईवी की तत्परता को रेखांकित करती है।

आईआईटी हैदराबाद के आई-टीआईसी में विकसित प्योर ईवी के 75,000 से ज़्यादा ईवी उपयोगकर्ता हैं और पूरे भारत में 70 डीलरशिप का नेटवर्क है। कंपनी ने 120 से ज़्यादा पेटेंट के साथ बेहतरीन उत्पाद विकसित किए हैं। कई प्योर ईवी मोटरसाइकिलें 30,000 किलोमीटर से ज़्यादा माइलेज देती हैं, जिससे कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने में काफ़ी मदद मिलती है।

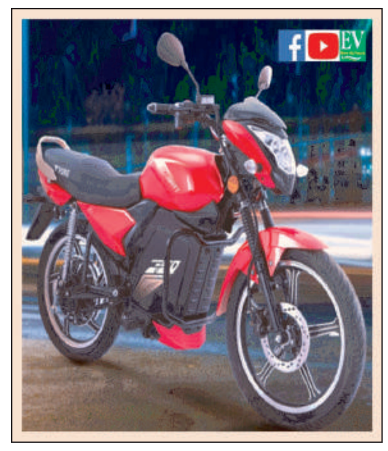

19 दिसंबर को ईवी उद्योग की स्थिरता पर कैटालिस्ट सम्मेलन के साथ इलेक्ट्रिक नवाचार के लिए जुड़ें, सहयोग करें और बदलाव लाएं

परिवहन विशेष न्यूज

ईवीएक्सपो का मुख्य उद्देश्य एक एकीकृत मंच बनाना है, जहां सरकारी और गैर-सरकारी संस्थाएं, उद्योग संघ, राज्य सरकारें, स्वायत्त निकाय, ईवी निर्माता, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदाता, अनुसंधान और विकास संगठन, बैटरी प्रबंधन प्रणाली डेवलपर्स, केंद्रीय और राज्य अक्षय ऊर्जा विभाग और संबंधित संस्थान और साथ ही खरीदार, विक्रेता, प्रशिक्षण केंद्र, निवेशक और कॉर्पोरेट पेशेवर एक साथ आते हैं। इस सहयोगात्मक स्थान का उद्देश्य भारत में ईवी उद्योग के विकास को सक्षम बनाना है।

ईवीएक्सपो कॉन्फ्रेंस 2024 में इलेक्ट्रिक वाहन परिदृश्य को आगे बढ़ाने के लिए समर्पित उद्योग विशेषज्ञों, नवोन्मेषकों और नीति निर्माताओं को एक साथ लाना है। सम्मेलन की शुरुआत ईवी अनुसंधान और विकास में सहयोग और निवेश के अवसरों पर जोर देने के साथ होगी, जिसमें बुनियादी ढांचे की जरूरतों और नियामक बाधाओं सहित अत्याधुनिक तकनीकों को एकीकृत करने की चुनौतियों को स्वीकार किया जाएगा।

ईवीएक्सपो कॉन्फ्रेंस 2024 में आवश्यक कौशल आवश्यकताओं पर प्रकाश डाला जाएगा, जिसमें वर्तमान श्रमिकों को बेहतर कौशल प्रदान करने और नई प्रतिभाओं को तैयार करने के लिए शिक्षा और उद्योग साझेदारी पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। सहयोग और साझेदारी पर चर्चा सरकारी नीतियों का लाभ उठाने, रणनीतिक गठबंधन बनाने और उपभोक्ताओं को ईवी लाभों के बारे में शिक्षित करने के महत्व को रेखांकित करेगी। ईवी के लिए अवसरों का मुद्रीकरण करने, वित्तपोषण में आने वाली बाधाओं को दूर करने, समान वितरण और वित्तपोषण प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने में तकनीकी नवाचारों की भूमिका के लिए वित्तीय रणनीतियों पर चर्चा की जाएगी।

ईवीएक्सपो कॉन्फ्रेंस 2024 इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग तकनीक और बुनियादी ढांचे पर केंद्रित एक राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय शिखर सम्मेलन है। यह ईवी उद्योग के विशेषज्ञों, ईवी चार्जिंग उपकरण निर्माताओं और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स को समर्पित है, जिसका उद्देश्य नई पीढ़ी के इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए आवश्यक विद्युत बुनियादी ढांचे और चार्ज प्वाइंट स्थापित करना है। यह कॉन्फ्रेंस ईवी चार्जिंग तकनीक और इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र के भीतर उद्योग की चुनौतियों, अवसरों और उच्च स्तर पर नेटवर्किंग पर चर्चा करने के लिए एक मंच प्रदान करता है। यह भारत में ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए विचारों का आदान-प्रदान करने और ज्ञान साझा करने के लिए एक खुले मंच के रूप में भी कार्य करता है। इसका मुख्य उद्देश्य भारत को इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग तकनीक और इंफ्रास्ट्रक्चर में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी के रूप में स्थापित करना है।

अनीश शाह का कहना है कि इलेक्ट्रिक 3-व्हीलर्स को वित्त वर्ष 26 के बाद सब्सिडी की जरूरत नहीं होगी

परिवहन विशेष न्यूज

फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अध्यक्ष अनीश शाह ने कहा कि इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर उद्योग को वित्तीय वर्ष 2026 के बाद सरकारी सब्सिडी पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा, क्योंकि यह आत्मनिर्भरता के स्तर पर पहुंच जाएगा।

शाह, जो महिंद्रा समूह के सीईओ और प्रबंध निदेशक भी हैं, ने कहा, ₹मात्रा और पैमाने में वृद्धि के कारण सब्सिडी कम हो गई है, जिससे लागत कम हो गई है। यह सब्सिडी वित्त वर्ष 26 के अंत तक जारी रहेगी। वित्त वर्ष 26 के बाद इसकी आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि हम पैमाने के उस स्तर पर पहुंच जाएंगे जहां उद्योग खुद को वित्तपोषित कर सकता है।"

शाह की यह टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब दो वर्षीय 10,900 करोड़ रुपये की पीएम ई-ड्राइव योजना की शुरुआत फेम-2 की तुलना में प्रति वाहन कम सब्सिडी के साथ हुई है तथा दूसरे वर्ष में सब्सिडी आधी कर दी जाएगी।

वर्तमान में इलेक्ट्रिक दोपहिया, तिपहिया वाहन, बसें, ट्रक और एम्बुलेंस पीएम ई-ड्राइव योजना से मांग प्रोत्साहन के लिए पात्र हैं।

इलेक्ट्रिक रिक्शा को वर्तमान में 5,000 रुपये प्रति किलोवाट घंटा की सब्सिडी मिलती है, जिसकी अधिकतम सीमा 25,000 रुपये प्रति वाहन है, जबकि यात्री और कार्गो इलेक्ट्रिक ऑटो को 5,000 रुपये प्रति किलोवाट घंटा की सब्सिडी मिलती है, जिसकी अधिकतम सीमा 50,000 रुपये प्रति वाहन है। अप्रैल 2025 से सब्सिडी आधी कर दी जाएगी।

मीडिया सूत्रों के अनुसार सरकार वित्तीय वर्ष 2027 से इलेक्ट्रिक दोपहिया और तिपहिया वाहनों की खरीद पर मांग प्रोत्साहन को समाप्त कर सकती है।

वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों का मानना है कि 2026 से केवल उन क्षेत्रों को मांग प्रोत्साहन की आवश्यकता होगी, जो 10% इलेक्ट्रिक वाहन प्रवेश तक नहीं पहुंचे हैं।

सरकार ने इस साल पीएम ई-ड्राइव योजना के तहत 80,546 इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर्स को प्रोत्साहित करने का वार्षिक लक्ष्य हासिल कर लिया है। भारी उद्योग मंत्रालय की वेबसाइट के अनुसार इस योजना के तहत 7 नवंबर तक ओईएम द्वारा 79,974 इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर्स की बिक्री की सूचना दी गई थी।

वेबसाइट पर कहा गया है, ₹80,546 की लक्षित संख्या से अधिक बेचे और पंजीकृत वाहन वित्त वर्ष 24-25 में प्रोत्साहन के लिए पात्र नहीं होंगे।₹ यह स्पष्ट नहीं है कि उपभोक्ता चालू वित्त वर्ष में की गई इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर खरीद पर प्रोत्साहन प्राप्त करने के पात्र बने रहेंगे या उन्हें सब्सिडी प्राप्त करने के लिए अगले वर्ष तक इंतजार करना होगा।

इससे पहले सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने भी कहा था कि उन्हें लगता है कि इलेक्ट्रिक वाहनों को सब्सिडी की जरूरत नहीं है, क्योंकि वाहनों की संख्या बढ़ने वाली है और इन वाहनों की लागत कम होने वाली है।

वर्तमान में भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग अभी शुरुआती चरण में है तथा कुल प्रवेश दर करीब 7% है। पिछले वित्तीय वर्ष में इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री में दोपहिया वाहनों की हिस्सेदारी 56% थी, जबकि तिपहिया वाहनों की हिस्सेदारी 38% थी। किफायतीपन और सीमित चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इलेक्ट्रिक वाहनों को तेजी से अपनाने में बड़ी बाधा रहे हैं।

पीएमओ सलाहकार का कहना है कि 4 व्हीलर में ईवी अपनाने के लिए आवश्यकता है बेहतर उत्पादों की

परिवहन विशेष न्यूज

ऐसे समय में जब भारत का यात्री वाहन उद्योग इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने में संघर्ष कर रहा है, प्रधानमंत्री कार्यालय के सलाहकार तरुण कपूर ने ऑटोमोबाइल उद्योग से चार पहिया वाहनों में बदलाव को तेज करने के लिए अधिक आकर्षक उत्पाद लाने का आग्रह किया।

कपूर ने मंगलवार, 19 नवंबर को फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (फिक्की) द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में बोलते हुए कहा, ₹मेरा मानना है कि चार पहिया वाहनों के मामले में उद्योग की भूमिका सरकार से कहीं अधिक बड़ी है, क्योंकि हमें अधिक उत्पादों, बेहतर उत्पादों और अधिक प्रचार की आवश्यकता है।₹

यात्री वाहन खंड में इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने की गति धीमी रही है। ईवी प्रवेश स्तर कम एकल अंकों में है। इसके विपरीत पिछले साल बेचे गए कुल इलेक्ट्रिक वाहनों में दोपहिया वाहनों की हिस्सेदारी 56% थी, जबकि तिपहिया वाहनों की हिस्सेदारी 38% थी।

इलेक्ट्रिक वाहनों को तेजी से अपनाने में किफ़ायतीपन और सीमित चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ी बाधाएँ रही हैं। जबकि फेम योजना के तहत दिए गए मांग प्रोत्साहन और

उसके बाद पीएम ई-ड्राइव ने इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

जबकि टैक्सियों जैसे बेड़े में इस्तेमाल की जाने वाली कारें फेम योजना का हिस्सा थीं, नएपीएम ई-ड्राइव ने उन्हें बाहर रखा है। कपूर ने कहा कि सरकार देश में चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने पर अधिक ध्यान देने के साथ चार पहिया वाहनों में इलेक्ट्रिक वाहन अपनाने को बढ़ावा देने के लिए उत्सुक है।

उन्होंने कहा, ₹सरकार की ओर से पीएम ई-ड्राइव में चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत बड़ा खर्च किया गया है।₹ पीएम ई-ड्राइव योजना भारत के चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को विकसित करने पर बहुत जोर देती है।

इस योजना में चार्जिंग अवसंरचना के लिए परिव्यय को दोगुने से भी अधिक बढ़ाकर 2,000 करोड़ रुपये कर दिया गया है, जिसमें चार पहिया वाहनों के लिए 22,100 फास्ट चार्जरों की स्थापना भी शामिल है।

उन्होंने कहा, ₹लेकिन उत्पादों और अधिक विकल्पों के साथ अधिक ग्राहक संतुष्टि प्राप्त करने के मामले में उद्योग को बहुत बड़ी भूमिका की योजना बनानी होगी।₹

बैटरी और चार्जिंग सेवाओं पर कराधान पर विचार करने की आवश्यकता पीएमओ सलाहकार ने यह भी कहा कि इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए बैटरी और चार्जिंग स्टेशनों पर कराधान पर विचार करने की आवश्यकता है।

कपूर ने कहा, ₹हमें शायद बैटरी पर कर लगाने पर विचार करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति चार्जिंग को सेवा के रूप में उपलब्ध कराता है, तो जीएसटी अधिक हो जाता है।₹

इलेक्ट्रिक वाहनों पर जीएसटी घटाकर 5% कर दिया गया है, जबकि इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए बैटरी और चार्जिंग सेवाओं पर जीएसटी 18% ही रहेगा। उद्योग सरकार पर दबाव बना रहा है कि इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग को और अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए इन पर जीएसटी घटाकर 5% किया जाए।

उन्होंने कहा, ₹हम समझते हैं कि कराधान एक बड़ा मुद्दा है। हमें सभी पहलुओं, सभी स्तरों पर विचार करना होगा ताकि उद्योग व्यवहार्य बना रहे और फिर लंबे समय में यह प्रतिस्पर्धी भी बना रहे।₹

उन्होंने कहा, ₹इस मामले को पहले ही संबंधित प्राधिकरण को बता दिया गया है। जीएसटी से जुड़े फैसले जीएसटी परिषद के माध्यम से लिए जाते हैं। सरकार इस पर कोई सीधा फैसला नहीं लेती है।"

हयुंडई ईवी लॉन्चिंग डेट हो गई कंफर्म, भारत में जनवरी 2025 में मारेगी एंट्री

हुंडई क्रेटा ईवी किस महीने भारत में लॉन्च होगी यह कंफर्म हो गया है। भारत में हुंडई की सबसे सस्ती इलेक्ट्रिक कार हो सकती है। यह फेसलिफ्ट क्रेटा पर बेस्ड होगी। इसमें क्रेटा ICE के समान ही फीचर्स देखने के लिए मिलेंगे। इसमें छह एयरबैग और ADAS फीचर मिल सकता है। इसकी कीमत 20 लाख रुपये से शुरू हो सकती है।

नई दिल्ली। को भारत की सड़कों पर टेस्टिंग के दौरान स्पॉट किया जा चुका है। जिसे लेकर कयास लगाए जा रहे थे कि हुंडई क्रेटा ईवी को जल्द भी भारत में लॉन्च किया जाएगा। वहीं, अब इसकी लॉन्चिंग डेट कंफर्म हो गई है। हाल ही में हुंडई इंडिया के मुख्य परिचालन अधिकारी (सीओओ) तरुण गर्ग ने एक निवेशक बैठक में इसकी लॉन्चिंग का खुलासा किया। उनके मुताबिक, हुंडई क्रेटा ईवी को जनवरी 2025 में लॉन्च किया जाएगा। आइए जानते हैं कि इसमें क्या कुछ खास होने वाला है।

कैसा होगा डिजाइन

क्रेटा ईवी को टेस्टिंग के दौरान कई बार देखा जा चुका है। इसका डिजाइन क्रेटा ICE जैसा देखने के लिए मिला है। इन टेस्ट म्यूल्स में कनेक्टेड LED DRL सेटअप के साथ समान हेडलाइट डिजाइन देखने के लिए मिला है। साथ ही इसके टेल लाइट का डिजाइन भी ICE क्रेटा जैसी ही होगा।

इसमें ब्लैंक्स-ऑफ ग्रिल और ट्वीक्ड फ्रंट और रियर बंपर देखने के लिए मिलेगा। इसमें एयरोडायनामिक रूप से डिजाइन किए गए अलॉय व्हील भी होंगे, जो 17-इंच के आकार के हो सकता है।

कैसा होगा इंटीरियर

क्रेटा ईवी में डुअल-टोन इंटीरियर और डुअल-स्क्रीन डिस्प्ले देखने के लिए मिलेगा। इसके अलावा, इसमें नया 3-स्पोक स्टीयरिंग व्हील और स्टीयरिंग व्हील के पीछे ड्राइव सिलेक्टर देखने के लिए मिलेगा, जो आपने Ioniq 5 में देख चुके हैं।

फीचर्स और सेफ्टी

जैसा की स्पाइ शॉट्स में देखा जा चुका है कि क्रेटा ईवी में 10.25-इंच टचस्क्रीन और 10.25-इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले होगा। इसमें अल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल, पैनोरमिक सनरूफ, वायरलेस फोन चार्जर और वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें भी देखने के लिए मिलेंगी।

फिक्की की 97वीं वार्षिक आम बैठक में स्थिरता और जलवायु कार्रवाई को गति

परिवहन विशेष न्यूज

केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने फिक्की की 97वीं वार्षिक आम बैठक को संबोधित करते हुए इस बात पर जोर दिया कि उद्योगों को शेयरधारकों के हितों को व्यापक हितधारक जिम्मेदारियों के साथ संतुलित करने की आवश्यकता है। उन्होंने जलवायु परिवर्तन, ऊर्जा उपयोग और उपभोग पैटर्न को कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी में शामिल करने के महत्व को रेखांकित किया।

मंत्री ने दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए सरकार के प्रयासों को रेखांकित किया, खासकर नवंबर की चुनौतीपूर्ण जलवायु परिस्थितियों के दौरान। उन्होंने औद्योगिक इकाइयों के स्वच्छ ईंधन में बदलाव पर प्रकाश डाला, जिसमें दिल्ली में 7,759 इकाइयों में से 7,442 ने स्वच्छ विकल्प अपनाए हैं। इसी तरह हरियाणा ने 3,141 इकाइयों में से 2,954 को, उत्तर प्रदेश ने 2,273 इकाइयों में से 2,183 को और राजस्थान ने 522 इकाइयों में से 482 को बदल दिया है। इसके अतिरिक्त वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए बीएस-VI ईंधन मानकों और SATAT (सस्ती परिवहन की दिशा में टिकाऊ विकल्प) पहल को बढ़ावा दिया जा रहा है।

केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने ग्रीन क्रेडिट पहल के बारे में भी बात की, जिसने अपने पहले 100 दिनों में उल्लेखनीय परिणाम हासिल किए हैं। कुल 22 सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों ने लगभग 47,937 हेक्टेयर भूमि को कवर करने के लिए ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम (जीसीपी) पोर्टल का उपयोग किया है। यह पहल जो सरकार के पर्यावरण एजेंडे के अनुरूप है, का लक्ष्य बाजार आधारित तंत्र का उपयोग करके भारत के हरित आवरण को 33% तक बढ़ाना है।

स्वच्छ औद्योगिक प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए मंत्रालय ने दस अपशिष्ट श्रेणियों के लिए परिपत्र अर्थव्यवस्था पहल के तहत विनियामक ढांचे की शुरुआत की है। इनमें लिथियम-आयन बैटरी, ई-कचरा, खतरनाक औद्योगिक अपशिष्ट, स्क्रैप धातु, टायर, जीवन के अंत में वाहन, जिप्सम, प्रयुक्त तेल, नगरपालिका ठोस अपशिष्ट और सौर पैनल शामिल हैं। यादव ने इस बात पर जोर दिया कि संसाधनों के सावधानीपूर्वक उपयोग के माध्यम से स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए परिपत्र अर्थव्यवस्था महत्वपूर्ण है।

फिक्की के अध्यक्ष डॉ. अनीश शाह ने 2030 तक 50% नवीकरणीय ऊर्जा प्राप्त करने के भारत के लक्ष्य पर प्रकाश डाला और कहा कि नवीकरणीय ऊर्जा वर्तमान में जीवाश्म ईंधन की लागत के 40% पर उत्पादित की जाती है, जो देश की ऊर्जा परिदृश्य को बदलने में प्रगति को दर्शाता है। उन्होंने बाढ़ और हीटवेव जैसी बढ़ती वैश्विक पर्यावरणीय चुनौतियों के समय में जलवायु कार्रवाई में भारत के नेतृत्व को भी स्वीकार किया।

फिक्की के भावी अध्यक्ष हर्षवर्धन अग्रवाल ने कहा कि स्थिरता, जैव विविधता और नेट जीरो की ओर संक्रमण के लिए सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि भारतीय व्यवसाय हरित प्रौद्योगिकियों में निवेश कर रहे हैं और सरकार के स्थिरता ढांचे के साथ तालमेल बिठाते हुए कम कार्बन, समावेशी विकास पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं।

जेईई मेन के लिए ड्रॉप ईयर लेना जोखिम भरा हो सकता है?

विजय गर्ग

जेईई के 15% अभ्यर्थी ड्रॉप ईयर लेते हैं आईआईटी में प्रवेश करने वाले 40-45% छात्र ड्रॉपर होते हैं जोखिमों में तनाव और खोया हुआ शैक्षणिक वर्ष शामिल है हर साल, बड़ी संख्या में छात्र संयुक्त प्रवेश परीक्षा (जेईई) मेन की तैयारी के लिए ड्रॉप लेने पर विचार करते हैं, जिसका लक्ष्य अपने प्रदर्शन में सुधार करना और शीर्ष स्तरीय इंजीनियरिंग कॉलेजों में सुरक्षित प्रवेश करना है। जेईई के लगभग 15 प्रतिशत अभ्यर्थी ड्रॉपर हैं, और जो लोग भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) में प्रवेश पाते हैं, उनमें से अनुमानित 40-45 प्रतिशत ऐसे छात्र हैं जिन्होंने तैयारी के लिए एक अतिरिक्त वर्ष लिया। हालाँकि, इस वर्ष गिरावट का निर्णय अपनी चुनौतियों और निहितार्थों से रहित नहीं है। छात्रों को ड्रॉप ईयर क्यों लगता है? एक वर्ष में ड्रॉप लेने की प्रेरणाएँ छात्रों के बीच व्यापक रूप से भिन्न होती हैं। कुछ सामान्य कारणों में शामिल हैंः वांछित रैंक या कॉलेज नहीं मिलनाः कई छात्रों को लगता है कि वे एक और केंद्रित प्रयास के साथ बेहतर रैंक हासिल कर सकते हैं या अपने सपनों के इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रवेश पा सकते हैं। पर्याप्त तैयारी का अभावः खराब समय प्रबंधन, अधूरा पाठ्यक्रम, या अवधारणाओं की कमजोर समझ अक्सर छात्रों को दूसरे मौके की तलाश में ले जाती है। बोर्ड परीक्षा और जेईई की तैयारी को संतुलित करनाः बोर्ड परीक्षा और जेईई की तैयारी का दोहरा दबाव भारी पड़ सकता है, जिससे कुछ छात्र जेईई के लिए तैयार नहीं रह पाते हैं। पहला प्रयास सफल नहीं रहाः जो छात्र अपने पहले प्रयास में उत्तीर्ण नहीं हो सके, वे अक्सर ड्रॉप ईयर को सफल होने के दूसरे अवसर के रूप में देखते हैं। बेहतर कोचिंग या परामर्शः कुछ उम्मीदवारों को लगता है कि उनकी प्रारंभिक तैयारी में उचित मार्गदर्शन और संसाधनों का अभाव था, जिससे उन्हें अधिक संरचित कोचिंग का विकल्प चुनने के लिए प्रेरित किया गया। अन्य प्रेरणाओं में प्रारंभिक तैयारी के दौरान आत्मविश्वास, स्वास्थ्य या व्यक्तिगत मुद्दे और कंप्यूटर विज्ञान या इलेक्ट्रॉनिक्स जैसी विशिष्ट इंजीनियरिंग शाखा को सुरक्षित करने की आकांक्षा शामिल है। ड्रॉप ईयर लेने के फायदे एक ड्रॉप वर्ष छात्रों को पूरी तरह से जेईई की तैयारी पर ध्यान केंद्रित करने की अनुमति देता है, कमजोर क्षेत्रों को संबोधित करने, जटिल अवधारणाओं में महारत हासिल करने और मॉक परीक्षाओं के माध्यम से रणनीतियों को परिष्कृत करने के लिए अतिरिक्त समय प्रदान करता है। ₹एक गिरावट वाले वर्ष के दौरान तैयारी में आपके द्वारा किया गया निवेश तेजी से रिटर्न दे सकता है, खासकर शीर्ष इंजीनियरिंग कॉलेजों से स्नातक होने के बाद उपलब्ध प्लेसमेंट पैकेज और करियर के अवसरों के साथ,₹ मुफ़्त यूट्यूब सामग्री और संरचित ऑनलाइन पाठ्यक्रमों सहित किफायती और उच्च गुणवत्ता वाले संसाधनों की उपलब्धता ने ड्रॉपर्स के लिए वित्तीय बोझ को कम कर दिया है, जिससे सभी के लिए केंद्रित तैयारी सुलभ हो गई है। चुनौतियाँ और कमियाँ जबकि एक ड्रॉप वर्ष के लाभ आकर्षक हैं, छात्रों को इसकी चुनौतियों पर भी विचार करना चाहिए। बढ़ा हुआ दबाव और तनावः दूसरे प्रयास में बेहतर प्रदर्शन करने की उम्मीद चिंता को बढ़ा सकती है। एक शैक्षणिक वर्ष का नुकसानः एक वर्ष छोड़ने से कॉलेज स्नातक और कार्यबल में प्रवेश में देरी होती है, जिससे छात्र अपने साथियों से पीछे रह जाते हैं। परिणामों की अनिश्चितताः एक गिरावट वाले वर्ष के बाद सफलता की गारंटी नहीं है, जिससे निराशा हो सकती है। बर्नआउट का जोखिमः एक ही सामग्री को दूसरे वर्ष तक दोहराने से थकान और प्रेरणा कम हो सकती है। छूटे अवसरः कुछ छात्र अपने पहले प्रयास में अच्छे कॉलेज प्रस्तावों को नज़रअंदाज कर सकते हैं, जो बाद में उपलब्ध नहीं हो सकते हैं। जेईई का प्रतिस्पर्धी परिदृश्य भी हर साल विकसित होता है, जिसमें परीक्षा पैटर्न, कटऑफ और प्रतिस्पर्धा के स्तर में बदलाव से अनिश्चितता बढ़ती है। एक बूंद वर्ष का मनोवैज्ञानिक प्रभाव एक वर्ष में गिरावट एक छात्र पर काफी प्रभाव डाल सकती हैमानसिक स्वास्थ्य. शुरुआत में अति आत्मविश्वासः कई ड्रॉपर शुरू में ही आत्मसंतुष्ट महसूस करते हैं, यह मानते हुए कि वे पहले से ही अवधारणाओं से परिचित हैं। जैसे-जैसे तेज़ गति वाला पाठ्यक्रम आगे बढ़ता है, इससे काम का बोझ बढ़ सकता है। अधीरताः छात्र अक्सर अपने ड्रॉप ईयर की शुरुआत अत्यधिक उत्साह के साथ करते हैं, अध्ययन के लिए लंबे समय तक समर्पित करते हैं। समय के साथ, यह तीव्रता जलन और हताशा का कारण बन सकती है। इन चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए, विजय गर्ग एक संतुलित दिनचर्या बनाए रखने की सलाह देते हैं जिसमें निर्धारित अध्ययन, शारीरिक गतिविधि और नियमित ब्रेक शामिल हैं। ड्रॉपर्स के लिए व्यायाम सलाह सफल ड्रॉप-ईयर छात्र केवल सैद्धांतिक अध्ययन के बजाय समस्या-समाधान को प्राथमिकता देते हैं। ₹अपनी प्रगति को पढ़ाई के घंटों से नहीं बल्कि प्रतिदिन हल किए गए प्रश्नों की संख्या से मापें।₹ जेईई एडवांस्ड के लिए अब उपलब्ध तीन प्रयासों के साथ, छात्र पिछले वर्षों के प्रश्नों में महारत हासिल करने और अपनी गति को निखारने पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। मिश्रा सुझाव देते हैं कि उम्मीदवार अपनी समस्या-समाधान कौशल में सुधार करने की प्रतिबद्धता के साथ अपनी तैयारी करते हैं, जो सफलता के लिए महत्वपूर्ण है। सामाजिक जीवन का प्रभाव ड्रॉप ईयर के दौरान जेईई की तैयारी के लिए अक्सर खुद को सामाजिक विकर्षणों से अलग करने की आवश्यकता होती है। सिद्धार्थ मिश्रा छात्रों को उन साथियों के साथ जुड़ने के लिए प्रोत्साहित करते हैं जो समान लक्ष्य साझा करते हैं, जिससे तैयारी यात्रा के दौरान प्रेरणा और सौहार्द सुनिश्चित होता है। ₹गिरावट के वर्ष अनिश्चित लग सकते हैं, लेकिन एक बार जब आप अपना लक्ष्य प्राप्त कर लेते हैं, तो इस अवधि के दौरान किए गए बलिदान प्रतीक्षा किए गए पुरस्कारों की तुलना में कम पड़ जाएंगे।₹ ड्रॉप ईयर लेना एक अत्यंत व्यक्तिगत निर्णय है जो छात्र के लक्ष्यों, तैयारियों और मानसिकता पर निर्भर करता है। अनुशासन, एक स्पष्ट योजना और सही संसाधनों तक पहुंच के साथ, एक ड्रॉप ईयर छात्रों के लिए अपनी क्षमता का एहसास करने का एक परिवर्तनकारी अवसर हो सकता है। हालाँकि, चुनौतियों से सफलतापूर्वक निपटने के लिए लचीलेपन, धैर्य और अटूट फोकस की भी आवश्यकता होती है। जैसा कि शिक्षक सहमत हैं, जबकि अधिकांश छात्र एक वर्ष की गिरावट के बाद सुधार करते हैं, उस सुधार की सीमा पूरी तरह से उनके समर्पण और रणनीतिक दृष्टिकोण पर निर्भर करती है।

सामाजिक जागरूकता

हमारे देश में बाल दिवस भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के जन्मदिन यानी 14 नवंबर को मनाया जाता है, लेकिन दुनिया यह दिवस 20 नवंबर को मनाती है। इस साल भी यह दिवस पूरे विश्व में मनाया गया। इसकी शुरुआत संयुक्त राष्ट्र ने 1954 में की थी। यह दिवस बच्चों से जुड़े मुद्दों के प्रति जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। 20 नवंबर 1959 में संयुक्त राष्ट्र की जनरल असेंबली ने बाल अधिकारों की घोषणा की थी। बाल अधिकारों को चार अलग-अलग भागों में बांटा गया है- जीवन जीने का अधिकार, संरक्षण का अधिकार, सहभागिता का अधिकार और विकास का अधिकार। बचपन बहुत सारी ऊर्जा लिए, मासूमियत, खेलकूद व शरारतों से भरा होता है। इसी समय में सीखी गई बातें जीवन की नींव बनती हैं। बच्चे का मन कोरी स्लेट की तरह होता है। उन्हें जैसे संस्कार और व्यवहार मिलता है, उसी से उस बच्चे के जीवन में उसका व्यवहार और विचार प्रभावित होते हैं। इसी समय में शारीरिक व मानसिक विकास होता है। इसलिए हर बच्चे को स्वस्थ, समृद्ध व संस्कारपूर्ण बचपन देना उसका अधिकार है। हमारे देश में विश्व बाल दिवस को राष्ट्रीय बाल अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है, ताकि बच्चों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया जा सके। राष्ट्रीय बाल अधिकार दिवस मनाने का उद्देश्य बच्चों के अधिकारों की देखभाल करने के साथ साथ कई कुरीतियों जैसे बाल विवाह, बाल मजदूरी, शोषण, तस्करी करना आदि को रोकना है। आपको कई छोटे-छोटे बच्चे छोटे-बड़े होटलों व ढाबों पर कप-प्लेट उठाते मिल जाएंगे।

जिन नन्हें हाथों में किताबें होनी चाहिए थीं, वो नन्हें हाथ चाय के कप धोते नजर आते हैं। इसका एक कारण इन बच्चों की मजबूरियां हैं। इनके समाज का ऐसा माहौल है कि ये बच्चे इतनी कम उम्र में काम करने को मजबूर हो जाते हैं। देश में बाल मजदूरी के खिलाफ कानून सख्त है। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया पेंसिल पोर्टल बाल श्रम को खत्म करने वाला एक इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफार्म है। सशक्त विकास योजना के लक्ष्यों में बाल मजदूरी को 2025 तक समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। बालश्रम के विरुद्ध फैक्टरी कानून 1948 में, बाल श्रम (निषेध व नियमन) कानून 1986 में बनाया गया तथा साल 2016 में बदलाव करके इसे और सख्त बनाया गया। हमारा देश शुरुआत से ही बच्चों के अधिकारों, समानता और उनके विकास के लिए प्रतिबद्ध रहा है। इसके लिए भारतीय संविधान में सभी बच्चों के लिए कुछ खास अधिकार सुनिश्चित किए गए हैं, जैसे 6 से 14 साल की आयु वाले सभी बच्चों की अनिवार्य और निःशुल्क प्रारंभिक शिक्षा का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 24 में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को जोखिम वाले कार्य करने से सुरक्षा का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 39 (घ) में आर्थिक जरूरतों की वजह से जबरन ऐसे कामों में भेजना जो बच्चों की आयु के उपयुक्त नहीं है, से सुरक्षा का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 39 (च) में बालकों को स्वतंत्र और गरिमामय माहौल में स्वस्थ विकास के अवसर और सुविधाएं मुहैया कराने और शोषण से बचाने का प्रावधान किया गया है। इसके बावजूद यह तथ्य है कि आज भी सामाजिक जागरूकता चाहिए

सामाजिक सरोकार की सराहनीय पहल : 22 समाजसेवियों ने अपनी नेक कमाई से 120 जरूरतमंद विद्यार्थियों को वितरित की स्वेटर

झज्जर : जिला मुख्यालय के अंतिम छोर पर बसे वीरों की देवभूमि कहे जाने वाले गांव धारौली की सामाजिक संस्था मां-मातृभूमि सेवा समिति द्वारा कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और किसी के चेहरे पे मुस्कान बिखेरने से जो सकून और खुशी मिलती है, वो सकून और खुशी किसी जन्नत से कम नहीं होती है को ध्यान में रखते हुए राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, गांव अंबोली, जिला झज्जर के 120 जरूरतमंद विद्यार्थियों को आयोजित वस्त्र समर्पण सेवा कार्यक्रम में निःशुल्क स्वेटर वितरण की गई I स्वेटर पाकर सभी विद्यार्थियों के चेहरे खुशी से खिल उठे।

समाजसेवी एवं शिक्षाविद् माननीय चेयरमैन सुखबीर जाखड़ ने कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप मे पधारे I अपने संबोधन में चेयरमैन सुखबीर जाखड़ ने विद्यार्थियों की हर क्षेत्र में सफलता की कामना करते हुए भविष्य में कड़ी मेहनत के लिए प्रेरित किया।

शिक्षाविद जोगिंद्र यादव, डायरेक्टर, मेडी-जेईई करियर इंस्टीट्यूट, कोसली और पर्यावरण संरक्षण को समर्पित मंजीत सिंह अम्बोली निवासी, प्रो. श्री हँस बैग हाउस, कोसली के पिता श्री बलबीर सिंह ने कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में शिरकत की। अपने संबोधन मे शिक्षाविद जोगिंद्र यादव ने कहा कि शास्त्रों व विद्वानों का भी कहना है कि मनुष्य को अपनी नेक कमाई से कुछ अंश सामाजिक कामों और जरूरतमंदों की भलाई में खर्च करना चाहिए I

माननीय राजेश यादव, प्रिंसिपल, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, गांव अंबोली ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की I प्रिंसिपल ने मां-मातृभूमि सेवा समिति की विद्यार्थियों को निःशुल्क स्वेटर वितरण करने की अनूठी पहल की भूरी भूरी प्रशंसा की।

समाजसेवी व शिक्षक डॉ. महावीर सिंह ने अपने जोशीले शब्दों से कुशलतापूर्वक मंच का संचालन करके वस्त्र समर्पण सेवा कार्यक्रम को यादगार बना दिया I

21 बार रक्तदान कर चुके युद्धवीर सिंह लांबा, अध्यक्ष, मां-मातृभूमि सेवा समिति, वीरों की देवभूमि धारौली ने बताया कि 1.माननीय सुखबीर जाखड़, चेयरमैन, रिलायंस ग्रुप ऑफ स्कूल्स 2.शिक्षा के साथ साथ सामाजिक सरोकार का दायित्व भी बेखुबी निभा रहे मास्टर हरबीर मल्हान गिरधरपुर निवासी 3.पर्यावरण संरक्षण को समर्पित मंजीत सिंह, प्रो. श्री हँस बैग हाउस, कोसली 4.युद्धवीर सिंह लांबा,वीरों की देवभूमि धारौली 5. धर्मेंद्र यादव, मेडी-जेईई करियर इंस्टीट्यूट कोसली 6.समाजसेवी सागर यादव, (फिजिकल ट्रेनर ऑफ़ इंडियन नेवी) रेलवे स्टेशन कोसली 7.हरियाणा सरकार में जूनियर इंजीनियर अजय मलिक, खानपुर कलां, सोनीपत 8.ब्रह्मशक्ति संजीवनी अस्पताल, बहादुरगढ़ और नवजीवन हॉस्पिटल, मॉडल टाउन रोहतक के मैनेजर विक्रांत शर्मा 9.धारौली निवासी नवीन लांबा सुपुत्र स्व. मांगे राम 10.असिस्टेंट टैक्सेशन ऑफीसर के पद पर कार्यरत, संजीव घणघस, गाँव जताई, भिवानी 11.कोसली रेलवे स्टेशन में नाहड रोड पर 'सोनू मोटर वाइंडिंग सेंटर' प्रो. सोनू कुमार धारौली 12. सरकारी बैंक में कार्यरत इंजीनियर अजय जांगड़ा भिवानी 13. प्रेमसुख कुमार, प्रो., बिट्टू स्कूल ड्रेस, कोसली 14.इंजीनियर अमित दांगी, गांव मदीना, रोहतक 15.रक्तदानी नितेश भौरिया, प्रो.अर्बन युवा रेडीमेड स्टोर, कोसली में कपड़ों की मशहूर दुकान 16.झज्जर निवासी श्री नरसिंह, सरकारी बैंक में कार्यरत 17.कोसली गांव के कमला मेडिकल स्टोर के प्रो.विक्रम यादव 18.कृष्ण सिंह, असिस्टेंट रजिस्ट्रार पद पर कार्यरत 19.मास्टर रोहित यादव, कोसली निवासी 20.श्रीमती अनार बाला, सामाजिक कार्यकर्ता कोसली 21.शिक्षाविद मास्टर पवन कुमार, गांव धनीरवास झज्जर निवासी 22.असिस्टेंट प्रोफेसर व करियर काउंसलर यशपाल चोपड़ा, बहादुरगढ़ निवासी आदि समाजसेवियों व शिक्षाविदों ने अपनी ईमानदारी से कमाया नेक धन से कार्यक्रम के सफल आयोजन मे सहयोग दिया ।

क्लाउड सीडिंग, नगरीकरण, और वैश्विक तापन

विजय गर्ग

क्लाउड सीडिंग, नगरीकरण, और वैश्विक तापन तीन महत्वपूर्ण विषय हैं, जो पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन से जुड़े हुए हैं। इनका प्रभाव एक-दूसरे पर भी पड़ता है। आइए इन्हें विस्तार से समझते हैं:

1. क्लाउड सीडिंग

क्लाउड सीडिंग एक कृत्रिम प्रक्रिया है जिसमें बादलों में ऐसे रसायनों (जैसे सिल्वर आयोडाइड या सोडियम क्लोराइड) का छिड़काव किया जाता है, जो वर्षा या बर्फबारी को बढ़ाने में मदद करते हैं।

उद्देश्यः

सूखा प्रभावित क्षेत्रों में पानी की उपलब्धता बढ़ाना।

कृषि, जलाशयों और जल आपूर्ति को सुधारना।

चुनौतियांः

रसायनों का पर्यावरण और स्वास्थ्य पर दीर्घकालिक प्रभाव।

यह प्राकृतिक जलवायु चक्र को प्रभावित कर सकता

2. नगरीकरण

नगरीकरण का मतलब है ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में लोगों का पलायन और शहरों का विस्तार।

प्रभावः

सकारात्मकः रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं का विकास।

नकारात्मकः

प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक उपयोग।

ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन बढ़ता है।

ताप द्वीप प्रभाव , जिसमें शहरी क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में अधिक गर्म हो जाते हैं।

जलवायु पर प्रभावः

शहरीकरण का सीधा संबंध वैश्विक तापन और पर्यावरणीय असंतुलन से है।

3. वैश्विक तापन

वैश्विक तापन का मतलब है पृथ्वी के औसत तापमान में वृद्धि, जो मुख्य रूप से ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन के कारण होता है।

कारणः

जीवाश्म ईंधन का जलाना।

औद्योगिकीकरण और शहरीकरण।

वनों की कटाई।

परिणामः

ग्लेशियरों का पिघलना और समुद्र स्तर में वृद्धि।

मौसम चक्रों में असामान्यता।

जैव विविधता को खतरा।

आपस में संबंध

1. क्लाउड सीडिंग और वैश्विक तापनः

क्लाउड सीडिंग एक अस्थायी समाधान हो सकता है, लेकिन यह जलवायु परिवर्तन के मूल कारणों को नहीं रोकता।

वैश्विक तापन की वजह से वर्षा के पैटर्न बदल रहे हैं, जो क्लाउड सीडिंग को अधिक जरूरी बना सकता है।

2. नगरीकरण और वैश्विक तापनः

शहरी क्षेत्रों में बढ़ता ऊर्जा उपयोग और गाड़ियों से निकलने वाला धुआं ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को बढ़ाता है।

शहरीकरण प्राकृतिक पारिस्थितिकी को नष्ट करता है, जो जलवायु संतुलन को बिगाड़ता है।

3. क्लाउड सीडिंग और नगरीकरणः

नगरीकरण के कारण पानी की मांग बढ़ती है, जिससे सूखा प्रभावित क्षेत्रों में क्लाउड सीडिंग का उपयोग बढ़ सकता

समाधान

वैश्विक तापन को रोकने के लिएः

नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग बढ़ाएं।

वनीकरण और कार्बन उत्सर्जन में कमी करें।

सतत नगरीकरणः

स्मार्ट सिटी योजनाएं लागू करें।

ऊर्जा-कुशल इमारतें बनाएं।

क्लाउड सीडिंग के विवेकपूर्ण उपयोगः

इसे पर्यावरणीय जोखिमों का ध्यान रखते हुए ही लागू करें।

प्राकृतिक जलवायु प्रक्रियाओं में न्यूनतम हस्तक्षेप करें।

यह तीनों प्रक्रियाएं एक जटिल लेकिन महत्वपूर्ण परिदृश्य को दर्शाती हैं, जिन्हें संतुलित और सतत तरीके से प्रबंधित करना अनिवार्य है।

कोल्ड ड्रिंक की बोतल पर भी सिगरेट और तंबाकू की तरह चेतावनी छपवानी चाहिए ताकि लोग इसके खतरों को समझ सकें : वरिष्ठ समाजसेवी डॉ उमेश शर्मा चेयरमैन-उ.प्र.अपराध निरोधक

रिपोर्ट्स और आंकड़ों के अनुसार, यह सच है कि कोल्ड ड्रिंक और शुगर से संबंधित स्वास्थ्य समस्याएं बहुत गंभीर हो सकती हैं। दरअसल, अत्यधिक चीनी का सेवन डायबिटीज, हृदय रोग, उच्च रक्तचाप, और यहां तक कि कैंसर जैसी बीमारियों का कारण बन सकता है। यह भी सही है कि इन उत्पादों पर सिगरेट और तंबाकू की तरह चेतावनियाँ छापी जानी चाहिए ताकि लोग इसके खतरों को समझ सकें। यह विचार चेयरमैन-उ.प्र.अपराध निरोधक समिति एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष-अखिल भारतीय विप्र एकता मंच के वरिष्ठ समाजसेवी डॉ उमेश शर्मा ने लोगों के स्वास्थ्य पर पड़ते हानिकारक असर को देते हुए राष्ट्रहित और समाजहित में व्यक्त किये।

कोल्ड ड्रिंक की बोतल पर सिगरेट और तंबाकू की तरह चेतावनी छपवाने का सुझाव वरिष्ठ समाजसेवी डॉ उमेश शर्मा ने स्वास्थ्य पर इसके हानिकारक प्रभावों को ध्यान में रखते हुए दिया है। उनका मानना है कि कोल्ड ड्रिंक में अत्यधिक चीनी का सेवन स्वास्थ्य समस्याओं जैसे डायबिटीज, हृदय रोग, उच्च रक्तचाप, और कैंसर का कारण बन सकता है। रिपोर्ट्स के अनुसार, 2 लीटर कोल्ड ड्रिंक में लगभग 250 ग्राम चीनी होती है, जो एक व्यक्ति के दैनिक चीनी सेवन से कहीं अधिक है।

श्री शर्मा ने चेतावनी के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि यदि इन उत्पादों पर सिगरेट की तरह चेतावनी दी जाए, तो लोग इसके स्वास्थ्य पर प्रभाव को समझने के लिए जागरूक हो सकते हैं। उनका कहना था कि अत्यधिक चीनी से इंसुलिन का स्तर बढ़ता है, जिससे रक्तचाप, हृदय रोग और यहां तक कि कैंसर जैसी गंभीर बीमारियाँ उत्पन्न हो सकती हैं। उन्होंने यह भी कहा कि, ₹डायबिटीज के मरीजों में कैंसर विकसित होने की संभावना 28% होती है। कोल्ड ड्रिंक में अत्यधिक चीनी की मात्रा को लेकर कई शोधों ने इसकी गंभीरता को उजागर किया है। रिपोर्ट्स और आंकड़ों के अनुसार उदाहरण के तौर पर, 2 लीटर कोल्ड ड्रिंक में लगभग 250 ग्राम चीनी होती है, जो एक व्यक्ति के दैनिक शुगर सेवन से कहीं ज्यादा है। यह अत्यधिक चीनी का सेवन शरीर में इंसुलिन का स्तर बढ़ा सकता है, जिससे अनेक जटिलताएँ उत्पन्न होती हैं, जैसे कि उच्च रक्तचाप, दिल की बीमारियाँ, और मेटाबोलिक समस्याएँ। उन्होंने कहा, किसी भी उत्पाद पर चेतावनी छापने का उद्देश्य केवल लोगों को सचेत करना होता है, ताकि वे अपने स्वास्थ्य को प्राथमिकता दें और ज्यादा चीनी या शुगर युक्त उत्पादों से दूर रहें। यदि कोल्ड ड्रिंक पर सिगरेट की तरह चेतावनी दी जाए, तो यह लोगों को यह सोचने के लिए प्रेरित कर सकता है कि उनकी पसंदीदा पेय का सेवन भी उनके स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव डाल सकता है। यह जरूरी है कि लोग शुगर के सेवन को सीमित करें और अपने आहार में संतुलन बनाए रखें ताकि वे इन समस्याओं से बच सकें।

उन्होंने आगे कहा,- रिपोर्ट्स और आंकड़ों के अनुसार, सबको पता होता है कि किसी भी एक स्वस्थ्य व्यक्ति को पूरे दिन में 6 चम्मच से ज्यादा चीनी नहीं लेनी चाहिए। परंतु फिर भी हम कोल्ड ड्रिंक तब तक पीते हैं, जब तक डायबिटीज का लेवल 400 पार नहीं कर जाता। याद रखना एक बार डायबिटीज होने पर दवाई तो आप खा लोगे परंतु उसके साइड इफेक्ट से नहीं बच पाओगे। ये सभी दवाएं खून में इंसुलिन का स्तर बहुत अधिक बढ़ा देती हैं। इंसुलिन की इतनी मात्रा होने से, खून बहुत गाढ़ा हो जाता है। शरीर में बड़ी मात्रा में इंसुलिन होने से उसे भारी नुकसान पहुंचता है। यह जिगर, गुर्दे और मल उत्सर्जन वाले अन्य अंगों को लगभग नष्ट कर देती है। गाढ़ेपन और काम में इंसुलिन पेट के एसिड की तरह होती है। सोचिए अगर पेट का एसिड आपके आंतरिक अंगों में भर जाए तो क्या होगा ?

उन्होंने कहा, वे एसिड से जल जाएँगे। इंसुलिन का बढ़ा हुआ स्तर, कोशिकाओं को नष्ट करके, उन्हें असामान्य रूप से विभाजित करने लगता है, और यही ऑन्कोलॉजी है। इस वजह से, आंकड़ों के अनुसार, डायबिटीज के 28% मरीज़ों में कैंसर विकसित हो जाता है। इसके अलावा, इंसुलिन की बड़ी मात्रा रक्त वाहिकाओं में कोलेस्ट्रॉल के तेजी से जमने का कारण बनती है, क्योंकि इंसुलिन के कारण गाढ़े हो गए खून का बहाव धीमा हो जाता है। जिसकी वजह से, रक्त वाहिकाएँ कोलेस्ट्रॉल से भर जाती हैं, जिसके कारण रक्तचाप बढ़ जाता है। डायबिटीज के 98% मरीज़ उच्च रक्तचाप से पीड़ित होते हैं और उनमें हृदय प्रणाली की कई अन्य समस्याएं पैदा हो जाती हैं। इसलिये राष्ट्रहित एवं स्वास्थ्यहित में कोल्ड ड्रिंक की बोतल पर भी चेतावनी छपवानी चाहिए ताकि अंजान लोग इसके खतरों को समझ सकें। यह महत्वपूर्ण विचार समाज के स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हो सकता है, ताकि लोग अपने आहार में संतुलन बनाए रखें और शुगरयुक्त पेय पदार्थों से बचें।

मीडिया एवं मनोरंजन उद्योग के क्षेत्र में रोजगार के अवसर

मीडिया और मनोरंजन उद्योग आज एक बड़ा और तेजी से बढ़ने वाला क्षेत्र है, जो विभिन्न प्रकार के रोजगार के अवसर प्रदान करता है। यह क्षेत्र पारंपरिक मीडिया (जैसे प्रिंट और टीवी) तक सीमित नहीं है, बल्कि डिजिटल प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया, ओटीटी सेवाओं और गेमिंग तक फैल गया है। नीचे कुछ प्रमुख क्षेत्र हैं जहां रोजगार के अवसर बढ़े हैंः 1. पत्रकारिता एवं समाचार मीडिया पत्रकारः रिपोर्टिंग और समाचारविश्लेषण संपादकः सामग्री संपादित करना. डिजिटल सामग्री निर्माताः वेबसाइटों और ऐप्स के लिए सामग्री बनाना। वीडियो और फोटो जर्नलिस्टः विजुअल स्टोरीटेलिंग। 2. फिल्म और टीवी का काम अभिनयः फ़िल्में, नाटक और वेब श्रृंखला। निर्देशक और निर्माताः पत्रों से पूरी फिल्म बनाने के लिए जिम्मेदार। पटकथा लेखनः पटकथाओं और कहानियों के लेखक। फ़िल्म संपादकः पोस्ट-प्रोडक्शन कार्य। 3. डिजिटल और सोशल मीडिया सोशल मीडिया मैनेजरः ब्रांड की ऑनलाइन प्रोफ़ाइल प्रबंधित करना। सामग्री लेखक और निर्माताः डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए पोस्ट और वीडियो बनाना। व्लॉगिंग और इन्फ्लुएंसर मार्केटिंगः डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से प्रचार करना। 4. गेमिंग और एनीमेशन गेम डेवलपरः गेम डिज़ाइन और विकास। एनिमेटरः कार्टून और ग्राफिकल दृश्य बनाना। वीएफएक्स कलाकारः दृश्य प्रभावों में विशेषज्ञ। 5. ओटीटी और स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म सामग्री विकासः नए शो और श्रृंखला की योजना। डेटा एनालिटिक्सः दर्शकों के रुझान की पहचान करना। डिजिटल मार्केटिंगः शो को प्रमोट करने के लिए कैंपेन चला रहे हैं. 6. दृश्य और ग्राफिक्सडिज़ाइन ग्राफ़िक डिज़ाइनरः मीडिया सामग्री के लिए डिज़ाइन बनाना। फ़ोटोग्राफ़र और वीडियोग्राफरः स्टिल और मोशन क्लिप बनाना। 7. मार्केटिंग और पीआर जनसंपर्क प्रबंधकः मीडिया और संचार के माध्यम से ब्रांड छवि बनाना। ब्रांड मैनेजरः मीडिया कंपनियों का विपणन और प्रचार। प्रगति के कारण डिजिटल मीडिया का उदय. एआई और वीआर जैसी नई प्रौद्योगिकियां। लोगों के बीच मनोरंजन और सूचना प्राप्ति की मांग बढ़ रही है। आवश्यक कौशल रचनात्मकता। संचार कौशल. प्रौद्योगिकी और डिजिटल उपकरणसमझना सोशल मीडिया रणनीति. मीडिया और मनोरंजन उद्योग में ताकतवर लोगों के लिए कई नए रुझान और विकास के अवसर हैं।

सोने की कीमतों में जोरदार उछाल, बड़ी गिरावट के किस वजह से चढ़े दाम?

परिवहन विशेष न्यूज

डोनाल्ड ट्रंप की राष्ट्रपति चुनाव में जीत के बाद सोने की कीमतों में करीब 5 हजार रुपये की गिरावट आई थी। हालांकि अब एक बार फिर सोने की कीमतों में तेजी देखने को मिल रही है। गुरुवार को राष्ट्रीय राजधानी में सोने की कीमत 1400 रुपये उछलकर 79300 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गई। आइए जानते हैं कि सोने की कीमतों में उछाल क्यों आ रहा है।

नई दिल्ली। सोने की कीमतों में एकबार फिर उछाल देखने को मिल रहा है। अखिल भारतीय सर्राफा संघ के अनुसार, आभूषण विक्रेताओं और खुदरा विक्रेताओं की ताजा खरीदारी के कारण गुरुवार को राष्ट्रीय राजधानी में सोने की कीमत 1,400 रुपये उछलकर 79,300 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गई।

पिछले सत्र में 99.9 प्रतिशत शुद्धता वाली कीमती धातु 77,900 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुई थी। हालांकि, गुरुवार को चांदी 93,000 रुपये प्रति किलोग्राम पर स्थिर रही। बुधवार को 99.5 प्रतिशत शुद्धता वाले सोने की कीमत 77,500 रुपये प्रति 10 ग्राम के पिछले बंद भाव के मुकाबले 1,400 रुपये बढ़कर 78,900 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गई।

इस बीच, एमसीएक्स पर वायदा कारोबार में दिसंबर डिलीवरी वाले सोने के अनुबंध की कीमत 568 रुपये या 0.75 प्रतिशत की तेजी के साथ 76,602 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गई।

क्यों बढ़ रहे हैं सोने के भाव

एलकेपी सिक्योरिटीज में कमोडिटी और करेंसी के वीपी रिसर्च एनालिस्ट जतीन त्रिवेदी ने कहा, 'भू-राजनीतिक तनावों ने सुरक्षित निवेश की मांग को फिर से जगा दिया है। साथ ही, रूस-यूक्रेन संघर्ष में परमाणु जोखिमों पर नई चिंताएं भी बढ़ गई हैं। इससे सोने की कीमतों में उछाल आया है।'

त्रिवेदी ने कहा कि भू-राजनीतिक घटनाक्रमों के कारण अल्पावधि में सोने की कीमतों में काफी उतार-चढ़ाव का अनुमान है। दिसंबर डिलीवरी के लिए चांदी के अनुबंध एमसीएक्स पर 318 रुपये या 0.35 प्रतिशत बढ़कर 90,407 रुपये प्रति किलोग्राम हो गए। वैश्विक स्तर पर, कॉमेक्स सोना वायदा 19.80 डॉलर प्रति औंस या 0.74 प्रतिशत बढ़कर 2,695.40 डॉलर प्रति औंस हो गया।

रूस-यूक्रेन तनाव ट्रिगर प्वाइंट

एचडीएफसी सिक्योरिटीज में कमोडिटीज के वरिष्ठ विश्लेषक सौमिल गांधी ने कहा, 'रूस और यूक्रेन के बीच संकट के बढ़ने के बाद निवेशकों के सुरक्षित निवेश की ओर लौटने से सोने में तेजी आई। हाल ही में अमेरिका निर्मित लंबी दूरी की मिसाइलों के हमले के बाद, यूक्रेन ने रूसी क्षेत्र में ब्रिटेन निर्मित मिसाइलों को तैनात किया है।'

यूक्रेन ने गुरुवार को कहा कि रूस ने देश के मध्य-पूर्व में नीपर शहर को निशाना बनाते हुए रात भर एक अंतरमहाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च की। अगर इसकी पुष्टि होती है, यह पहली बार होगा जब मास्को ने युद्ध में इस तरह की मिसाइल का इस्तेमाल किया है। इस घटनाक्रम ने व्यापक संकट की संभावना को बढ़ा दिया है, जिससे सुरक्षित पनाहगाह परिसंपत्ति के रूप में सोने की मांग में वृद्धि हुई है।

गोल्ड या बिटकॉइन... किसमें करें निवेश, कौन देगा तगड़ा मुनाफा?

अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की जीत के बाद बिटकॉइन में जोरदार तेजी आई है। इसने पिछले एक साल में करीब 150 फीसदी का मल्टीबैगर रिटर्न दिया है। वहीं सोने में भी इस साल काफी तेजी आई है। इसने एक साल में करीब 25 फीसदी का स्थिर रिटर्न दिया है। आइए जानते हैं कि सोने और बिटकॉइन में से कौन निवेश के लिहाज से बेहतर है।

नई दिल्ली। गोल्ड को दुनिया की सबसे पुरानी करेंसी माना जाता है, जिसका लेनदेन दुनिया के किसी भी हिस्से में किया जा सकता है। वहीं, बिटकॉइन को नए जमाने की डिजिटल करेंसी का तमगा दिया गया है। इन दोनों ने पिछले कुछ समय में शानदार रिटर्न दिया है। आइए जानते हैं कि निवेश और रिटर्न देने के लिए लिहाज से दोनों में से कौन-सी असेट बेहतर है।

बिटकॉइन का क्या है हाल?

अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप की जीत के बाद दुनिया की सबसे बड़ी क्रिप्टोकरेंसी बिटकॉइन में तूफानी रफ्तार देखने को मिल रही है। यह पहली बार 94 हजार डॉलर के स्तर पर पहुंच गई है। पिछले एक महीने की बात करें, तो बिटकॉइन ने 35 फीसदी का रिटर्न दिया है। वहीं, एक साल में निवेशकों को इससे 146 फीसदी से अधिक का मल्टीबैगर रिटर्न मिला है। फिलहाल, बिटकॉइन 92,530 डॉलर के स्तर पर है।

सोने से कितना हुआ मुनाफा?

सोने की बात करें, तो इसकी कीमतों में भी बड़ा उछाल आया है। एक साल पहले गोल्ड प्राइस 62,650 रुपये प्रति 10 ग्राम थी, जो अब 78,080 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गई है। इस हिसाब से गोल्ड ने एक साल में करीब 25 फीसदी का रिटर्न दिया है। सोने ने पिछले दिनों करीब 82 हजार रुपये का अपना ऑलटाइम हाई भी बनाया था। इसका मतलब कि सोना पिछले कुछ दिनों में लगभग 5 हजार रुपये सस्ता हुआ है।

सोने और बिटकॉइन का भविष्य

सोना सदियों पुरानी भरोसेमंद असेट क्लास है। इसे दुनिया का सबसे सुरक्षित निवेश समझा जाता है। वहीं, बिटकॉइन सबसे तेजी से बढ़ती असेट क्लास है। इसने पिछले दिनों मार्केट कैप के लिहाज से चांदी को पीछे छोड़ दिया और सातवें नंबर पर पहुंच गई। दरअसल, ट्रंप ने चुनावी अभियान में वादा किया था कि राष्ट्रपति बनने के बाद वे अमेरिका को क्रिप्टो कैपिटल बनाएंगे। यही वजह है कि बिटकॉइन की कीमतों में जोरदार उछाल देखने को मिल रहा।

सोना सेफ इन्वेस्टमेंट के लिए बेहतर

ट्रंप की जीत के बाद सोना थोड़ा सस्ता जरूर हुआ है, क्योंकि डॉलर मजबूत हुआ, साथ ही बॉन्ड यील्ड भी बढ़ी है। लेकिन, वैश्विक अस्थिरता के चलते सोने के दाम में फिर तेजी आ सकती है। खासकर, यूक्रेन के रूस पर हमले ने तनाव को बढ़ा दिया है और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने परमाणु हमले की धमकी भी दी है। प्रतिष्ठित रेटिंग एजेंसी गोल्डमैन सैक्स का भी अनुमान है कि सोने के भाव में आगे और तेजी आएगी। यह निवेश का सबसे सुरक्षित तरीका है और आपको मध्यम से लंबी अवधि में स्थिर रिटर्न दे सकता है।

बिटकॉइन में जोखिम है ज्यादा

वहीं, बिटकॉइन की बात करें, तो भारत में इसे लेकर कोई खास नियम-कायदा नहीं है। ट्रंप की जीत से आगे भी बिटकॉइन की कीमतों में तेजी जारी रह सकती है, लेकिन भारत में फिलहाल इसे सुरक्षित निवेश नहीं कहा जा सकता। साथ ही, भारत में क्रिप्टोकरेंसी से होने वाले मुनाफे पर 30 फीसदी का भारी टैक्स भी लगता है। क्रिप्टो ट्रांसफर पर 1 फीसदी टीडीएस भी है। यहां क्रिप्टो को लेकर खास सिक्योरिटी फीचर नहीं है। ऐसे में बिटकॉइन या क्रिप्टोकरेंसी में निवेश तभी करें, जब आपकी जोखिम लेने की क्षमता अधिक हो।

भारी बिकवाली के बीच संसेक्स, निफ्टी में गिरावट; अदाणी ग्रुप को सबसे ज्यादा झटका

अरबपति कारोबारी और अदाणी ग्रुप के मालिक गौतम अदाणी पर अमेरिका में धोखाधड़ी और रिश्वत देने के आरोप लगे हैं। इसमें गौतम अदाणी के अतिरिक्त 7 अन्य लोग भी आरोपी हैं। इस खबर का अदाणी ग्रुप के स्टॉक के शेयर मार्केट पर भी काफी नकारात्मक असर हुआ है। सेंसेक्स और निफ्टी आधा फीसदी से अधिक की गिरावट के साथ बंद हुए।

नई दिल्ली। भारतीय शेयर बाजार में गुरुवार को भी बड़ी गिरावट दिखी। अरबपति उद्योगपति गौतम अदाणी पर अमेरिका में कथित तौर पर रिश्वतखोरी और धोखाधड़ी का आरोप लगा है। इससे अदाणी ग्रुप की सभी 10 लिस्टेड कंपनियों में भारी गिरावट आई है। हालांकि, अदाणी ग्रुप ने धोखाधड़ी और रिश्वत के आरोपों पर बयान जारी करके सफाई दी है। उसने सभी आरोपों को बेबुनियाद बताया है। अदाणी ग्रुप ने यह भी कहा कि वह अपने सभी कानूनी विकल्पों पर विचार करेगा।

विदेशी फंडों की लगातार निकासी और एशियाई-यूरोपीय बाजारों के कमजोर प्रदर्शन ने भी भारतीय बाजार को प्रभावित किया। बीएसई बेंचमार्क सेंसेक्स 422.59 अंक यानी 0.54 प्रतिशत गिरकर 77,155.79 पर बंद हुआ। दिन के दौरान यह 775.65 अंक यानी 0.99 प्रतिशत गिरकर 76,802.73 पर आ गया। एनएसई निफ्टी 168.60 अंक यानी 0.72 प्रतिशत गिरकर 23,349.90 पर आ गया।

अदाणी पोर्ट्स 13 फीसदी गिरा

30 शेयरों वाले सेंसेक्स पैक में अदाणी ग्रुप के अदाणी पोर्ट्स में 13 फीसदी से अधिक की गिरावट आई है। वहीं, अदाणी एंटरप्राइजेज, अदाणी एनर्जी सॉल्यूशंस, अदाणी पोर्ट्स और अदाणी ग्रीन एनर्जी सहित समेत अदाणी ग्रुप के अन्य सभी शेयरों में लगभग 23 प्रतिशत तक की तेज गिरावट आई है।

एसबीआई, एनटीपीसी, आईटीसी, एशियन पेंट्स, बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व में भी ज्यादा गिरावट दिखी। वहीं, पावर ग्रिड, अल्ट्राटेक सीमेंट, एचसीएल टेक्नोलॉजीज और एक्सिस बैंक फायदे में रहे।

विदेशी निवेशकों की बिकवाली जारी

एक्सचेंज के आंकड़ों के अनुसार, विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) ने मंगलवार को 3,411.73 करोड़ रुपये के शेयर बेचे थे। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के कारण बुधवार को भारतीय शेयर बाजार बंद था। एशियाई बाजारों की बात करें, तो सियोल, टोक्यो और हांगकांग में गिरावट रही, जबकि शंघाई में तेजी दिखी। यूरोपीय बाजार लाल निशान में कारोबार कर रहे थे। वहीं, अमेरिकी बाजार बुधवार को ज्यादातर हरे निशान में बंद हुए थे।

वैश्विक तेल बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड 1.13 प्रतिशत उछलकर 73.71 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया। चार दिनों की गिरावट को रोकते हुए, मंगलवार को बीएसई बेंचमार्क सेंसेक्स 239.37 अंक या 0.31 प्रतिशत चढ़कर 77,578.38 पर बंद हुआ। पिछले सात कारोबारी दिनों में गिरावट के बाद मंगलवार को निफ्टी में भी उछाल आया। यह 64.70 अंक या 0.28 प्रतिशत बढ़कर 23,518.50 पर बंद हुआ।

गिरते बाजार में लगा अपर सर्किट, ब्रोकरेज के बड़े टारगेट का दिखा कमाल

परिवहन विशेष न्यूज

सुजलॉन एनर्जी देश में विंड पावर यानी पवन ऊर्जा टरबाइन की सबसे बड़ी निर्माता है। इसी ने भारत में ज्यादातर पवन ऊर्जा क्षमता को स्थापित किया है। यह अलग-अलग क्षमता वाली पवन टरबाइन का निर्माण करती है। पिछले कुछ दिनों से सुजलॉन एनर्जी के शेयरों में लगातार अपर सर्किट लग रहे हैं। आइए जानते हैं कि इसकी वजह क्या है।...

नई दिल्ली। भारतीय शेयर बाजार में आज गिरावट का दौर है। कमजोर वैश्विक रुझानों और बिकवाली के चलते सेंसेक्स और निफ्टी आधा फीसदी से अधिक की गिरावट के साथ कारोबार कर रहे हैं। लेकिन, इस सुस्ती के बीच सुजलॉन एनर्जी के शेयरों में पांच फीसदी का अपर सर्किट लगा है। हालांकि, मुनाफावसूली के चलते इसमें थोड़ा करेक्शन हुआ और यह फिलहाल 4.76 की बढ़त के साथ 65.18 रुपये पर कारोबार कर रहा है।

सुजलॉन में 38 फीसदी गिरावट के बाद तेजी

सुजलॉन एनर्जी के शेयरों में पिछले चार कारोबारी सत्र से अपर सर्किट लग रहा है। इस दौरान शेयर का भाव 54 रुपये से 65 रुपये के पार पहुंच गया है। मल्टीबैगर स्टॉक सुजलॉन एनर्जी में यह तेजी 52 वीक के उच्चतम स्तर से 38 फीसदी की गिरावट देखने के बाद आई है। यह गिरावट पिछले दो महीने में आई थी। सुजलॉन ने 12 सितंबर, 2024 को 86.04 रुपये का हाई बनाया था, जो उसके बाद इसमें जोरदार बिकवाली देखने को मिली।

Suzlon Energy में भारी तेजी की वजह

ब्रोकरेज फर्में सुजलॉन एनर्जी में निचले स्तर से ही खरीदारी की सलाह दे रही हैं। जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज ने 68 रुपये के टारगेट प्राइस के साथ सुजलॉन को Buy रेटिंग दी है। हालांकि, जियोजीत की सलाह तब आई थी, जब सुजलॉन 60 रुपये के आसपास ही था। जियोजीत का मानना है कि सुजलॉन में ग्रोथ की काफी संभावनाएं हैं। इसका वैल्यूएशन भी अब काफी आकर्षक हो गया है।

मॉर्गन स्टैनली ने भी दी है Buy रेटिंग

प्रतिष्ठित वैश्विक ब्रोकरेज फर्म मॉर्गन स्टैनली ने भी सुजलॉन एनर्जी को खरीदने की सलाह दी है। उसने सुजलॉन के लिए 71 रुपये का टारगेट प्राइस दिया है। मॉर्गन स्टैनली का मानना है कि सुजलॉन एनर्जी की कारोबारी क्षमताएं और विंड एनर्जी सेगमेंट में मजबूत मौजूदा इसे भारत के एनर्जी ट्रांजिशन का अहम लाभार्थी बनाती हैं। ब्रोकरेज ने कहा कि सुजलॉन का 5.1 गीगावाट का बड़ा ऑर्डर बैकलॉग अगले 24 महीनों में पूरा किया जा सकता है।

सुजलॉन एनर्जी के तिमाही नतीजे

सुजलॉन ने सितंबर तिमाही में अच्छा प्रदर्शन किया है। उसका शुद्ध मुनाफा करीब दोगुना बढ़कर 200 करोड़ रुपये रहा, जो एक साल पहले 102 करोड़ रुपये था। इस दौरान कंपनी का रेवेन्यू 48 फीसदी बढ़कर 2,103 करोड़ रुपये रहा। यह पिछले साल इसी तिमाही में 1,421 करोड़ रुपये था। हालांकि EBITDA मार्जिन में गिरावट आई और यह पिछले साल के 15.74 फीसदी से घटकर 13.97 फीसदी रहा।

ब्याज दर घटाने के सुझाव पर RBI ने चेताया, महंगाई बेकाबू हुई तो इंडस्ट्री-एक्सपोर्ट हो सकते हैं तबाह

परिवहन विशेष न्यूज

पिछले कुछ दिनों से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण समेत कई केंद्रीय मंत्रियों ने आरबीआई को ब्याज दरों में कटौती करने का सुझाव दिया है। हालांकि केंद्रीय बैंक ने अपनी मासिक रिपोर्ट में स्पष्ट किया है कि उसका फोकस अभी महंगाई घटाने पर बना रहेगा। उसने आगाह किया है कि अगर महंगाई बेकाबू हुई तो इसका उद्योग और निर्यात पर काफी बुरा असर पड़ सकता है।

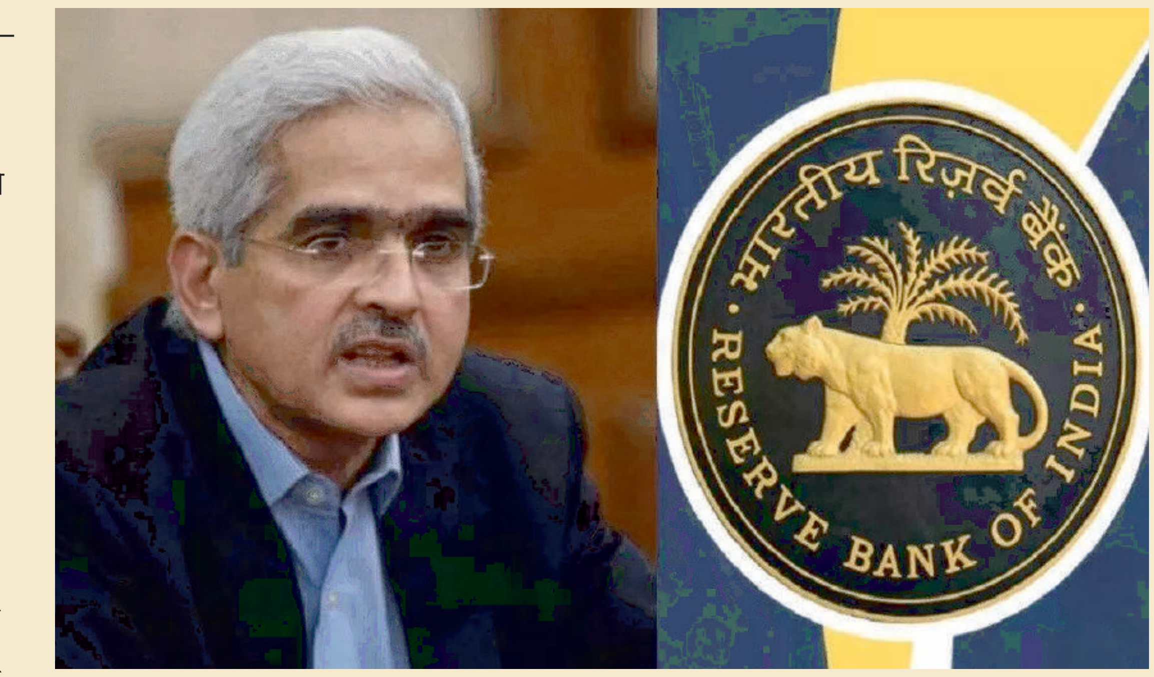

नई दिल्ली। ऐसे समय जब केंद्र सरकार के प्रमुख कैबिनेट मंत्री ब्याज दरों में कटौती की मांग कर रहे हैं, तब केंद्रीय बैंक की तरफ से ऐसे संकेत दिए गये हैं कि वह ब्याज दरों को घटाने को लेकर बहुत उत्साहित नहीं है। बुधवार को आरबीआई की मासिक रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर महंगाई ऐसे ही बेकाबू रही, तो देश के उद्योग और निर्यात पर भी असर हो सकता है।

आरबीआई ने अक्टूबर, 2024 में महंगाई दर के बढ़ने की स्थिति को अंचभित करने वाला करार दिया है। साथ ही यह भी कहा है कि जुलाई और अगस्त, 2024 में महंगाई दर के नीचे आने के बाद आरबीआई ने चेतावनी थी कि इसे काबू में करने की कोशिशों में कोई ढिलाई नहीं होनी चाहिए। साथ ही केंद्रीय बैंक ने यह भी संकेत दिये हैं कि पिछले कुछ समय से खाद्य उत्पादों की महंगाई दर में जो वृद्धि देखी गई है, उसका असर खाद्य तेलों, प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों पर भी दिखाई देने लगी है।

महंगाई दर के ताजे आंकड़े बताते हैं कि यह छह फीसद को पार करके पिछले 14 महीनों के उच्चतम स्तर पर है। कई महीनों बाद इसने आरबीआई की लक्ष्मण रेखा (6 फीसद) को भी पार कर लिया है। ऐसे में जो एजेंसियां दिसंबर, 2024 में ब्याज दरों में कमी की उम्मीद लगा रही थी वह अपने बयान बदलने लगी हैं। हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने देश में ब्याज दरों को घटाने की बात की है। पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने भी ऐसी ही बात की है।

आरबीआई महंगाई के खतरे को लेकर गंभीर

ऐसे में आरबीआई की ताजी रिपोर्ट यह संकेत दे रही है कि महंगाई के खतरे को लेकर वह काफी गंभीर है। आरबीआई ने महंगाई को चार फीसद (दो फीसद नीचे या दो फीसद ऊपर) के दायरे में रखने का लक्ष्य मिला हुआ है। आरबीआई कहता रहा है कि महंगाई को रोकना देश के मध्यम वर्ग और गरीब जनता के हितों के लिए सबसे जरूरी है।

आरबआई रिपोर्ट के मुताबिक, बढ़ती महंगाई का असर शहरी मांग और कंपनियों के राजस्व पर साफ तौर पर दिखाई देने लगा है। अगर इन पर नियंत्रण नहीं किया गया तो इसका असर रीयल इकोनमी, उद्योगों और निर्यात पर भी दिखाई देगा। निर्यात पर असर ज्यादा चिंताजनक है क्योंकि अभी वैश्विक हालात जो बन रहे हैं उसमें भारत से निर्यात बढ़ने के संकेत हैं।

रिपोर्ट में वैश्विक स्तर पर महंगाई और मांग की स्थिति पर भी चिंता जताई गई है। विश्व में महंगाई मोटे तौर पर कम हुई है लेकिन वैश्विक मांग में कोई खास वृद्धि नहीं देखी जा रही है। विकसित देशों के केंद्रीय बैंकों के पास ब्याज दरों को घटाने की जगह है लेकिन विकासशील देशों के केंद्रीय बैंकों के लिए स्थिति चुनौतीपूर्ण है।

अदाणी समूह पर अमेरिका में धोखाधड़ी का मुकदमा, शेयरों में भारी गिरावट; अदाणी ग्रुप ने कहा- सभी आरोप निराधार

परिवहन विशेष न्यूज

अरबपति कारोबारी गौतम अदाणी और उनके अदाणी ग्रुप की कुछ फर्मों पर अमेरिका में धोखाधड़ी और रिश्वत देने के आरोप लगे हैं। इन आरोपों के मुताबिक अदाणी ग्रुप ने भारत में सोलर एनर्जी कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए भारतीय अधिकारियों को 265 मिलियन डॉलर की रिश्वत दी या देने की योजना बना रहे हैं। इस खबर के बाद अदाणी ग्रुप के सभी शेयरों में भारी गिरावट आई है।

नई दिल्ली। अरबपति कारोबारी और अदाणी ग्रुप के मालिक गौतम अदाणी पर अमेरिका में धोखाधड़ी और रिश्वत देने के आरोप लगे हैं। इसमें गौतम अदाणी के अतिरिक्त 7 अन्य लोग भी आरोपी हैं। इस खबर का अदाणी ग्रुप के स्टॉक के शेयर मार्केट पर भी काफी नकारात्मक असर हुआ है।

अदाणी ग्रुप के ज्यादातर स्टॉक 10 से लेकर 20 फीसदी गिरावट के साथ कारोबार कर रहे हैं। इससे ओवरऑल शेयर मार्केट का सेंटिमेंट भी खराब हुआ। सेसेंक्स और निफ्टी, दोनों ने आधा फीसदी से अधिक का गोता लगाया है।

अदाणी ग्रुप ने धोखाधड़ी और रिश्वत के आरोपों पर बयान जारी करके सफाई दी है। ग्रुप का कहना है कि अदाणी ग्रीन के निवेशकों पर लगे सभी आरोप बेबुनियाद है। अदाणी ग्रुप ने यह भी कहा कि वह नियमों का पूरी तरह पालन करता है और अपने सभी कानूनी विकल्पों पर विचार करेगा।

अदाणी ग्रुप पर क्या आरोप हैं?

अदाणी ग्रुप के खिलाफ पूरा मामला अदाणी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड और एक अन्य फर्म से जुड़ा है। इस मामले को अमेरिकी अदालत में 24 अक्टूबर 2024 को दर्ज किया गया, जिसकी सुनवाई बुधवार को हुई। यूनाइटेड स्टेट्स अटॉर्नी ऑफिस का कहना है कि अदाणी ग्रुप ने भारत में सोलर एनर्जी कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए भारतीय अधिकारियों को 265 मिलियन डॉलर यानी करीब 2200 करोड़ रुपये की रिश्वत दी या देने की योजना बना रहे हैं। इससे अदाणी ग्रुप को अगले 20 साल में कथित तौर पर 2 अरब डॉलर का फायदा होने का अनुमान था।

अदाणी पर आरोप है कि रिश्वत के पैसों को जुटाने के लिए अमेरिकी, विदेशी निवेशकों और बैंकों से झूठ बोला। अमेरिका में मामला इस वजह से दर्ज हुआ, क्योंकि प्रोजेक्ट में अमेरिकी निवेशकों का पैसा लगा है। अमेरिकी कानून के मुताबिक, उस पैसे को रिश्वत के रूप में देना अपराध है।

अदाणी ग्रुप के शेयरों में कितनी गिरावट?

अदाणी ग्रुप की कुल 10 कंपनियां शेयर मार्केट में लिस्ट हैं। इनमें से सभी आज लाल निशान में कारोबार कर रही हैं। अदाणी ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी अदाणी एंटरप्राइजेज में 20 फीसदी, अदाणी एनर्जी सॉल्यूशंस में 20 फीसदी और अदाणी विल्मर में 10 फीसदी का लोअर सर्किट लग गया है। वहीं, अदाणी एनर्जी सॉल्यूशंस में 18 फीसदी से ज्यादा गिरावट आई है। अदाणी पोर्ट्स में भी 10 फीसदी का लोअर सर्किट लगा है।

इसके अलावा अदाणी पावर 14.01 फीसदी, अदाणी टोटल गैस 14.79 फीसदी, ACC 11.94 फीसदी, अम्बुजा सीमेंट्स 15.65 फीसदी और एनडीटीवी का शेयर 9.36 फीसदी तक गिर गया था। अदाणी ग्रुप के कुछ शेयरों में मामूली रिकवरी भी दिख रही है।

विपक्ष ने अदाणी मामले पर सरकार को घेरा

अदाणी ग्रुप पर अमेरिका में लगे आरोपों से सियासत भी गरमा गई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप लगाया कि पीएम नरेंद्र मोदी की सरकार गौतम अदाणी को बचा रही है और एक्शन लेने बच रही है।

राहुल ने कहा, 'अब यह बात अमेरिका में बिल्कुल स्पष्ट और स्थापित हो चुकी है कि मिस्टर अदाणी ने भारतीय कानून और अमेरिकी कानून दोनों को तोड़ा है। अमेरिका में उन पर अभियोग लगाया गया है। यह हमारी कही गई बातों की पुष्टि है। मैं सोच रहा हूं कि मिस्टर अदाणी इस देश में एक स्वतंत्र व्यक्ति की तरह क्यों घूम रहे हैं।'

महाराष्ट्र झारखंड चुनावी रिजल्ट पर सबकी नज़रें 23 नवंबर 2024 पर टिकी-एक्जिस्ट पोल से सभी दल सहमें

मतदाताओं की उम्मीद-अब चुने हुए प्रतिनिधि व सरकार के खरा उतरने का इंतजार शुरू

चुनाव आयोग को शहरी क्षेत्र में कम व ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक वोटिंग प्रतिशत मतदान की खाई को पाटनें ज़रूरी कदम उठाने की आवश्यकता-एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानीं गोंदिया महाराष्ट्र

वैश्विक स्तरपर पूरी दुनियाँ की नज़रें 23 नवंबर 2024 को आने वाले भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई वाले महाराष्ट्र व आदिवासी बहुल इलाके झारखंड में 20 नवंबर 2024 को हुए विधानसभा चुनाव का परिणामपर लगी हुई है जिसके एक्जिस्ट पोल का आंकलन मीडिया के हर प्लेटफार्म पर 20 नवंबर 2024 शाम 6 के बाद से शुरू होगए है। हर राजनीतिक दल व उम्मीदवार की सांसें अटकी हुई है, हालांकि हर पार्टी व उम्मीदवार अपनी जीत का दम भर रहे हैं, परंतु एक्जिस्ट पोल दोनों पक्षों में अति भारी टक्कर होने के आंकड़े दे रहे हैं, जिसमें मात्र 10 सीटों का अंतर बताया जा रहा है, जिसमें बाज़ी किधर भी पलट सकती है इसका एक कारण शहरी क्षेत्र में मतदान का कम प्रतिशत होना भी है, जैसे मुंबई पुणे व नागपुर जैसे शहरी इलाकों में 50-55 प्रतिशत मतदान होना, मतदाताओं की उदासीनता को व्यक्त करते हैं, जिससे स्वाभाविक रूप से महायुती को फर्क पड़ने की संभावना जताई जा रही है, हालांकि महायुति व महाविकास आघाडी दोनों को मिलने वाली सीटों का अंतर बहुत कम बताया जा रहा है, परंतु मेरा व्यक्तिगत रूप से आँकलन व पिछले एक माह से महाराष्ट्र वह झारखंड के चुनावों पर नज़र रख रहा हूं, तो मेरा अनुमान है महाराष्ट्र में महायुती व झारखंड में सोरेन सरकार की वापसी होने की संभावना दिखाई दे रही है, हालांकि हकीकत से पर्दा 23 नवंबर 2024 को ही उठेगा, यह मेरा निजी आकलन है।चूँकि अब मतदाताओं ने उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला मशीनों में कैद कर दिया है, जिसका पता हमें 23 नवंबर 2024 को ही पहले पड़ेगा इसलिए आज हम मीडिया में उपलब्ध जानकारी के सहयोग से इस आर्टिकल के माध्यम से चर्चा करेंगे, महाराष्ट्र झारखंड चुनावी रिजल्ट पर सबकी नज़रें 23 नवंबर 2024 पर टिकी, एक्जिस्ट पोल से सभी दल सहमें।

साथियों बात अगर हम 23 नवंबर 2024 को आने वाले चुनावी परिणामों की करें तो, महाराष्ट्र और झारखंड में उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो चुकी है। महाराष्ट्र में जहां 288 सीटों पर एक चरण में मतदान हुआ है, वहीं झारखंड में 81 सीटों पर राजनीतिक दलों की साख दांव पर लगी है, दोनों ही प्रदेशों में किसे बहुमत मिलने की संभावना है, ये भी अब अनुमानतः साफ हो चुका है, ज्यादर एग्जिट पोल में दोनों ही प्रदेशों में वर्तमान सरकार ही बनती नजर आ रहीहै।एग्जिट पोलमतदाताओं के मतदान के तुरंत बाद किए जाने वाले सर्वेक्षण होते हैं, जिनका उद्देश्य आधिकारिक परिणाम घोषित होने से पहले चुनाव के परिणाम की भविष्यवाणी करना होता है। ये पोल आम तौर पर मतदाताओं से पूछते हैं कि उन्होंने किस पार्टी या उम्मीदवार को वोट दिया और कभी-कभी उनके चुनाव के कारण भी पूछे जाते हैं।एग्जिट पोल मतदान एजेंसियों और मीडिया संगठनों द्वारा किए जाते हैं और आम तौर पर मतदान समाप्त होने के तुरंत बाद नतीजे जारी किए जाते हैं। एग्जिट पोल जनता की राय का एक सिर्फ आकलन देते हैं और चुनाव के परिणाम के बारे में शुरुआती संकेत दे सकते हैं, लेकिन वे हमेशासटीक नहीं होते हैं। महाराष्ट्र की जंग में एक तरफ महाविकास अघाड़ी गठबंधन है वहीं, उनके सामने महायुति की चुनौती है। बीजेपी के नेतृत्व वाला सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन सत्ता बरकरार रखने की कोशिश कर रहा है। एकनाथ शिंदे मौजूदा वक्त में महाराष्ट्र के सीएम हैं, वहीं विपक्षी गठबंधन की बात की जाए तो कांग्रेस के साथ शिवसेना उद्धव गुट और एनसीपी शरद गुट मैदान में हैं।अब 23 नवंबर को नतीजों की घोषणा की जाएगी जिस पर पूरी दुनियाँ की नजरें एकटक टिकी है।

साथियों बात अगर हम महाराष्ट्र में चुनाव लड़ने वाले दो गठबंधनों की करें तो, महाराष्ट्र एग्जिट पोल के नतीजे सामने आ चुके हैं. प्रदेश की 288 सीटों के लिए लाखों की तादाद में वोटर्स ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है, इस बार का असेंबली इलेक्शन मुख्य रूप से दो गठबंधन के बीच है, सत्तारूढ़ महायुति और विपक्षी महाविकस अघाड़ी के प्रत्याशियों के बीच मुख्य रूप से मुकाबला है।महायुति की अगुआई जहां बीजेपी कर रही है, वहीं विपक्षी एमवीए में कांग्रेस, एनसीपी (शरद पवार गुट) और शिवसेना (उद्धव गुट) शामिल हैं।महायुति में बीजेपी के साथ ही एनसीपी (अजित पवार गुट) औरशिवसेना (एकनथ शिंदे गुट) घटल दल हैं। ज्यादातर सर्वे एजेंसयिों ने महायुति की सत्ता में वापसी दिखाया है, जबकि कुछ ने विपक्षी एमवीए के हिस्से में ज्यादा सीटें जाने का अनुमान जताया है। पोल ऑफ पोल्स में बीजेपी की अगुआई वाली महायुति गठबंधन की सत्ता में वापसी की संभावना जताई गई है।महाराष्ट्र विधानसभा की 288 सीटों के लिए कुल 4,136 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनमें से लगभग आधे यानी 2,086 उम्मीदवार स्वतंत्र हैं। मुख्य पार्टियों में, बीजेपी 149 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जबकि शिवसेना (एकनाथ शिंदे गुट) 81 सीटों पर और अजित पवार की नवल-राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी 59 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। विपक्षी दलों में कांग्रेस 101 उम्मीदवारों को मैदान में उतारी है, शिवसेना 95 सीटों पर और शरद पवार की पार्टी 86 उम्मीदवारों के साथ चुनावी मैदान में है।छोटे दलों की भी अपनी महत्वपूर्ण उपस्थिति है। बहुजन समाज पार्टी 237 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जबकि ऑल इंडिया मजलिस-ए- इत्तेहादुल-मुसलमीन 17 सीटों पर अपनी किस्मत आजमा रही है।पीएम के लिए महाराष्ट्र में जीत एनडीए की स्थिति को मजबूत करेगी। लोकसभा में इस साल कम सीटों के बाद यह चुनाव बीजेपी के लिए अति महत्वपूर्ण है।

साथियों बात अगर हम महाराष्ट्र में शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में मतदान परसेंट में भारी अंतर होने की करें तो, शहरी क्षेत्रों में मतदाताओं की उदासीनता एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। मुंबई, नागपुर और पुणे जैसे बड़े शहरों में मतदाता कम संख्या में निकलते हैं। इसके कारण नतीजे कुछ ही मतदाताओं के हाथों में आ जाते हैं। महाराष्ट्र के चुनावों में यह सवाल बना हुआ है कि क्या मुंबई और पुणे जैसे शहरी केंद्र अपनी कम मतदान दर के इतिहास को चुनौती देंगे या वही पुराना पैटर्न फिर से दिखेगा? शहरी वोटर की उदासीनता यह मुद्दा 2019 विधानसभा चुनावों में भी देखने को मिला था। महाराष्ट्र के 64 शहरी निर्वाचन क्षेत्रों में से 62 पर राज्य के औसत से कम मतदान हुआ था। लोकसभा चुनावों में भी यह ट्रेंड बना रहा। मुंबई, जो राज्य की राजधानी और भारत की वित्तीय राजधानी है, लंबे समय से कम मतदान दर की समस्या से जूझ रही है। हालांकि, हालिया चुनावों में मुंबई में थोड़ा सुधार देखा गया है। विधानसभा चुनावों में यहां 50 प्रतिशत से अधिक मतदान हुआ है। निर्वाचन आयोग ने कहा कि पिछले विधानसभा और संसदीय चुनावों में महाराष्ट्र के शहरी क्षेत्रों में कम मतदान दर्ज किया गया था जिसके चलते शहरी क्षेत्रों में ज्यादा से ज्यादा मतदान सुनिश्चित करने के लिए मतदाताओं को जागरुक करने पर विशेष ध्यान दिया गया था। बहुमंजिला इमारतों और सोसाइटी में 1,185 से अधिक मतदान केंद्र स्थापित किए गए थे और शहरी तथा युवा मतदाताओं को जागरूक करने के लिए चुनाव से पहले चलाये गए अभियानों में फिल्मी हस्तियों को भी शामिल किया गया।

साथियों बढ़कर हम चुनाव आयोग द्वारा अति जनजागरण अभियान के बावजूद कम मतदान की करें तो मतदान बुधवार को संपन्न हो गया। शाम पांच बजे तक महाराष्ट्र में 58.22 प्रतिशत और झारखंड में 67.59 प्रतिशत मतदान हुआ। वहीं, झारखंड में 2019 में इन विधानसभा सीट पर 67.04 प्रतिशत मतदान हुआ था।

अतः अगर हम उपरोक्त पूरे विवरण का अध्ययन कर इसका विश्लेषण करें तो हम पाएंगे कि महाराष्ट्र झारखंड चुनावी रिजल्ट पर सबकी नज़रें 23 नवंबर 2024 पर टिकी- एक्जिस्ट पोल से सभी दल सहमें।मतदाताओं की उम्मीद-अब चुने हुए प्रतिनिधि व सरकार के खरा उतरने का इंतजार शुरू।चुनाव आयोग को शहरी क्षेत्र में कम व ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक वोटिंग प्रतिशत मतदान की खाई को पाटनें ज़रूरी कदम उठाने की आवश्यकता है।

युवा भारतीय महिलाओं की उभरती आकांक्षाएँ : पारंपरिक सामाजिक संरचनाओं और मानदंडों को चुनौती देती महिलाएं

उच्चशिक्षा और कौशल विकास में लड़कियों की अब लड़कों के बराबर शैक्षिक उपलब्धि है, जिसमें 50% से अधिक युवा महिलाएँ कक्षा 12 पूरी कर रही हैं और 26% कॉलेज की डिग्री प्राप्त कर रही हैं। युवा महिलाएँ विभिन्न कैरियर पथों और डिजिटल कौशल प्लेटफ़ॉर्म तक पहुँच से प्रभावित होकर पेशेवर महत्त्वाकांक्षाओं को तेज़ी से प्राथमिकता दे रही हैं।स्किल इंडिया मिशन और स्टेम फ़ॉर गर्ल्स इंडिया जैसे कार्यक्रमों ने तकनीकी क्षेत्रों में युवा महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा दिया है।

-प्रियंका सौरभ

पिछले एक दशक में युवा भारतीय महिलाओं की आकांक्षाओं में एक परिवर्तनकारी बदलाव देखा गया है, जो उनकी बढ़ती स्वायत्तता, शिक्षा और कार्यबल में भागीदारी को दर्शाता है। यह विकास भारत के सामाजिक परिदृश्य को महत्त्वपूर्ण रूप से पुनर्परिभाषित कर रहा है।

उच्च शिक्षा और कौशल विकास में लड़कियों की अब लड़कों के बराबर शैक्षिक उपलब्धि है, जिसमें 50% से अधिक युवा महिलाएँ कक्षा 12 पूरी कर रही हैं और 26% कॉलेज की डिग्री प्राप्त कर रही हैं। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण (2017-18) उच्चशिक्षा में महिलाओं के बढ़ते नामांकन पर प्रकाश डालता है, जिसमें महिला सकल नामांकन अनुपात 27.3% तक पहुँच गया है। युवा महिलाएँ विभिन्न कैरियर पथों और डिजिटल कौशल प्लेटफ़ॉर्म तक पहुँच से प्रभावित होकर पेशेवर महत्त्वाकांक्षाओं को तेज़ी से प्राथमिकता दे रही हैं। स्किल इंडिया मिशन और स्टेम फ़ॉर गर्ल्स इंडिया जैसे कार्यक्रमों ने तकनीकी क्षेत्रों में युवा महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा दिया है।

विवाह की औसत आयु 2005 में 18.3 वर्ष से बढ़कर 2021 में 22 वर्षहो गई है, जिसमें अधिक युवा महिलाएँ अनुकूलता के आधार पर साथी चुनती हैं।एक रिपोर्ट के अनुसार 52% महिलाओं ने साथी चयन में अपनी बात रखी, जो 2012 में 42% थी। कई युवा महिलाएँ आर्थिक स्वतंत्रता के लिए प्रयास कर रही हैं, विशेष रूप से उद्यमिता के माध्यम से, क्योंकि सरकार महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्टअप के लिए समर्थन दे रही है। उदाहरण के लिए: नीति आयोग द्वारा महिला उद्यमिता मंच ने 10,000 से अधिक महिला उद्यमियों के नेटवर्क को बढ़ावा दिया है। युवा महिलाएँ स्वयं सहायता समूहों और स्थानीय शासन में बढ़ती भागीदारी के साथ राजनीतिक रूप से अधिक सक्रिय हैं। ग्रामीण महिलाओं के बीच स्वयं सहायता समूह सदस्यता 2012 में 10% से बढ़कर 2022 में 18% हो गई। ये आकांक्षाएँ पारंपरिक सामाजिक संरचनाओं और मानदंडों को चुनौती दे रही हैं। जैसे-जैसे अधिक महिलाएँ करियर बना रही हैं, घरों में पारंपरिक लैंगिक अपेक्षाएँ बदल रही हैं।मनरेगा पुरुषों और महिलाओं के लिए समान वेतन प्रदान करता है, जो ग्रामीण घरेलू गतिशीलता को प्रभावित करता है। अधिक शिक्षा और आय के साथ, युवा महिलाओं का अब परिवार के वित्तीय और सामाजिक निर्णयों में अधिक प्रभाव है। स्वयं सहायता समूहों ने ग्रामीण महिलाओं को सामूहिक रूप से घरेलू वित्त का प्रबंधन करने के लिए सशक्त बनाया है। बाद में विवाह करने और साथी चुनने में सक्रिय भागीदारी की ओर बदलाव ने अरेंज मैरिज की पारंपरिक संरचना को चुनौती दी है। बाल विवाह में कमी और बाद में विवाह करने को प्राथमिकता देने की रिपोर्ट करता है। बढ़ती स्वतंत्रता ने सामाजिक प्रतिबंधों को चुनौती देते हुए शिक्षा या काम के लिए महिलाओं की अकेले यात्रा को सामान्य बना दिया है। 2012 में 42% की तुलना में अब 54% महिलाएँ बस या ट्रेन से अकेले यात्रा करने में सहज महसूस करती हैं। युवा महिलाएँ पेशेवर सेटिंग्स में लैंगिक समानता के बारे में तेज़ी से मुखर हो रही हैं, कानूनी और सामाजिक सुधारों को बढ़ावा दे रही हैं। पोष अधिनियम (कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम), 2013 ने महिलाओं को कार्यस्थल के मुद्दों को प्रभावी ढंग से सम्बोधित करने के लिए सशक्त बनाया है। स्वयं सहायता समूह और ग्राम सभाओं में युवा महिलाएँ शासन में महिलाओं की भूमिका पर पारंपरिक विचारों को चुनौती दे रही हैं।केरल कुदुम्बश्री मिशन महिला-नेतृत्व वाले शासन को बढ़ावा देता है, जिसने राज्यों में इसी तरह के मॉडल को प्रेरित किया है।

भारतीय महिलाएँ ऊर्जा से लबरेज, दूरदर्शिता, जीवन्त उत्साह और प्रतिबद्धता के साथ सभी चुनौतियों का सामना करने में सक्षम हैं। भारत के प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता रवींद्रनाथ टैगोर के शब्दों में, हमारे लिए महिलाएँ न केवल घर की रोशनी हैं, बल्कि इस रौशनी की लौ भी हैं। अनादि काल से ही महिलाएँ मानवता की प्रेरणा का स्रोत रही हैं। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई से लेकर भारत की पहली महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले तक, महिलाओं ने बड़े पैमाने पर समाज में बदलाव के बडे.उदाहरण स्थापित किए हैं।

2030 तक पृथ्वी को मानवता के लिए स्वर्गसमान जगह बनाने के लिए भारत सतत विकास लक्ष्यों की ओर तेजी से बढ़ चला है। लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण करना सतत विकास लक्ष्यों में एक प्रमुखता है। वर्तमान में प्रबंधन, पर्यावरण संरक्षण, समावेशी आर्थिक और सामाजिक विकास जैसे महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए विशेष ध्यान दिया गया है।

महिलाओं में जन्मजात नेतृत्व गुण समाज के लिए संपत्ति हैं। प्रसिद्ध अमेरिकी धार्मिक नेता ब्रिघम यंग ने ठीक ही कहा है कि जब आप एक आदमी को शिक्षित करते हैं, तो आप एक आदमी को शिक्षित करते हैं।जब आप एक महिला को शिक्षित करते हैं तो आप एक पीढ़ी को शिक्षित करते हैं।

स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) के माध्यम से महिलाएँ न केवल ख़ुद को सशक्त बना रही हैं बल्कि हमारी अर्थव्यवस्था की मजबुती में को भी योगदान दे रही है।सरकार के निरन्तर लगातार आर्थिक सहयोग से आत्मनिर्भर भारत के संकल्प में उनकी भागीदारी दिन-ब-दिन बढ़ती जा रही है। पिछले 6-7 वर्षों में महिला स्वयं सहायता समूहों का अभियान और तेज हुआ है। आज देश भर में 70 लाख स्वयं सहायता समूह हैं। महिलाओं के पराक्रम को समझने की ज़रूरत है, जो हमें महिमा की अधिक ऊंचाइयों तक पहुँचाएगी। आइए हम उन्हें आगे बढ़ने और फलने-फूलने में मदद करें। महिलाओं के सर्वांगीण सशक्तिकरण के लिए 'अमृत काल' इन्हें समर्पित हो।

युवा भारतीय महिलाओं की उभरती आकांक्षाएँ भारत के सामाजिक ताने-बाने को उत्तरोत्तर रूप से परिभाषित कर रही हैं, एक ऐसे समाज को बढ़ावा दे रही हैं जहाँ लैंगिक समानता और महिलाओं की एजेंसी आदर्श बन गई है। सहायक नीतियों को सुनिश्चित करने से इस बदलाव में तेज़ी आ सकती है, जिससे समावेशी और सशक्त भविष्य का मार्ग प्रशस्त हो सकता है।

ओड़िया को रोजगार का भाषा बनाकर विछिन्न उत्कल में विकास की रणनीति

योग्य सलाहकार होंगे, कानून बनेगा : मनमोहन सामल

कार्तिक कुमार परिच्छा, स्टेट हेड

सिंहभूम , ओड़िया भाषा को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से उसे हितकारी व आर्थिक रूप से लाभकारी भाषा बनाया जायेगा।इसके लिए ओडिशा सरकार जल्द ही योग्य लोगों की दिशा में नई योजना तैयार करे तो ओडिशा नंबर एक राज्य बन सकता है, ऐसा विचार कल शाम भाजपा प्रदेश कार्यालय के बौद्धिक सम्मेलन में व्यक्त किया गया। अब सरायकेला खरसावां सिंहभूम समेत बंगाल, छत्तीसगढ़, आंध्रप्रदेश में ओडिशा से अलग थलग पड़े इलाकों के में ओडिया भाषा का विकास किया जायेगा। इस बैठक में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए ओड़िआ के बीजेपी अध्यक्ष मनमोहन सामल ने कहा कि सरकार एक उच्चस्तरीय समिति बनाएगी और उड़िया भाषा और साहित्य के सुधार के लिए कदम उठाएगी।

इस समिति में योग्य सलाहकार लिये जायेंगे। भाजपा बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ के नेता सुदर्शन नायक ने भाषा आयोग की कार्यप्रणाली पर समन्वय एवं बल दिया।

भाषा पर राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त केंद्रीय साहित्य अकादमी के सदस्य पद्मश्री पंडित डॉ. अंतर्यामी मिश्र विशेष वक्ता के रूप में शामिल हुए और उन्होंने इस संस्कारित भाषा की सुरक्षा और समृद्धि के लिए निम्नलिखित कुछ प्रस्ताव रखे। ओड़िया भाषा के विकास के लिए चार पहलुओं से योजना बनाई जानी चाहिए। भाषा तात्विक, जनसांख्यकीय, कानकुन एवं प्रतिष्ठात्मक होनी चाहिए।

मिश्र ने कहा कि प्राथमिक शिक्षा स्तर पर सामान्य भाषा शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा स्तर पर उन्नत भाषा शिक्षा, स्नातक शिक्षा स्तर पर उच्च भाषा शिक्षा और स्नातकोत्तर शिक्षा स्तर पर ओजस्विनी भाषा शिक्षा के साथ साथ भाषा शिक्षा लाभकारी एवं आर्थिक लाभकारी बनाई जायेगी।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति में परिवर्तन कर शिक्षकों को भाषा विज्ञान के व्यावहारिक पहलुओं में प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। कुछ बुद्धिजीवियों की राय है कि कुछ जिलों और उप-जिलों के नामों में भी संशोधन करना जरूरी होगा।

सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के पूर्व अतिरिक्त निदेशक और थिंकर्स क्लब के अध्यक्ष बरदा दास ने अतिथि का परिचय कराया जहां प्रोफेसर पूर्ण चंद्र मल्लिक ने धन्यवाद ज्ञापन किया।

अंत में अतिथियों ने मिरिश भारती पत्रिका का विमोचन किया। चर्चा में कई बुद्धिजीवियों ने भाग लिया

तामिलनाडु पान ब्रोकर और ज्वेलर्स एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष स्वामी तेजानन्द की धार्मिक यात्रा संपन्न

चेन्नई-हरिद्वार। तामिलनाडु पान ब्रोकर और ज्वेलर्स एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष स्वामी तेजानन्द ने अपनी धार्मिक यात्रा के तहत हरिद्वार के सोऽहम आश्रम में 22 अक्टूबर 2024 से 22 नवंबर 2024 तक रहने के बाद अपनी यात्रा पूरी की। स्वामी तेजानन्द 22 नवंबर 2024 को सुबह 10:35 बजे नई दिल्ली से चेन्नई के मीनंबक्कम हवाई अड्डे पर पहुंचेंगे। उनके साथ सोऽहम आश्रम हरिद्वार के परम पूज्य स्वामी कल्याणस्वरुजी महाराज भी उपस्थित रहेंगे। इस अवसर पर तामिलनाडु पान ब्रोकर और ज्वेलर्स एसोसिएशन के सदस्यों ने स्वामी तेजानन्द के आगमन की तैयारी की है और उनका स्वागत करने के लिए उत्सुक हैं। स्वामी तेजानन्द की धार्मिक यात्रा के दौरान उन्होंने हरिद्वार में विभिन्न धार्मिक स्थलों का दर्शन किया और सोऽहम आश्रम में ध्यान और योग का अभ्यास किया।

कानपुर में ईवीएम स्थल का कैमरा बंद होने से फिर भड़के सपाई, अखिलेश को बताया

- सपा ने लगाया मतगणना में बेईमानी से जीतने की कोशिश का आरोप

सुनील बाजपेई

कानपुर। सीसामऊ के उपचुनाव में कई जगह बवाल के आरोपी सपाई आज गुरुवार को फिर भड़क उठे। वजह बनी उस महत्वपूर्ण स्थान का सीसीटीवी कैमरे बंद होना, जहां गल्ला मंडी में मतगणना के लिए ईवीएम रखी गई हैं। इसको लेकर समाजवादी पार्टी लोगों ने जमकर हो हल्ला भी किया। इसकी सूचना समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव तक भी पहुंचा दी गई है।

वहीं सीसीटीवीबंद होने को प्रशासन में इंटरनेट सर्वर से जुड़ी टेक्निकल खामी बताया। यद्यपि बाद में सीसी टीवी कैमरा चालू भी हो गया ,फिर भी समाजवादी पार्टी के लोग इसे भारतीय जनता पार्टी की मतगणना में बेईमानी से जीतने की साजिश बता रहे हैं।

शायद यही वजह है कि समाजवादी पार्टी के लोग मतगणना स्थल गल्ला मंडी पर डेरा भी डाले हुए हैं। यहां 23 नवंबर को मत गणना की जानी है।जिसके लिए प्रशासन ने सारी तैयारियों को अंतिम रूप भी दे दिया है।

जानकारी के मुताबिक सीसामऊ उपचुनाव के बाद गुरुवार सुबह भी माहौल गरमा गया। गल्लामंडी जहां पर ईवीएम जमा की गई है, वहां का सीसीटीवी बंद हो गया। इसके बाद सपाइयों ने जिलाधिकारी से लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव तक से बात की और हंगामा किया।

शिकायत और हंगामे के करीब डेढ़ घंटे बाद सीसीटीवी शुरू हो पाया। उधर, सपा मीडिया सेल ने बंद सीसीटीवी का वीडियो शेयर किया। इस पर लिखा कि पुलिस की दम पर वोटर्स को नहीं रोक पाए तो अब सीसीटीवी बंद कर दिया है। भाजपा अब ईवीएम के जरिए चुनाव आयोग से मिलकर खेल खेलना चाहती है।

अवगत कराते चलें कि कल सीसामऊ उप चुनाव के लिए मतदान के बाद गल्लामंडी मतगणना स्थल पर ईवीएम को कड़ी सुरक्षा में सील करके रख दिया गया है। किसी तरह की कोई गड़बड़ी न हो सके, इसके लिए गल्लामंडी में फोर्स के साथ ही सीसीटीवी भी लगाए गए हैं। उसका सीधा प्रसारण भी वहां मौजूद कार्यकर्ताओं के सामने टीवी लगाकर स्क्रीन पर किया जाता है। जिससे कि कोई सवाल नहीं उठा सके।

फिलहाल ईवीएम जमा होने के बाद कल बुधवार रात से ही सपाई गल्लामंडी में डेरा डाले हुए हैं।

जानकारी देते हुए सपाइयों ने बताया कि गुरुवार सुबह 8 बजे 8 से सीसीटीवी कैमरा बंद हो गया। इसके बाद वहां मौजूद सपा नेता अर्पित यादव समेत अन्य कार्यकर्ताओं ने मामले की जानकारी एडीएम और डीएम को दी लेकिन जब इसके बाद भी सीसीटीवी नहीं चला तो सपा प्रत्याशी नसीम सोलंकी, सपा विधायक अमिताभ बाजपेई के साथ ही सपा प्रमुख अखिलेश यादव को भी जानकारी दी गई।

बीजेडी सरकार में वापसी अवास्तविक: बिजेड़ी बिधायक बद्री पात्र

मनोरंजन सासमल, स्टेट हेड ओड़िशा

भूबनेश्वर : बीजू जनता दल को हराकर भारतीय जनता पार्टी पहली बार राज्य सरकार की कुर्सी पर बैठी है। इन सबके बीच मोहन सरकार को सत्ता में आए 5 महीने हो गए हैं। दूसरी ओर, पहली बार विपक्ष की सीट पर बैठी बिजेड़ी को अपनी हार का कारण नहीं मिल पा रहा है। इनमें एक के बाद एक बिजेड़ी नेता नवीन पटनायक को दोबारा मुख्यमंत्री बनाना चर्चा का विषय बना हुआ है।बद्री ने कहा कि 5 साल पहले बिजेड़ी सरकार में वापसी अवास्तविक है। बिजेड़ी नेता जो ऐसी बातें कह रहे हैं, उसका कोई औचित्य नहीं है। बिजेड़ी के लिए कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाना अवास्तविक है। वे नहीं जानते कि क्या वे ऐसी बेतुकी बात कहने के लिए अधिकृत हैं। मुझे नहीं पता कि नवीन बाबू ने उनसे यह कहने को कहा था या नहीं। हम कभी भी कांग्रेस के साथ उतनी दूरी पर नहीं थे, जितनी भाजपा के साथ। बद्री पात्र ने कहा कि जो लोग कहते हैं कि राय को गुमराह किया गया है उनकी अधिक निंदा हो रही है। जानकारी के मुताबिक, कबी सूर्यनगर कालीमेघी गांव के पास एक सभा में लतिका ने कहा, नवीन पटनायक जल्द ही छठी बार मुख्यमंत्री बनेंगे। लतिका ने बीजेडी कार्यकर्ताओं से एकजुट होने और नवीन को फिर से मुख्यमंत्री बनाने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा, आने वाले दिनों में फिर लड़ाई होगी। नवीन पटनायक को एक बार फिर मुख्यमंत्री बनाएं। यह समय दूर नहीं है। कुछ ही समय में नवीन पटनायक फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे। जो अवसर आपने स्वयं को दिया है वह बार-बार वापस आएगा। ओडिशा के लोग एक बार फिर मुस्कुराएंगे।

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक एवं संपादक संजय कुमार बाटला द्वारा इम्प्रेशंस प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग लिमिटेड, सी-18,19,20 सेक्टर 59, नोएडा (उत्तर प्रदेश) से मुद्रित एवं 3, प्रियदर्शनी अपार्टमेंट ए-4, पश्चिमी विहार, नई दिल्ली- 110063 से प्रकाशित। सम्पर्क : 9212122095, 9811902095. newstransportvishesh@gmail.com
(इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी) किसी भी कानूनी विवाद की स्थिति में निपटारा दिल्ली के न्यायालय के अधीन होंगे। RNI No :- DELHIN/2023/86499. DCP Licensing Number F.2 (P-2) Press/2023